खण्ड-07 सत्र-04 (भाग-3) / अंक-47

शुक्रवार 18 अगस्त, 2023 / 27 श्रावण, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-04 में अंक 45 से अंक 47 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 (भाग-3) शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023/27 श्रावण, 1945 (शक) अंक-47

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	4-36
3.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात	37-38
4.	समिति के प्रतिवेदन से सहमति	41
5.	सदन में अव्यवस्था	42-58
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	59-97
7.	धन्यवाद प्रस्ताव	98-107
8.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	108-162

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 (भाग-3) शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023/27 श्रावण, 1945 (शक) अंक-47

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.15 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
2. श्रीमती ए. धनवंती चंदील ए.
3. श्री अजय दत्त
4. श्री अमानतुल्ला खान
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्री बी एस जून
7. श्री धर्मपाल लाकड़ा
8. श्री दिनेश मोहनिया
9. श्री दुर्गेश कुमार
10. श्री गुलाब सिंह
11. श्री हाजी युनूस
12. श्री जय भगवान
13. श्री जरनैल सिंह
14. श्री करतार सिंह तंवर
15. श्री कुलदीप कुमार
16. श्री मुकेश अहलावत
17. श्री नरेश यादव
18. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
19. श्री प्रवीण कुमार
20. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस

21. श्री प्रकाश जारवाल
22. श्री राजेश गुप्ता
23. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री शरद कुमार चौहान
26. श्री संजीव झा
27. श्री सोमदत्त
28. श्री शिवचरण गोयल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्री सही राम
31. श्री विनय मिश्रा
32. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
33. श्री अभय वर्मा
34. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
35. श्री अजय कुमार महावर
36. श्री जितेंद्र महाजन
37. श्री महेंद्र गोयल
38. श्री महेन्द्र यादव
39. श्री मदन लाल
40. श्री मोहन सिंह बिष्ट
41. श्री ओमप्रकाश शर्मा
42. श्री पवन शर्मा
43. श्री प्रलाद सिंह साहनी
44. श्री ऋतुराज गोविंद
45. श्री रघुविंदर शौकीन
46. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
47. श्री शोएब इकबाल
48. श्री एस. के. बग्गा
49. श्री सुरेंद्र कुमार
50. श्री विजेंद्र गुप्ता
51. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 (भाग-3) शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023/27 श्रावण, 1945 (शक) अंक-47

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.15 बजे समवेत हुआ ।

माननीया उपाध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं ।

माननीया अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सदन को अति हर्ष के साथ बताना चाहती हूं कि दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री अजय दत्त जी, 'विश्व शांति और मानवाधिकार' के साथ-साथ यूनाइटेड नेशन की कई अन्य संस्थाओं से 'विश्व शांति दूत' के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हाल ही में श्री अजय दत्त जी को कंबोडिया के नेशनल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान कंबोडिया इलेक्शन का 'इलेक्शन आब्जर्वर' के रूप में आमंत्रित किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार श्री अजय दत्त जी भारत के पहले विधायक है जो विदेश में चुनाव आब्जर्वर के लिए बतौर 'इलेक्शन आब्जर्वर' गए हों। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि दिल्ली विधानसभा से हमारे साथी श्री अजय दत्त जी को किसी दूसरे देश

का चुनाव ऑब्जर्व करने का मौका मिला। मैं दिल्ली विधानसभा की ओर से और सभी साथियों की ओर से श्री अजय दत्त जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूं, धन्यवाद।

नियम-280 के तहत गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय और अजय दत्त भाई को बहुत-बहुत बधाई अब हमारे पास देश में दो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए एक मोदी जी और दूसरे अजय दत्त जी।..

माननीया अध्यक्षाः विषय पर आएं गुलाब जी, बहुत सारे वक्ता हैं, नियम-280 के तहत, गुलाब जी। नियम-280 के तहत बहुत सारे वक्ता हैं, सभी सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अपने विषय को शॉर्ट में रखें, शुरू करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री गुलाब सिंहः माननीय अध्यक्षा महोदय जी, मैं जो इशू आज रखने जा रहा हूं, ये बुढ़ापा पेंशन से संबंधित है और सभी विधायकों की पीड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इससे पहले पेंशन नहीं दी। लास्ट टाइम एक लाख लोगों को पेंशन दी गई, हर विधायक को वोटर के अनुपात के हिसाब से उस समय सबको पेंशन दी गई थी। लेकिन कई वर्ष के बाद लगातार सभी विधायकों के कार्यालय में भी बुजुर्ग आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से आठ-दस हजार बुजुर्गों के नम्बर नोट कर रखे हैं हमने कि जी अब जैसे ही

पेंशन शुरू होगी, हम देंगे। लेकिन कई वर्षों से पेंशन अभी शुरू नहीं हो पा रही, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अगर जितना जल्दी हो सके, बुढ़ापा पेंशन को अगर दुबारा से शुरू किया जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी और सभी विधायक भी मानते होंगे इस बात को कि इस चीज की बड़ी जरूरत है। सब मानते हैं ना, सारे मानते हो, बनना चाहिए, तो प्लीज..

माननीया अध्यक्षाः कम्पलीट कीजिए।

श्री गुलाब सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया जी, प्लीज बस इतना सा रिक्वैस्ट है, धन्यवाद जी।

माननीया अध्यक्षाः धन्यवाद, करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे 280 के तहत अपनी विधान सभा से जुड़े मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्षा जी, मैं आपका ध्यान ऐसे दो प्रोजैक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह प्रोजैक्ट तैयार करके, जिनपर काम भी, एक पर तो काम भी शुरू हुआ, कुछ रूकावट आईं लेकिन अभी दोनों प्रोजैक्ट रूके हुए हैं और दोनों ही बहुत बड़े प्रोजैक्ट हैं। एक प्रोजैक्ट है, मांड़ी रोड़ पर स्थित जौनापुर गांव में स्कील सैंटर जो हमारी सरकार ने आने के बाद स्कील सैंटर को स्कील यूनिवर्सिटी बनाया। उसका निर्माण का कार्य रूकना। अध्यक्षा

जी जब 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो पहले से एक प्रस्ताव था कि जौनापुर में स्कील सैंटर का निर्माण हो। 2012 में उसके लिए 37 एकड़ जमीन जौनापुर गांव में अलॉट भी हुईं वो काफी धीमी गति से प्रोजैक्ट था, रूका हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद उस प्रोजैक्ट को बहुत जल्दी कलियरैंस मिली और मनीष सिसोदिया जी ने, अरविन्द केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी उसके लिए 175 करोड़ रुपए का बजट सैंग्शन कराया और बिल्डिंग का निर्माण भी उसका शुरू हो गया और बिल्डिंग का जब निर्माण शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली में दो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई, एक स्कील यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी। लेकिन अध्यक्षा जी, काम शुरू होने के बाद वन विभाग और एनजीटी की तरफ से एक ओब्जैक्शन आने के बाद उस काम को रोक दिया गया। आपत्ति यह थी कि यह जमीन फॉरैस्ट विभाग के अंतर्गत आती है। 2012 में जब यह अलॉटमेंट हुआ उस टाइम एक प्रशासनिक चूक हुई, ये विषय मैं पहले भी यहां उठा चुका हूं कि जो ये 37 एकड़ जमीन थी, वो एक तरफ तो फॉरैस्ट में चली गई और दूसरी तरफ स्कील सैंटर को भी अलॉट कर दी गईं काम रूकने के बाद सरकार ने फिर इस पर तत्परता से काम किया। मैं मनीष जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला और इस 37 एकड़ जमीन के बदले जो वो फॉरैस्ट विभाग का एक सुझाव था कि इतनी जमीन आप दिल्ली में और कहीं दे दीजिए, वहां पर हम फॉरैस्ट लगा देंगे। गांव ईशापुर और गालिबपुर

में 37 एकड़ की जगह 42 एकड़ जमीन अलॉट करके ये प्रस्ताव रिज मैनेजमेंट बोर्ड को भेज दिया गया, जिसके चेयरमेन चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वहां से प्रोजैक्ट क्लीयर करके, वहां से प्रोजैक्ट बहुत जल्दी क्लीयर हुआ कि ये बहुत बड़ा काम है यूनिवर्सिटी बननी है, काम शुरू हो चुका था और इसको उसके बाद सीईसी, सैंट्रल एम्पावर कमेटी को भेज दिया मार्च, 2021 में जो कि सैंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक ढ़ाई वर्ष होने के बाद भी ये प्रोजैक्ट वहां पर रूका हुआ है, इसको क्लीयरैंस नहीं मिली है। तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजैक्ट को वहां से क्लीयरैंस दिलाई जाए जिससे कि 5 हजार बच्चे इस यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़ने हैं, ये काम हो सके। दूसरा जहां पर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, मांडी रोड़ उसके चौड़ीकरण का विषय है। वो प्रोजैक्ट भी दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह क्लीयर करके, फरवरी,2021 में डीडीए को भेज दिया गया है, साढ़े 43 एकड़ जमीन उस पर एक्वायर होनी है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सारा काम सत्येन्द्र जैन जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी देख–रेख में पूरा कराया, सारे नक्शे वगैरा उसके फाइनल किए, पूरा ले–आउट फाइनल किया और वो प्रोजैक्ट भी ढ़ाई वर्ष से डीडीए के पास पेंडिंग है। जमीन एक्वायर हो तो उसपर दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी रोड़ बनाए। तो मेरी आपसी विनती है कि दोनों प्रोजैक्ट जो दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरह से क्लीयर हैं, छतरपुर विधान सभा के लिए बहुत महत्व के काम हैं।

एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और दूसरा, जो रोड़ का काम है क्योंकि ये रोड मांडी रोड ये हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद रोड को जोड़ता है जहां से बहुत ट्रैफिक दिल्ली में आता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक ज्वाइंट मीटिंग में चंडीगढ़ में इसको अनाउंस कर चुके हैं कि ये जो हमारे 5 प्रोजैक्ट होने थे उनका एक भाग है। तो मेरी आपसे विनती है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी चोड़ा कराया जाए, डीडीए से जमीन जो एक्वायर कराई जाए 43 एकड़ इसके लिए और स्कील यूनिवर्सिटी के निर्माण को सैंट्रल एम्पावर कमेटी से जल्दी से जल्दी क्लीयर कराकर ये दोनों काम शुरू किए जाएं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षाः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और सदन का ध्यान दिल्ली में जो गवर्नमेंट एडिड स्कूलस हैं, इन स्कूलस के बारे में और यहां पर जो एडमिशन प्रोसैस है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैडम दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं वहां का जो एडमिशन प्रोसैस है वो ऑनलाइन है, अभी कुछ समय पहले वो हुआ है और इस प्रोसैस के होने के बाद जो है बहुत सारी समस्याओं का हल निकल गया है, बच्चों को बहुत आसानी से दाखिला मिल जाता है। बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो उनका क्लस्टर बनता है, उनके हिसाब से उनको दाखिला मिल जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एडिड

स्कूल हैं, वहां पर जो दाखिले का प्रोसैस है वो बिल्कुल भी ट्रांस्पेरेंट नहीं है आज। आज किसी भी गवर्नमेंट एडिड स्कूल में आप दाखिला बच्चा कराने जाता है, तो वहां उसको दाखिला मिलता नहीं है। बहुत सारे स्कूल तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ स्कूल और उनकी मैनेजमेंट हर दाखिले के लिए मोटा-मोटा डोनेशन मांगते हैं और जो पेरेंट डोनेशन देते हैं उनको दाखिला मिल जाता है और जो डोनेशन नहीं देते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम्हारा ड्रॉ में नाम नहीं आया। ड्रॉ में नाम आने के बाद भी बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम्हें डोनेशन देनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार इन स्कूल्स को 95 परसैंट टीचर्स सैलरी में सहयोग करती है, सैनेटेशन स्टाफ दिल्ली सरकार देती है, सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली सरकार देती है, मिड-डे-मिल वहां दिल्ली सरकार का जाता है। वहां बच्चों को स्टेशनरी यूनिफार्म का अमाउंट उनके अकाउंट में दिल्ली गवर्नमेंट डालती है। लेकिन एडमिशन प्रोसैस जो है वो गवर्नमेंट एडिड स्कूल ने अपने हाथ में ले रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारे क्षेत्र में लगभग 12-13 गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं, ज्यादातर स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां वो मनमानी करते हैं, वो बहुत मोटा-मोटा पैसा बच्चों से लेते हैं, उनके पेरेंटस से लेते हैं और पेरेंटस परेशान रहते हैं। तो मेरा सदन के माध्यम से, आपसे और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि इन सभी स्कूलों के अंदर भी, दिल्ली के अंदर इनका भी एडमिशन प्रोसैस जो है ओनलाइन कर दिया जाए, ताकि ये ट्रॉस्परेंट

रहे और जो डोनेशन और अनाप-शनाप पैसे जो मांगे जाते हैं उसपर रोकथाम लग सके। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल भी, गवर्नमेंट एडिड कुछ स्कूल हैं, कुछ स्कूलस एमसीडी के पास भी हैं, जहां वो जो गवर्नमेंट एडिड व्यवस्था में चल रहे हैं, जहां मैनेजमेंट चला रही है, वहां भी सेम तरह की शिकायत है। तो अगर यहां प्रभारी साहब उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एमसीडी के भी जो गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं उनको भी ओनलाइन प्रोसैस में ला दिया जाए ताकि इससे ट्रांसपरेंसी आएगी और बच्चों को सुविधा मिलेगी, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षा: सही राम जी।

श्री सही राम: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया मैं 280 के माध्यम से वैसे तो अपनी विधान सभा की बात रख रहा हूं, लेकिन जो मेरी बात है वो खाली मेरी विधान सभा तक सीमित नहीं है, मैं समझता हूं कि शायद वो पूरी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि पिछले 15-20 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आपने एक कहावत सुनी ही होगी, कि हमारे देहात में कहते हैं धींगड़ा मारता भी है और रोने भी नहीं देता। ये हाल पिछले 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार ने किया। जैसे कि जब कोई प्रोपर्टी ऑनर अपनी प्रोपर्टी बनाता है और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो निगम की सरकार गई वो भ्रष्टाचार के नाम पर ही गई है। इनके बड़े-बड़े जो नेता हैं उन्होंने मन से भी कहा था कि निगम में जो

भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैठे हैं ये करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं तभी दिल्ली की जनता ने सत्ता बदल दी। जब कोई भी आदमी दिल्ली में अपना अनोथराइज्ड कॉलोनी में या गांव में अपना मकान बनाता है, अपनी प्रोपर्टी बनाता है, तो पिछली निगम की सरकार में लोगों ने पैसे खूब जबरदस्त कमाए। लेकिन जो अधिकारी रहे उनकी कोई कम्पलेंट ना हो, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रोपर्टी को बुक कर देते थे कि कल को कोई कम्पलेंट होगी तुम्हारे खिलाफ तो तुम तो कह दोगे कि जी ये तो हमने बुक कर रखी है। अध्यक्ष महोदया, प्रोपर्टी मकान बनकर तैयार हो गया, फ्लैट बनकर तैयार हो गया। लेकिन प्रोपर्टी मालिक को या फ्लैट मालिक को यही नहीं पता की तुम्हारी प्रोपर्टी एमसीडी में बुक है। उसे कब पता चलता है या तो फलैट खरीदने वाला या मकान मालिक जिसने अपने रहने के लिए मकान बनाया है। जब वो ऑनलाइन बिजली कम्पनी में अप्लाई करने जाता है, तो वहां से उसे पता चलता है भई तुम्हारी प्रोपर्टी तो एमसीडी में बुक है। अध्यक्ष महोदय उसे कहा जाता है कि आप निगम में जाओ और इसकी एनओसी लेकर आओ तो हम आपका मीटर लगा देंगे। अध्यक्ष महोदय यहां काफी पुराने काउंसलर भी बैठे हैं आज इस विधान सभा में। सबको पता है कि जिसकी प्रोपर्टी एक बार बुक हो गई, उसकी एनओसी एमसीडी देती ही नहीं है क्योंकि वो खुद फंसेंगे, क्योंकि वो करप्ट रहे हैं। इसकी वजह से मैं आज अपनी विधान सभा की बात तो कर रहा हूं, पूरी दिल्ली में लाखों लोग आज भी परेशान घूम रहे हैं, धक्के खा

रहे हैं। अब भ्रष्टाचार किया किसी ने, माल खाया किसी ने और धक्के खा रहा है एक गरीब आदमी, प्रोपर्टी ऑनर। आज मेरा आपसे निवेदन है, आज सर दिल्ली में हमारी सरकार है, निगम में हमारी सरकार है, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा आपसे भी और अपनी मेयर से भी, हाउस के माध्यम से कि सरकार इसमें कुछ संशोधन करे और संशोधन करके एक ऐसा प्लान लाए कि जिससे कोई ऐसा चार्ज लगाए उनपर, न्यूनतम चार्ज लगाए। कि भई इतने गज के प्लाट पर इतने पैसे निगम को देंगे इतने गज के प्लाट पर इतना पैसा निगम को मिलेगा और उनको, वो जो बिजली कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पर जो बुकिंग है एक तो निगम की आय हो जाएगी निगम को चार्ज मिलेगा, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्योंकि वो किसी न किसी रास्ते से जाकर अगर उसने मकान बनाया है तो बिजली तो उसे लेनी पड़ेगी बगैर बिजली के रह नहीं सकता तो वो फिर दूसरे रास्ते अपनाता है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बहुत गंभीर है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन करके और एमसीडी को ये आदेश दिये जाएं कि 2022 से पहले जो बुकिंग हुई है उनसे मिनिमम चार्ज लेकर उनको रेग्यूलराइज करें, उस वेबसाइट से उस बुकिंग को हटाएं। अगर आप इसमें करेंगी तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लाखों लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत आभार।

माननीया अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ग्यारहवें नंबर पर आपका नंबर है अगर समय सही रखेंगे आप तो आपको मौका मिलेगा उसी में रख दीजिएगा, बारहवें पर आपका है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः महत्वपूर्ण, सभी विषय महत्वपूर्ण हैं जब बोलने का मौका मिले तब बोलिएगा और निवेदन है समय का ध्यान रखें, हां जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान रोहिणी निवासियों के साथ हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे रोहिणी विधानसभा क्षेत्र एसी-13 के अंतर्गत सेक्टर-18, 19 सूरज पार्क जेजे कैंप, एन-43 की झुग्गियां, राजा विहार, सूरज पार्क कालोनी इस क्षेत्र में लगभग एक लाख लोग या तो निम्न आय वर्ग के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनका निवास है और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिये कि इस एक लाख की आबादी के लिए एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर दो एकड़ जमीन डीडीए द्वारा दिल्ली सरकार को दिलवाई गई और pillar to post पांच-छह साल आपके समक्ष भी मामला उठाकर और अन्य अधिकारियों के सामने मामला उठाकर वहां पर स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुईं लोगों में बहुत उत्साह था कि एक भी सरकारी स्कूल नहीं था अब लगभग ढ़ाई हजार बच्चों

के लिए ये दो एकड़ का स्कूल बनकर तैयार हो गया है और इस वर्ष उसमें पहली कक्षा से केजी से बारहवीं तक का यह विद्यालय बनकर तैयार हुआ था कि हमको दाखिला मिलेगा। गरीब लोगों के छोटे-छोटे बच्चे जो 5-5 किलोमीटर दूर या हाइवे क्रॉस करके दूर-दूर जाया करते थे, बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा था लेकिन अब वो समस्या दूर हो जाएगी लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस क्षेत्र के नागरिकों का दुर्भाग्य ही मानूंगा कि जब स्कूल बनकर तैयार हो गया तो यहां पर संवैधानिक अधिकार के तहत घर के नजदीक उनको स्कूल मिलना चाहिए था और ये शिक्षा नियमों के अनुसार भी बच्चों को घर के नजदीक ही स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए इसीलिए हर योजना में हर लेआउट में आबादी के अनुसार एक स्कूल की व्यवस्था की जाती है लेकिन स्थानीय निवासी निम्न आय वर्ग से हैं जो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए बने स्कूल को जब स्कूल बनकर तैयार हो गया तो वहां पर बोर्ड लगा दिया गया कि यहां पर क्षेत्रीय बच्चों के लिए दाखिले की व्यवस्था नहीं है और वहां एक बोर्ड लगा School of Specialized Excellence का। लोगों में बहुत रोष हुआ। लगातार लोग उस पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां तक की मुख्य मंत्री जब उसका उद्घाटन करने आए तब भी वहां के नागरिकों ने जबरदस्त विरोध किया जिसके कारण मुख्य मंत्री जी को पिछले दरवाजे से निकल करके जाना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों का अधिकार न छीना

जाए। अभी उसमें नवीं कक्षा से कक्षाएं शुरु की गई हैं और मात्र जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अनुसार 100 से ज्यादा बच्चे वहां नहीं हैं। स्कूल में ये तक बताया गया कि कई पोर्शन में उल्लू बोल रहे हैं क्योंकि ढ़ाई हजार बच्चों का दो एकड़ का स्कूल और मात्र 100 बच्चे और वो भी क्षेत्र के नहीं हैं कहीं से भी आ सकते हैं और जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनके बच्चों को उसी प्रकार दर–दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पहले स्कूल नहीं था तो मन में पीड़ा थी, लेकिन जब नहीं है तो क्या करें। लेकिन अब तो पीड़ा इतनी अधिक बढ़ गई है कि स्कूल है और उसी स्कूल के आगे से निकल कर दूर उनको जाना पड़ता है। मैंने इस संबंध में पहले भी कई बार 280 में दिया आज ये मेरा आठवां अटेंप्ट था 280 में इस विषय को उठाने के लिए जो मुझे आज मौका मिला है। अध्यक्षा जी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विद्यालय को वहां के क्षेत्रीय बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए उपलब्ध कराया जाए और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं वहां पर सरकार को एक प्रपोजल भी मेरी ओर से दिया गया है। हम कोई जिद नहीं कर रहे क्योंकि हमारी आवश्यकता है। आप हमारा स्कूल वहां बनाईये और आपको लगता है कि सरकार ने जिद कर ली है तो आप दो शिफ्ट में चला लीजिए। एक शिफ्ट वहां के गरीब बच्चों के लिए क्योंकि वहां पर 25 हजार लोग तो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। अनधिकृत कालोनी में लगभग 30 हजार लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप दो शिफ्ट में स्कूल चला

लीजिए एक में आप स्पेशलाइज एक्सीलेंस का स्कूल चला लीजिए और एक शिफ्ट में साधारण बच्चों का सामान्य विद्यालय चला लीजिए लेकिन हमें विद्यालय चाहिए उस क्षेत्र के लिए और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा माननीय अध्यक्षा जी जब तक कि बच्चों को स्कूल नहीं मिल जाता। उसमें अभिभावक भी शामिल हैं, आम जनता भी शामिल है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, वीरेन्द्र सिंह कादियान जी।

श्री वीरेन्द्र सिंह कादियानः माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार अच्छी स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने अच्छी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की स्किल डेवलपमेंट के संस्थान बनाए, स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की शुरुआत की, अपना अलग से बोर्ड बनाया इसी के चलते दिल्ली की जनता ने पिछले 15 वर्षों से चली आ रही सरकार को उखाड़ फेंका और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनाईं लोगों की उम्मीद थी की जैसे दिल्ली सरकार के शिक्षा संस्थान और स्कूल बेहतरीन हो गये उसी प्रकार से एमसीडी के स्कूल भी बेहतरीन हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से एमसीडी में जो प्राइमरी स्कूल हैं क्योंकि प्राइमरी शिक्षा एमसीडी स्कूलों में होती है और ये 1534 स्कूल हैं। अध्यक्ष महोदया 9 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन वहां पर मात्र 21 फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों चाहिए क्योंकि आज देखो हमारे जो

छोटे–छोटे बच्चे हैं वो मोटापे के शिकार हैं। वो कंप्यूटर, मोबाइल और बैठे रहना, बाहर न निकलना, स्कूल स्कूल से घर तो उनको ओबेसिटी, स्ट्रेस रिलीज के तौर पर डिसीप्लीन की भावना, टीम वर्क्स करना इन सबके चलते उनका शारीरिक, मनौवैज्ञानिक, मानसिक और सोशल, सामाजिक विकास के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर एमसीडी के स्कूलों में होने चाहिए। एमसीडी में 17 स्टेडियम हैं, उन स्टेडियमों में कोई ट्रेनर नहीं है, तो एमसीडी के स्टेडियमों में ट्रेनर की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली की स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी का महत्व और फायदा तभी होगा जब ये छोटे–छोटे, कम, अल्प आयु से ही बच्चे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का महत्व समझेंगे जिससे उनका विकास मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास तो होगा ही होगा और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के बच्चे खेलों में मैडल लेकर अपना नाम रौशन करेंगे, देश का नाम रौशन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक चीज का और संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में बहुत से ओलंपियन एशियाड मैडलिस्ट और कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मैडलिस्ट हैं। इन मैडलिस्ट के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। कुछ राज्यों में इनको पेंशन दी जा रही है। दिल्ली में भी कई बार ये आवाज उठी, तो इनके लिए पेंशन दी जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको लगे युवाओं को लगे कि अगर हम खेल में जाएंगे तो हमारा नाम रौशन तो होगा ही हमें अपार संभावनाएं रोजगार की भी रहेंगी और मान–सम्मान के रूप में

पेंशन मिलेगी। तो माननीया अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एमसीडी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं और एमसीडी में क्योंकि हमारी सरकार है, मैं चाहता हूं कि वहां पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति हो ताकि बच्चों का विकास हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। जयभगवान जी।

श्री जयभगवानः माननीय अध्यक्ष महोदया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदया मैं आपका ध्यान दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डूसिब की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें करीब-करीब 9374 दुकानें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हैं। अलग-अलग डूसिब के जो एरिये हैं, डूसिब की जो कालोनियां हैं उनके अंदर हैं जिसमें से मेरा जो बवाना का एरिया है उसके अंदर शाहबाद डेयरी, बवाना जेजे कालोनी सेक्टर-24, सेक्टर-20, सेक्टर-25, सेक्टर-26 के अंदर करीब-करीब 159 दुकानें जो शापिंग काम्पलेक्स बना रखे हैं वो जो खाली पड़े हैं जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है बहुत ज्यादा खराब है। अध्यक्ष महोदया मैं चाहता हूं कि उन दुकानों को सभी को अलॉट किया जाए जिससे रोजगार के साधन उत्पन्न हों। जो गरीब लोग हैं उनको वो दुकानें मिलें क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्लानिंग के साथ में वो शापिंग काम्पलेक्स वहां पर कालोनियों के अंदर छोड़े हैं अगर वो वहां पर दुकानें बन जाएंगी और उन्हें जल्दी से जल्दी अलॉट करके ऑक्शन की जाए जिससे

रोजगार के साधन उपलब्ध हों अध्यक्ष महोदय। एक तो मेरा मुद्दा यह है अध्यक्ष महोदया, दूसरा मेरा मुद्दा यह है की डूसिब डिपार्टमेंट ने 2007 में अशोक मलहोत्रा कांड हुआ जिसमें सीबीआई सारे कागज डूसिब से उठाकर ले गई और मेरे कई इलाकों से गरीब लोगों के जो डाक्यूमेंट्स हैं, प्लाटों के कागज हैं वो उन्हें नहीं दिये गये हैं वो पिछले 2007 से पिछले 15 सालों से लगातार कागजों के लिए बार–बार परेशान हो रहे हैं कि हमें हमारे प्लाटों के कागज दिये जाएं लेकिन आज तक नहीं दिये गये हैं। तो अध्यक्ष महोदया मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि शाहबाद डेयरी इलाका या बवाना का इलाका मेरा इन सभी इलाकों के अंदर जो हमारे डूसिब डिपार्टमेंट ने जो कालोनियां काटी हैं उनके सभी कागजात जो अलॉटी हैं उनको तुरंत मुहैया कराए जाएं क्योंकि बार–बार लोगों को यही कहा जाता है कि भई सीबीआई कागज उठाकर ले गईं अब लोगों को क्योंकि बहुत सी जरूरतें होती हैं और उनके कागजात नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उन्हें जल्दी से जल्दी दिया जाए। अध्यक्ष महोदया एक मेरा छोटा सा मुद्दा और भी है कि बी–ब्लॉक सीटीसी शाहबाद डेयरी क्योंकि सीटीसियां काफी बनी हुई हैं हमारे जो शौचालय हैं और हमारे यहां पर क्योंकि कम्युनिटी सेंटर नहीं है आबादी करीब ढ़ाई लाख के आसपास है तो लोग परेशान होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो बी–ब्लॉक जो शौचालय है उसको तोड़कर और उसमें एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जिससे लोगों को वहां पर लोगों की जो परेशानी है वो खत्म होगी, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने 280 के तहत मुझे सवाल उठाने का मौका दिया। मैं बहुत ही गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि वजीरपुर विधानसभा में ऐसी एक परसेंट भी पीडब्लूडी की रोड नहीं होगी जो खराब हो जिस पर कोई गड्ढ़ा हो और जो एमसीडी के रोड जो खराब थे उसको विधायक फंड से और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मुख्य मंत्री सड़क योजना के फंड से लगभग बनवा दिया गया। जो रह गई हैं उसका फंड भी अब सेंग्शन हो गया वो भी बन जाएंगी, लेकिन सवाल कुछ तीन-चार ऐसी सड़कों का है जिसके बारे में कोई भी विभाग यह मानने को तैयार नहीं है की ये किसकी है। ऐसी एक सड़क वजीरपुर गांव के पास में है जिसके बारे में बताया जाता है कि रातो-रात पार्क के अंदर से एक सड़क निकाल दी गई थी। अब समस्या यह होती है कि उस सड़क को कोई मान नहीं रहा उसकी है तो बनेगी कैसे, तो बना नहीं रहे। लाइट भी मैंने उस पर ऐसे लगाई कि एक गुरुद्वारा कोने पर था उसके ऊपर एक हाईमास्ट लगाई उसके बाद में एक दिल्ली सरकार का स्कूल नया बना तो उसके ऊपर लाइट्स लगाई तो उस रोड के ऊपर हमने रौशनी करी लेकिन उसे बनाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे ही एक सड़क एसएएस के अंदर है एसएफएस फलैट फेज-4 के वहां वो बहुत छोटा टुकड़ा था तो पीडब्लूडी से रिक्वेस्ट करके वो बनवा ली गई और तीसरी ऐसी सड़क जिसके बारे में मैं विशेष उल्लेख करना

चाहता हूं वो भारत नगर नेपाली बस्ती के साथ में है जो नाले के साथ होकर निकलती है जिसकी स्थिति इस वक्त काफी खराब है। बहुत छोटी सड़क है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है 50 एक फुट की गली मात्र कह सकते हों। लेकिन क्योंकि वो सड़क शास्त्री नगर जो कि सदर विधान सभा है, जिसमें सोमदत्त जी विधायक हैं इन्होंने भी कई बार मुझसे बात की है कि बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक उस पर आता है। वहां एक होस्पिटल भी है तो वहां से भी बहुत लोग निकलते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि कोई तो विभाग उसको ओन करें या क्योंकि जैसे सदन के अंदर एक कमेटी ऐसी है जिसको कोई भी विभाग नहीं देखता है तो वो कमेटी उसे देखती है। तो ऐसे ही ये भी होना चाहिए कि कोई सड़क अगर कोई विभाग ओन नहीं कर रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ना फंड की कमी है, ना पीडब्ल्यूडी के पास फंड की कमी है, ना मुख्य मंत्री सड़क योजना में फंड की कमी है, ना अरविन्द केजरीवाल के दिल और जिगर में कोई कमी है, फिर 50 फुट की सड़क कैसे रह जायेगी। तो आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं कि सड़क कोई डिपार्टमेंट ओन करें। फंड की कोई दिक्कत नहीं है बस आप यहां से अगर निर्देश दे दें तो वो सड़क को दिवाली से पहले बना दिया जायेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः शिवचरण गोयल जी। बोलना चाहते हैं।

श्री शिवचरण गोयलः थोड़ा बोल देते है।

माननीया अध्यक्षः जैसे आपकी इच्छा। बोलिए।

श्री शिवचरण गोयलः मेरी विधान सभा में एक रामा रोड है जो सदगरूसिंह मार्ग से निकलता है। वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का इलैक्ट्रिकल दफ्तर बना हुआ है। उस रोड पर सीवर और ड्रेन लगातार पिछले कई सालों से बह रही है। और बार–बार जल बोर्ड को, पीडब्ल्यूडी को, पत्राचार से फोन से, इन्शपैक्शन से सभी से करवाने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकल रहा। वहां से जो भी लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सिडेंट होने के जब पानी भरा होगा सड़क के ऊपर और सीवर ओवरफ्लो कर रहे होगें, ड्रेन भरी होंगी तो प्रोब्लम तो और वो पूरा मेन रोड है। वहां से रोज हजारों व्हीकल्स निकलते हैं। पूरा कॉमर्शियल एरिया है, बैंकेट्स बने हुए है, फैक्ट्रियां बनी हुई है। लोग पूरे परेशान है। तो मेरी पीडब्ल्यूडी मंत्री से, जल विभाग के मंत्री से हाथ जोडकर प्रार्थना है कि ये जो वहां पर लाखों लोग निकलते हैं और लाखों लोग काम करते हैं इस समस्या से निजात दिलवायें ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही वहां पर एक बी–58 और शिव बस्ती कलस्टर एरिया है जिसमें कम से कम भी 20 हजार लोग रहते हैं। उन्हें उस गंदे पानी से निकलना पड़ता है और काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसका निवारण जल्द से जल्द किया जाये। शुक्रिया। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद मैडम। 280 के तहत मुझे बोलने का मौका मिला है। लेकिन मैं एक मिनट सहीराम जी के विषय पर उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं कि बीच में 2022 में एक बिजली मंत्रालय से नोटिफिकेशन आया था कि जिस बिल्डिंग में कोई रह रहा है तो उसको आप मीटर देने से मना नहीं कर सकते। 15–20 दिनतक मीटर लगना शुरू हो गया था फिर अधिकारियों की मिलीभगत से उस नोटिफिकेशन को विदड्रा किया गया और ये कहा गया कि जब तक नगर निगम से बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलेगा तब तक बुक्ड प्रॉपर्टीज में मीटर नहीं लगाये जायेंगे। मैडम एक समीकरण और है। पानी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार कहा है कि अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसका पानी आप नहीं रोक सकते है और उसके आधार पर झुग्गी वालों को सभी इलिगल बिल्डिंग्स में हर जगह पानी का मीटर लगाया गया था। मेरा सिर्फ मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट है कि उस ऑर्डर के आलोक में बिजली के लिए भी ये ही ऑर्डर कर दिया जाए कि अगर बिल्डिंग में लोग रह रहे है तो आप बिजली उसका नहीं रोक सकते है। बिजली काटने पर ऑर्डर है कि अगर किसी बिल्डिंग से बिजली काट दी गई है तो उस बिजली को रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। तो नया मीटर क्यों नहीं लगना चाहिए? या तो आप उस बिल्डिंग में किसी को रहने मत दीजिए एक तो ये मेरा सुझाव है और दूसरा सुझाव है कि अगर बिल्डिंग बुक हुई है तो बुक करते

वक्त का जेई, एई और एक्सईन जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का था उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए ये नहीं कि बुक करके पैसा कमाने का एक अलग चैनेल तैयार किया जाए। तो मेरे ये दो सुझाव है मैडम। अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। माननीय लोक निर्माण विभाग की मंत्री महोदया को आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे लक्ष्मी नगर विधान सभा में चार रोड हैं, डिसुज कैनाल रोड, पटपटगंज रोड, मदरडेरी रोड और विकास मार्ग इन चारों रोडों की स्थिति बहुत खराब है मैडम। और दुखद ये है कि हमारे एक्सईन साहब लगातार मेरे लिखने, अभी पिछले दिनों 21 जून को भी मैंने ईएनसी साहब को चिट्ठी लिखा था कि मेरे क्षेत्र में जितने भी काम पीडब्ल्यूडी से सम्बन्धिात हैं या तो किये नहीं जा रहे हैं। फाईलें लटकाई जा रही है, भटकाई जा रही है, टरकाई जा रही है और बड़े प्लानिंग से विधान सभा डिस्टर्ब हो, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि मदरडेरी रोड पर नाले के निर्माण की बात हुई नाला जर्जर हो गया था, पानी लोगों के घरों की जड़ों में जा रहा था। तो मेरे को एक्सईन साहब ने बताया कि नाले का अप्रूवल हो गया है सैंक्शन हो गया, बनाने जा रहे है। बाद में पता चला कि उन्होंने सिर्फ 60 परसेंट नाले का ही टेंडर कराया और 40 परसेंट ऐज इट इज छोड़ दिया। तो मतलब इससे और लोग परेशान हो गए। ऐसे ही सेन्ट्रल वर्ज बनाना था। सेन्ट्रल वर्ज पर जो ग्रिल उन्होंने लगाया, सैकेंड पुराने ग्रिल को लाकर लगा दिया और पेंट कर दिया। ऐसे ही एक जगह सीटिंग प्लेस बनाना था उर्जा विहार पर। उसमें जो

पत्थर लगे महीने दिन बाद वो पत्थर टूटने शुरू हो गए। एक रोड कटिंग करके जल बोर्ड ने पानी का लाईन डाला मैडम वो लक्ष्मी नगर विधान सभा और कृष्णा नगर विधान सभा दोनों में डला वो पानी का लाईन। कृष्णा नगर विधान सभा विद इन 60 डेज रि–स्टोर हो गये। मेरे यहां का एरिया एक साल वैसे ही पड़ा रहा। लगातार अभी विकास मार्ग पर सौन्दर्यीकरण का कार्य चल रहा है। आपका दौरा भी हुआ था। मेरे लिए तो दुखद है मुझे जानकारी नहीं था। आपने अपने एक्स एमएलए को बुलाया साथ लेकर दौरा किया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन वो दोयम दर्जे का काम। मैडम ऐसे पिलर लगाये हैं कि लात मारो तो वो पिलर टूट जाता है। जो ग्रिल लगाये है वो तारों के ग्रिल लगा दिये है ताकि दो महीने बाद कोई भी उखाड कर ले जाये।.. मैने वीडियो भेजा है। आप कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा। ऐसे दोयम दर्जे का कार्य कि मैं.. वो तो मैं कह ही रहा हूं।..

माननीया सभापतिः राजेश गुप्ता जी।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः देखिये सच्चाई सामने आने पर आप ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन दुखद है.. ...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी, अजेश यादव जी। आप कम्पलीट..

श्री अभय वर्मा: हाॅ तो मैडम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा जो एक्सईन है वो अब तक जितने भी काम किये हैं। एक बार मैडम इन्क्वायरी कर लें। मैं मैडम से मिला था। मैं इनको नोट भी करा के आया हूं। मेरा सिर्फ ये कहने का कि हम बीजेपी और आप में फंस कर अधिकारियों को क्यों बैनिफिट दे रहे हैं। अगर वो अपना काम ईमानदरी से करें। मैं तो कहता हूं कि आप कह दो काम नहीं करना, लेकिन वो एक तरफ तो कहता है कि मुझे मंत्री जी रोकते हैं, मुझे आम आदमी पार्टी वाले रोकते हैं और दूसरी तरफ दोयम दर्जे का काम करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप काम मत करो, ठीक है भई बीजेपी का विधायक है वहां काम नहीं होंगे देंगे। मेरे को ये स्वीकार है क्योंकि मै तो भाजपा से जीत गया मैडम। ये मेरे तकदीर का मामला है। लेकिन लक्ष्मी नगर के लोगों के साथ क्यूं बेईमानी हो। लक्ष्मी नगर के लोगों के साथ दोयम दर्जे का काम क्यूं हो। तो मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जो भी पीडब्ल्यूडी के काम हैं। एक बार बुलाकर रिव्यू कर लें।..

माननीया अध्यक्ष: विषय आ गया आपका। मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री अभय वर्मा: जब भी मुझे बुलायेंगी मैं भी आ जाऊंगा। मैं स्पोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कम से कम बेईमानी नहीं हो। अधिकारी लाभ ना उठाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री शहरी विकास महोदय का ध्यान करावल नगर विधान सभा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, करावल विधान सभा क्षेत्र अधिकांश अन-ऑथोराईज्ड कालोनीज का है और 1993 से लेकर 2015 तक, इन कालोनियेां के अंदर अन-ऑथोराईज्ड कालोनी के विकास के नाम से कार्य किये गए और पिछले वर्षो के अंदर मेरी विधान सभा करावल नगर के अन्तर्गत सोनिया विहार एक जगह है। सोनिया विहार में दिल्ली सरकार के माध्यम से 374/- करोड़ रूपया फंड अलाटमेंट किया गया था और 374/- करोड़ रूपया फंड देने के बाद डीएसआईडीसी को वो फंड दिया नहीं जा रहा है जिसकी वजह से करावल नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य चल रहा है।..

माननीया अध्यक्षः आपने क्या लिखकर दिया है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैने तो ये ही लिखकर दिया था। हो सकता है कॉपी बदल दी इन्होंने। मैने तो फिर भी कॉपी निकलवाई जी वहां से। और ये देख लीजियेगा।

माननीया अध्यक्षः ये अंडर पास का विषय दिया हुआ है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ना-ना बहन वो उसका था। ये इसी अन-ऑथोराईज्ड का था उसने गलत ढंग से वहां.. ये जो आप बोल

रहे है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कोई चेलेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन..

माननीया अध्यक्षः अच्छा जो भी है बोलिये। जल्दी खत्म कीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः जी-जी। अभी पिछले दिनों के अन्तर्गत डीएसआईडीसी को बजट अलाटमेंट..

माननीया अध्यक्षः गलत है ये बहुत ज्यादा। लेकिन आप बोलिये।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैने कल का ही रिपीट करने को उसको बोला था उसने उसकी जगह 16 का दे दिया ये। ये उनके कार्यालय से..

माननीया अध्यक्षः अच्छा अब आप बोलिये-बोलिये।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः नहीं हमारे पास ना भी हो हम तब भी काम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में जो डीएसआईडीसी का टेंडर हुए थे। जिन-जिन विधान सभाओं का टेंडर होने के बाद कुछ विधान सभाओं को बाढ़ नियंत्रण विभाग को विकास कार्य करने को उनको ट्रांस्फर कर दिया। मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि करावल नगर के अन्तर्गत जो विकास कार्य जैसे सोनिया

विहार जैसी कालोनी के अंदर उसका बजट माननीय मंत्री जी को यहां से निर्देश दें आप ये चेयर उनको निर्देश दें कि बजट के साथ partiality ना हो। बजट दिया जाये। ये ही नहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत भी करावल नगर विधान सभा को बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया दलगत राजनीति से उठकरके हमको डेवल्पमेंट का काम करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि करावल नगर विधान सभा में कार्य हो सके, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महोदया जी, ये जो आपकी जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, जिस पद पर आप पदासीन हैं, यहां पर स्पीकर पिछले दिनों के अंदर यदि कोई मंत्री मुझे याद है यहां चौधरी प्रेम सिंह जी इस हाउस के सभापति थे और उसमें योगा नन्द शास्त्री हमारे यहां बाढ़ नियंत्रण मंत्री थे, वो बगैर पूछे मेरी विधान सभा के अन्तर्गत उन्होंने दौरा तय कर दिया। दौरे करें अच्छी बात है। हम इस सदन के मैम्बर हैं। जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये बात कही तो उन्होंने इसी पीठ से एक चिट्ठी लिखी कि माननीय सदस्य भले ही किसी दल का हो, दौरा करते समय उसका विषय ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत हो कि आप करें। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। जितेन्द्र महाजन जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कादियान जी बैठिये आप। बैठिये हो गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जितेन्द्र महाजन जी को मौका नहीं देना। बिधूड़ी कह रहे हैं आपको मौका नहीं देना। बैठ जाईये अभी तो आप आये हैं थोड़ी थकान उतार लीजिये उसके बाद। बोलिये जितेन्द्र महाजन जी प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाईये, बोलिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जितेन्द्र महाजन जी शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाईये हो गया आप लोग भी बीच में कूदते हैं ना, आप नहीं सुनते ना। आप लोग भी जब बीच में बोलते हैं किसी के तो आप लोग भी नहीं सुनते। आज ही तो नहीं बोले धन्यवाद, जितेन्द्र महाजन जी शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शुरू करें। मैं आगे बढूं।

श्री जितेंद्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मेरा भी 280 में जो वक्तव्य है वो

पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्षा जी, हमारे रोहताश नगर विधानसभा में पिछले कुछ वर्षों में विश्वकर्मा सेतु के नीचे सड़क बनाने का काम, ब्यूटीफिकेशन करने का काम, इलैक्ट्रिफिकेशन करने का काम के टेंडर हुये थे मगर बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है की कुछ काम हुये नहीं हैं और कुछ काम हुये हैं उनकी क्वालिटी जो है वो अत्यंत घटिया है। पिछले 12 महीने में 12 बार मैंने संबंधित पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों को मेल के द्वारा जानकारी दी है। मैंने अधिकारियों से ये निवेदन किया है कि इस काम का जो टेंडर हुआ है उसका वर्क आर्डर और शड्यूल की कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाये मगर 12 महीने में 12 बार रिक्वेस्ट करने पर भी आज तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरी जानकारी ये भी है कि electrification के कुछ कामों के भुगतान बिना काम किये ही कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारे कामों की सर्तकता विभाग से जांच कराई जाये और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः राजकुमारी जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः धन्यवाद महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे हरी नगर, विधानसभा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है दीनदयाल हॉस्पिटल तो हमारी जो दिल्ली सरकार है जितने भी दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विभाग आते हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है तो हर

विभाग से कहीं भी कोई भ्रष्टाचार था उसको हर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करके, ऑनलाइन करके बहुत ही अच्छी एक मिसाल कायम की है लेकिन आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री को एक अपनी बात का संज्ञान देना चाहूंगी। दीनदयाल हॉस्पिटल में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जोकि कॉन्ट्रैक्चुअल बैस पर काम करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बाउंसर्स जो हैं वो ऐसा काम करते हैं बहुत ही मेहनत का गर्मी हो सर्दी हो और काफी जो महिलायें हैं सफाईकर्मी जो हैं वो मायापुरी मेरे ही क्षेत्र में जे.जे. क्लस्टर है सैंकड़ों की संख्या में वहां पर सफाई कर्मचारी हैं लेकिन मैं जनता की मैं प्रतिनिधि हूं जब मेरे ऑफिस में वो आकर महिलाकर्मी या जो दीनदयाल में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं तो जब वो बताते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो हमें 8 घंटे के एवज में 10 हज़ार रुपया मिलती है और उनके एकांउट में वो डाली जाती है और जो उनके खाते की जो कॉपी होती है बैंक एकाउंट की वो वहां जो एजेंसी है जो भी इस काम का क्लीनिगं स्वीपिंग का या सिक्योरिटी गार्ड का बाउंसर्स का जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है जो आगे उनको रखती है वो कॉपिज़ अपने पास रख लेते हैं मंथली। वो ज्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं होते कि वो ज्यादा उनकी तहकीकात वो लोग करवायें। तो मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि ऐसी जो महिलायें हैं जो कि काम करती हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाउंसर हैं दिल्ली सरकार की तरफ से जो उनको एक न्युन्तम वेतन निर्धारित किया जाता है उसकी हमें एक डिटेल्ड

report दी जाये जिससे कि हम उनको बता सकें कि आपकी तनख्वाह 10 हज़ार रुपये है या 15 हज़ार है 13 हज़ार है। उनका कहना है कि बीच में जो contractual base पर ये टेंडर जो है एजेंसी जो है वो उनमें थोड़ा उनके साथ भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन दिल्ली सरकार ये चाहेगी कि जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको दिये हुये हैं उनके ऊपर विजिलेंस कमेटी से एक इन्क्वायरी करवाई जाये। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि ऐसी हमें रिपोर्ट मिलेगी जिससे कि हम उनको दिलवायेंगे आगे और जो ये इस तरह का जो उन्होंने बीच में भ्रष्टाचार जो किया हुआ है वो हमें मालूम होना चाहिये, उसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास आनी चाहिये। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री विशेष रविः मैडम ये एक बहुत बड़ा विषय है इसमें दिल्ली के अंदर बहुत सारे..

...व्यवधान...

श्री विशेष रविः शोषण हो रहा है लगातार।

...व्यवधान...

श्री विशेष रविः इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो एस.सी./एस.टी. कम्यूनिटी के हैं।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री जी इस पर जवाब देंगे बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सभी साथी बैठिये, आप बैठिये, आप बैठिये।

माननीय जल मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्षा महोदया, ये बात कई बार दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति में भी आई है और जब मैं याचिका समिति के अंदर मैम्बर था तो हमने इसकी जांच की है अखिलेश त्रिपाठी जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कई सारे मैम्बर हमारे यहां बैठे हैं और उसमें ये सामने आया कि इस पूरी की पूरी समस्या के पीछे कारण ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो आउटसोर्सिंग एजेंसी को चाहे वो डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हों, सफाई कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट हों वो सब आप GEM पर देते हो। सरकार के अंदर नियम बना हुआ है कि आप GEM पर ये कॉन्ट्रैक्ट दो तो मान लीजिये minimum wage किसी की 15 हज़ार रुपये या 18 हज़ार रुपये है दस लोग लगाने हैं तो 18 हज़ार के हिसाब से 1 लाख 80 हज़ार हो गये एक महीने के तो वो जो ठेका छूटेगा वो 1 लाख 80 हज़ार से 1 रुपया ज्यादा का छूटता है या दो रुपये ज्यादा छूट जायेगा। तो उसके अंदर क्योंकि वो मिनिमम है तो आपको उसको ठेका देना भी पड़ेगा आप ये भी नहीं कह सकते तुमको नहीं देंगे और जब एक एजेंसी किसी आदमी का ठेका या किसी प्रोसेस का ठेका उतने ही पैसे में ले ले जितने पैसे उसको उनकी तनख्वाह में देने हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो भ्रष्टाचार करेगा। वो या तो उन लोगों से पैसा वापस लेगा या 8 घंटे की जगह उनकी 10 घंटे की

ड्यूटी करायेगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा जो है अपनी क्योंकि उसके ऊपर वो अपना कमीशन तो वसूलेगा जो मैनेजमेंट फीस है। इसके लिये सरकार ने एक योजना भी बनाई है कि हम दिल्ली सरकार की ही एक कम्पनी है ICSIL, Govt. undertaking है। हमने कहा कि दिल्ली सरकार में जितने भी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे हम ICSIL के जरिये लेंगे जो डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन्हीं को लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको निकाल दिया जाये, उन्हीं को जो है हम ICSIL के जरिये लेंगे क्योंकि ICSIL एक सरकारी कम्पनी है वो 10 परसेंट कमीशन तो लेगी और वो सरकार के पास ही जायेगा उसके अंदर एक भारत सरकार की कम्पनी है TCL और एक हमारी दिल्ली सरकार की कम्पनी है DSSIDC उनकी जो है वो बेसिकली मिलकर वो कम्पनी बनी हुई है और वो इन्श्योर करते हैं जो हमारी जानकारी है अब तक वो इन्श्योर करते हैं कि उससे पूरा पैसा जो है उनकी जो है खाते में पहुंचता है। सेम हमने जो हमारे मीटर रीडर थे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर उनके साथ भी यही शिकायत थी जब मीटर रीडरों को बुलाया गया मैंने उनको पर्सनली कईयों को बुलाया की भई तुमको कितना पैसा मिलता है तो बताया गया कि किसी को 8 हज़ार रुपये मिलता है, किसी को 10 हज़ार मिलता है, किसी को 11 हज़ार रुपये मिलता है जबकि minimum wages 18 हज़ार है, तो जो आदमी 10 हज़ार रुपये मिलेंगे उसको, उसको आप कैसे एक्सपैक्ट कर सकते हो कि वो तीन लोगों के घर में

ऊपर जायेगा, सीढ़ियों से जायेगा मीटर की फोटो खिंचेगा, मीटर की रीडिंग करेगा फिर अगले में जायेगा फिर ऊपर जायेगा फिर नीचे जायेगा इतने में तो कोई काम नहीं करेगा। इतनी मेहनत का काम तो दिल्ली जल बोर्ड में भी जितने भी हमारे मीटर रीडर्स थे हमने उनको ICSIL के थ्रु लिया है ताकि उनको minimum wages जो है मुहैया कराया जा सके मगर मैं एक बात जरा जरूर बता दूं इस सदन के लिये बहुत जरूरी है कि ये ICSIL का प्रपोजल भी हमारी तरफ से फाइनांस डिपार्टमेंट को चला गया और फाइनांस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने इसके ऊपर भी चार तरीके के एतराज़ लगा दिये कि नहीं ये ऐसे कैसे कर लोगे, ये ऐसे कैसे कर लोगे, ये ऐसे कैसे सर लोगे। तो हमारी बहन जी ने ये सवाल उठाया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये सवाल उठाया। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं और आप इस बात को समझो, सरकार जहां-जहां भ्रष्टाचार और शोषण कम करने की कोशिश कर रही हैं दिल्ली सरकार के फाइनांस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी है जो वहां खड़ा हुआ है बीच में, उसके खिलाफ रिपोर्टें आ चुकी हैं मगर कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि एक तरफ से ये कोशिश है कि इन सब कामों को ठप्प किया जाये और मैं आपसे कहना चाहता हूं आप चलिये उन अस्पतालों में चलिये, आप उन डेटा एन्ट्री ऑपरेटर से बात कीजिये उनका शोषण हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है उनके साथ। मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मैं उस भ्रष्टाचार के

लिये किसी आदमी को सज़ा दे सकूं, वो सारी ताकत जो है आपके एल.जी. साहब के पास है।..

श्री ओमप्रकाश शर्मा: समाधान नहीं है आपके पास।

माननीय जल मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): ये समाधान है कि ICSIL से हो जाये मगर उस पर भी आपके ऑफिसर बैठे हुये हैं बताओ क्या करूं? तो इन सारी चीज़ों के लिये मैं आप पर कोई दोष नहीं दे रहा। इन सारी चीज़ों के लिये कम से कम इस विधानसभा को एक होना चाहिये और कहना चाहिये कि भई ये सारे काम तो होने दीजिये ये तो नॉर्मल काम हैं। इन सारे कामों को होने के लिये जो है सारी विधानसभा के लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों इसके अंदर एक राय होनी चाहिये कि ये काम होते रहें तभी जो है इसके अंदर कोई सोल्युशन होगा वरना इसी तरीके से चल रहा है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। अब श्रीमती आतिशी जी माननीय मंत्री कार्यसूची के बिंदू क्रमांक-2 के उप-बिंदू-1 एवं 2 में दर्शाये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी इसके बाद जून साहब इस, जून साहब इस विषय के बाद आप..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिए, मैं आपको मौका दे दूंगी।

...व्यवधान...

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः आदरणीय अध्यक्षा महोदया।

माननीया अध्यक्षः आप बैठ जाईये, राजेन्द्र पाल जी बैठ जाईये, गौतम जी आपको मौका मिल जायेगा।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ठीक है जी।

माननीया शिक्षा मंत्री (श्रीमती आतिशी मार्लीना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक-2 के उप-बिंदू-i) और ii) में दर्शाये गये दस्तावेज़ों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।

2 i) दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रतियां।[1]

ii) लोकायुक्त के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां (अंग्रेजी प्रति) व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)[1]:

1. वर्ष 2016-17 हेतु 15वां वार्षिक प्रतिवेदन
2. वर्ष 2017-18 हेतु 16वां वार्षिक प्रतिवेदन
3. वर्ष 2018-19 हेतु 17वां वार्षिक प्रतिवेदन

---

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23196 पर उपलब्ध।
[2]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23197 पर उपलब्ध।

श्री बी.एस.जून: अध्यक्ष महोदया।

माननीया अध्यक्ष: बैठ जाईये, मैंने आपका नाम नहीं लिया। अब श्रीमती आतिशी जी माननीय मंत्री कार्यसूची के बिंदू क्रमांक-2 के उप-बिंदू-2 में दर्शाये गये सभी दस्तावेज़ों की प्रतियां सदन पटल पर रखेंगी। ठीक है, हां जी जून साहब बताईये।

श्री बी.एस.जून: अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस सदन में कह रहा हूं कि पिछले दो दिन से जो भी प्रोसिडिंग्स हाउस की चल रही हैं बाहर जाकर कुछ मिडिया के लोग उनको distort करते हैं edited करते हैं और उनको ट्वीस्ट करके एक ऐसी इमेज फैलाई जा रही है जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार को अटैक कर रहे हैं। परसों जल बोर्ड पर बात हुई, कल स्वास्थ्य विभाग पर बात हुई और हर विधायक ने कहा क्योंकि फाइनांस डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने और एल.जी. ने पैसा रोककर इन डिपार्टमेंट्स को पंगु बना दिया है जिससे लोगों को भी दिक्कत आ रही है और इन डिपार्टमेंट्स को भी काम करने में दिक्कतें आ रही हैं लेकिन हमारे यहां एक यूट्यूबर हैं Times Now Nav Bharat के मिस्टर सुशांत सिन्हा उनको, लगता है, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री से कुछ ज्यादा प्रेम है, वो उनको ऐसा ट्वीस्ट करते हैं selectively कुछ लाइनें उठाते हैं और वो प्ले करते हैं जबकि किस बारे में किस कॉन्टैक्सट में क्या बात कही उसको छुपा जाते हैं। तो ये इस हाउस का breach of

privilege है क्योंकि वो प्रोसिडिंग्स को ट्वीस्ट कर रहे हैं distort कर रहे हैं। कल मैंने उसके खिलाफ एक राइटिंग में कम्पलेंट दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कम्प्लेंट को प्रिविलेज़ कमेटी को भेजा जाये और उनको पनिश किया जाये।

माननीया अध्यक्षः जी, आ गया विषय आ गया, सभी का विषय आ गया, अब बैठिये।

श्री कुलदीप कुमारः एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

माननीया अध्यक्षः कुलदीप जी बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कुलदीप जी बैठ जाईये, मैं बोलने का मौका दूंगी।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, एक अमन चोपड़ा नाम का व्यक्ति भी है..

माननीया अध्यक्षः मैं आपको बोलने का..

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः क्योंकि ये पिटिशन कमेटी का मैटर था और ये रिपोर्ट जो है आप ही के द्वारा पिटिशन कमेटी को भेजी गई है उसके ऊपर अगर ये किया जा रहा है तो प्रिविलेज का मैटर है और इसको प्रिविलेज में भेजा जाये, मेरा आपसे निवेदन है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं सभी सदस्यों को ये कहना चाहती हूं कि जिस-जिस भी साथी के साथ ऐसा हुआ है कि उसके वक्तव्य के साथ छेड़छाड़ करकर और किसी दूसरे तरीके से उसे दर्शाया गया है, बताया गया है वो सभी लोग लिखित में अपनी शिकायत दे दें, आपकी शिकायत प्राप्त होते ही इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जायेगा।

श्री अजय कुमार महावरः अध्यक्ष महोदया, मैंने नियम-54 के तहत एक calling attention लगाई है उस पर अभी तक L.O.B. में तो हमने देखा नहीं, मैं आपके..

माननीया अध्यक्षः मैं ये विषय ले लूं फिर आपको बोलने का मौंका देती हूं।

श्री अजय कुमार महावरः जी।

माननीया अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 17 अगस्त, 2023 को सदन में प्रस्तुत किये गये कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के संबंध में याचिका समिति के चौथे अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत हैं।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 17 अगस्त, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के चौथे अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीया अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें:

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें,

(सदस्यों द्वारा हां कहने पर)

हां पक्ष जीत, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री ऋतुराज गोविन्द द्वारा द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में कथित घोटाले और सीएजी द्वारा.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको बताना जरूरी है। मुझे सुनाई देता है। मैं उनको बोल चुकी कि..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैंने उनको बोल दिया कि मैं ये विषय ले लूं.

......व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैंने ये....

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गौतम जी बैठिये। दो मिनट बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपने एक बात बता दी, मैंने आपको ये कहा जो मेरे समक्ष विषय हैं मैं ये ले लूं, मैं आपकी बात सुनूंगी भी, आपको बोलने का मौका भी दूंगी। मैंने मना किया।

......व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः हम यहां ग़लतू विषय डिस्कस कर रहे हैं। हम यहां बेकार विषय डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ना। मैंने बोल, लिया और न लेने में क्या फर्क है। मैंने उन्हें बोला है कि जो विषय मेरे समक्ष है, मैं इसको कर लूं, उसके बाद आपको मौका देती हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः महावर जी बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में कथित घोटाले और सीएजी द्वारा संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताई गयी अन्य अनियमितताओं के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। ऋतुराज जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको क्या बोला, बड़े साफ शब्दों में, बड़ी विनम्रता के साथ मैंने ये बोला है कि जो विषय मेरे समक्ष है, मैं पहले इसको ले लूं आपके विषय पर मैं आपको रूलिंग दे दूंगी।

इसपर क्या, ऐसा क्या है, जो इसमें आपको समझ नहीं आया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं नहीं, अभी अभी..

माननीया अध्यक्षः इसमें क्या ऐसा विषय है जो आपको..

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः एक के बाद एक विषय शुरू होता जाएगा।

माननीया अध्यक्षः नहीं ऐसा नहीं है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः एक के बाद एक।

माननीया अध्यक्षः ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः एक के बाद एक होगा।

माननीया अध्यक्षः ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं नहीं, हमें मौका ही नहीं मिलेगा।

माननीया अध्यक्ष: बैठिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अगर हम कॉलिंग अटैंशन लगाएंतो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यदि हम शॉर्ट डुरेशन डिस्कसन लगाए तो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।

माननीया अध्यक्ष: आपको जाना है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आपका जाने का मन है?

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इस हाउस की उपयोगिता क्या है?

माननीया अध्यक्ष: आपका जाने का मन है?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं आप बताइये।

माननीया अध्यक्ष: नहीं, आपका सदन से जाने का मन है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बताइये तो सही न।

माननीया अध्यक्ष: बैठ जाइये।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अब..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: बैठिये,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: तो बैठ तो जाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: बैठिये,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: महावर जी। आप चार लोग एक साथ बात करेंगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: नहीं आपमें इतनी कैपेसिटी होगी कि आप चार लोगों की बात एक साथ सुन भी सकते हो और एक साथ जवाब भी दे सकते हैं। मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं साधारण इंसान हूं, एक बार में एक ही की सुन सकती हूं। आप डिसाइड करिये आठों एक साथ बोलेंगे, आठो लोग एक साथ बोलेंगे, आठो लोग एक साथ बोलेंगे,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मेरा भी आग्रह है, बैठाइये साथियों को, अपने साथियों को बैठाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप अपने साथियों को बैठाइये। बिष्ट जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बिष्ट जी, मोहन सिंह बिष्ट जी। जितेन्द्र महाजन जी कृपया बैठें। अगर अजय महावर जी ने दिया है कॉलिंग अटेंशन तो वो बोल रहे हैं न, आप लोग क्यों खड़े हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः तो बैठिये न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ के नहीं होता समर्थन, बैठ के आप आम आदमी पार्टी वाले बन जाएंगे। बैठ के भी भारतीय जनता पार्टी वाले ही रहेंगे। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बिधूड़ी जी बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये, महावर जी बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः हां तो बैठ जाइये न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैंने आपको मौका, मैंने आपको मौका देने के लिए तो बिल्कुल भी मना नहीं करा है। मैंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि जो विषय मेरे समक्ष है, पहले मैं इस विषय को ले लूं उसके बाद आपकी बात को मैं सुनूंगी भी..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ॠतुराज गोविन्द जी, शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कुलदीप जी, कुलदीप जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शुरू करें।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अगर आप चाहते हैं तो चेयर का सम्मान करिये मैंने बोला है। पहले मैं ये विषय, पहले इस विषय पर चर्चा होगी, उसके बाद।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मत बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज गोविन्द जी, ऋतुराज झा जी शुरू करें चर्चा, शुरू करें।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः जी।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः माननीय अध्यक्ष जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मुझे पता है। मुझे पता है, मेरे पास है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज जी शुरू करें।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः अभी हमारे देश में, हमारे माननीय प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी जी..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अब देखिये जो मैंने आपको कहा है, एक सेकेंड। मैं जो आपको कहना चाहती हूं, जब तक आप लोग बैठ के,..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः जब तक आप लोग ये.....

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः कहते हैं..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः मैं बोलूं अब।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः इस चेयर को भी आपसे बहुत उम्मीद है। मैं बोलूं एक बात, मैं बोलूं, मैं बोलूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप मुझे बोलने का मौका देंगे।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः मार्शल आउट कर दीजिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मेरा निवेदन यह है जब तक एक साथी वहां से वार्तालाप नहीं करेगा। एक व्यक्ति संवाद नही करेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। सब लोग संवाद करेंगे, मुझे नहीं सुनाई देगा, न कुछ समझ आएगा। बैठ कर एक व्यक्ति संवाद करें,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः एक सदस्य संवाद करें, आपके चाहे चीफ व्हिप संवाद करें या ये करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये। मैं रूलिंग दे देती हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः एक व्यक्ति संवाद करेगा। आप डिसाइड करें कौन संवाद स्थापित करेगा आपकी तरफ से,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बाकी बैठिये फिर। बाकी सब बैठिये। देखिये अगर आपको रूलिंग चाहिए, रूलिंग में भी वही शब्द होंगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः महावर जी पहले सुन लिजिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः पहले आप मेरी बात सुनिये। रूलिंग में भी वही शब्द होंगे जो मैंने आपको बहुत ही प्यार से यहां से कहा कि मेरे सामने जो विषय है पहले, मैं वो टेक-अप कर लूं, उसके बाद अगर आपको रूलिंग चाहिए। मैं आपको रूलिंग पढ़कर बोल देती हूं। आपको ज्यादा उसमें वो लगेगा।

श्री अजय कुमार महावरः मैं ये कह रहा हूं आप कभी भी इस पर चर्चा कराएं। एक मिनट मेरी बात सुनिये न जी। मैं कह रहा हूं चर्चा आप बाद में कराएं, उसपर आपत्ति नहीं है, पर आप रूलिंग दीजिए कि नरेश बाल्यान जो विधायक हैं जिस पर मनी एक्सटोर्शन का मामला है। जिस परमनी एक्सटोर्शन का मामला है। अपराधिक षडयंत्र का मामला है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं..

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः गैंगस्टर से मिला हुआ है वो आदमी।

...व्यवधान...

मननीया अध्यक्षः जो मैंने बड़ी विनम्रता से बात कही। जो बात मैंने बड़ी विनम्रता से कही। अगर वो रूल के अंतर्गत ...

...व्यवधान....

श्री अजय कुमार महावरः विच रूलिंग, रूलिंग दीजिए आप।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अब मैं उस बात को रूल के अंतर्गत बोल देती हूं।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः रूलिंग दे दीजिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यों से नियम, मुझे माननीय सदस्यों से नियम 54 और 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये विनय मिश्रा जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि समय के अभाव के कारण कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहीं हूं। ठीक, धन्यवाद। ऋतुराज जी।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय,

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः जाना है न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः इतने शोर में ...

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कोई तरीका नहीं ये, ये कोई तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ये कोई तरीका है?

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः दो मिनट बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये दो मिनट।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये तो, मैं भी आप लोगो से निवेदन कर रही हूं।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठिये,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अगर बैठिये तो, बिना बैठे तो कोई बात नहीं समझ..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये, पांच मिनट बैठिये, बैठ जाइये बिधूड़ी जी प्लीज।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी, विजेन्द्र गुप्ता जी, महावर जी, अगर आप जाना चाहते हैं जाइये, अगर आप समाधान चाहते हैं तो बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइए। अनिल बाजपेयी जी अभी तो, अभी तो महत्वपूर्ण विषय के लिए समय मांग रहे थे और अब समय खराब कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः देखिये एक सेकेंड, विनय मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। विनय मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मैं पूरे सदन से अपील करना चाहती हूं विनय मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। विनय मिश्रा जी अपनी बात रखें।।

श्री विनय मिश्राः मैडम जो ये बात उठा रहे हैं। कल शाम को अजय कुमार मलिक है मैम...

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः मैडम..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सुन लिजिए दो मिनट। सुन लिजिए प्लीज।

श्री विनय मिश्राः मैडम जो ये मसला उठा रहे हैं, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दे रहा हूं। कल शाम को अजय कुमार मलिक की कोर्ट है द्वारका की, उन्होंने टाइम्स नॉउ को रेस्ट्रेंन किया है कि आप ये खबर नहीं चलाओगे क्योंकि ये खबर झूठी है, इसपर बाकायदा नरेश बाल्यान जी ने एफआईआर करायी है कि ये मुद्दा झूठा है। मैं आपको ऑर्डर की कापी देता हूं आप इनको दे दीजिए मैम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऑर्डर की कापी देना चाहता हूं, ये झूठ की दुकान चला रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं आपको, मैं पूरा आश्वासन दे रही हूं मैं सुन लिया आपकी बात, बैठिये। बैठिये।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः मैडम ....

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः एक दवाई व्यापारी से घोण्डा के भाजपा के विधायक हैं.....

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः एक करोड़ रुपया मांगा है।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः मैं आर्डर पढ़ना चाहता हूं मैंडम एक बार आर्डर पढ़ता हूं आपके सामने।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः तरीका है। बिल्कुल तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः मैडम मैं आर्डर पढ़ता हूं, इनको समझ आ जाएगी।

...व्यवधान.....

माननीया अध्यक्षः ये कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी तरीका नहीं है ये, आप चर्चा होने ही नहीं देना चाहते।

...व्यवधान...

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।)

माननीया अध्यक्षः जाना था तो ऐसे ही चले जाते। अगर फुटेज देकर, मीडिया की हैड लाइन बनाकर जाना था तो ऐसे ही चले जाते। सदन का समय भी क्यों खराब किया। ऋतुराज जी।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः मैडम मैं आर्डर पढ़ दूं। चले गये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः देखिये मैं पूरे सदन को एक बात कहना चाहती हूं कि ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है और जो अभी बोला है विनय मिश्रा जी ने, ये सदन के रिकॉर्ड में भी आया है और इस तरह का अगर कोई गलत कॉलिंग अटैंशन देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी लेकिन ये सब चीजें तभी संभव होती है जब शांति बने कि सामने वाला कह क्या रहा है। अगर सभी लोग शोर मचाएंगे, शोर में कौन क्या कह गया, किसके खिलाफ कह गया, कौन तथ्यविहिन बात को रखकर चला गया, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए अगर यहां से बोला जा रहा है शांति बनाए रखें तो आपको उस बात को महत्वपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए और उसकी महत्वता को समझना चाहिए। जी, ऋतुराज जी।

अल्पकालिक चर्चा नियम-55

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय को उठाने का मौका दिया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हर भाषण में एक ही बात कहते हैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा और अभी सीएजी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश की गयी है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत माला प्रोजेक्ट है, जोकि इनकी योजना थी लगभग 75 हजार किलो मीटर की सड़कों को बनाने का, जिसका एस्टिमेटेड कोस्ट 15 करोड़ के आस पास था, जिसको बाद में 18 करोड़ रुपए और फिर 25 करोड़ कर दिया गया और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य में जो कि एस्टिमेटेड कोस्ट था 18 करोड़ पर किलो मीटर का, उसका कोस्ट जोकि इन्होंने किया है वो 250 करोड़ यानी कितना गुना हो गया आप लोग कैलकुलेट कर लिजिए। 250 करोड़ पर किलोमीटर, सोने की सड़क मतलब 18 करोड़ पर किलोमीटर का जो एस्टिमेटेड कोस्ट है, इन्होंने बनाया है 250 करोड़ पर किलो मीटर के हिसाब से।

ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये कोई ऋतुराज झा की रिपोर्ट नहीं है। सीएजी एक संवैधानिक बॉडी है, जोकि हर सरकार का ऑडिट करती है और सीएजी की रिपोर्ट से ही कोयला घोटाला उजागर हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट से ही टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ था। पर, ये घोटालो का घोटाला है, ये महाघोटाला है। आप सोचिये कि 75 हजार किलोमीटर की सड़क बनाने में इन्होंने लगभग

750 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया है, 750 लाख और जब भी पैसे की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, इनके मित्र की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है।

''चौथी पास राजा की एक ही कहानी आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी।'' अडानी ही अडानी। कैसे, हम बताते हैं आपको। आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी और भारतमाला प्रोजैक्ट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। केरला में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजैक्ट अडानी का। तेलंगाना में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। आन्ध्रप्रदेश में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। महाराष्ट्र में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। इसके अलावा उड़ीसा में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। मध्यप्रदेश में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का। वेस्ट बंगाल में भारत माला प्रोजैक्ट अडानी का और ऐसे मित्र हैं अडानी जी जिनके साथ मतलब एक-एक प्रोजैक्ट में एकदम रिश्ता जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये पहले सीरियल आता था। ये जो है सो हिन्दुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय हैं। जिसके बिना उनको रात को नींद भी नहीं आती है और उस व्यक्ति का भारत माला प्रोजैक्ट में एक भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है जिसमें अडानी ना हो। एक भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है और इतना ही नहीं है, पूरे आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पर चले जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का। पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का। समुन्द्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का। सड़क

अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेन्ट अडानी का, मोदी अडानी का।.. देश में प्रधानमंत्री भी अडानी का। एकदम ठीक कहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की आम आदमी को नहीं जीने दूंगा और चौथी पास राजा की एक ही कहानी आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी। आप देखिए कि ये लोग वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह हैं। धो मांझकर के अपनी पार्टी में ले आते हैं, वो इमानदार हो जाता है। जैसे वाटर घोटाला किया था हेमंत विश्ववर्मा इनकी पार्टी में आ गया तो असम का मुख्यमंत्री हो गया। यही लोग बंगाल में कहते थे चिड फंड हुआ है, चिड फंड घोटाला हुआ है। सीबीआई हुआ ईडी हुआ और वही सफबेन्दु अधिकारी इनकी पार्टी में आ गया तो लीडर ऑफ अपोजीशन हो गया बंगाल में। इनका येदुरप्पा को लेकर के क्या कहानी रही। सुखराम को लेकर क्या कहानी रही। शिंदे और सिंधिया ऑपरेशन लोटस चलाए, अपनी पार्टी में ले आये। ये अजीत पवार घोटालेबाज था, 76 हजार करोड़ का चक्की पिसिंग, पिसिंग करते थे। इनकी पार्टी में आ गया तो ईमानदार हो गया। इनका कोई काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, इनका एक जिसको बोलते हैं ना क्रोनी कैप्टोलीजम, उद्योगपतियों के साथ एक ऐसा नेक्सेस है कि जो देश के गरीबों को लूटने का और शोषण करने का काम कर रही है। जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो इमानदार हो जाता है। ईडी और सीबीआई पपेट हैं नरेन्द्र मोदी जी का जो केवल और केवल political vendetta के लिए, केवल ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, लोगों

को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो अगर ईडी और सीबीआई औरअगर मोदी जी ने काम किया होता तो विजय माल्या पैसा लेकर नहीं भागता। मेहुल चौकसी पैसा लेकर नहीं भागता। नीरव मोदी पैसा लेकर नहीं भागता और अडानी के ऊपर में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का प्रधानमंत्री का पूरा जो नेक्सेस है, पूरी जो इमानदारी का ढोंग है, जो भाषण है पूरी तरह से खोखला है और उनका जो है इसमें पूरी तरीके से इनके साथ में लेनदेन है। तो अध्यक्ष महोदय आज इस सदन के माध्यम से हम सब लोग आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में 750 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतमाला प्रोजैक्ट और ये द्वारका एक्सप्रेस वे का जो ये सोने की सड़क जो इन्होंने बनाई है 18 करोड़ का स्टीमेटिड कोस्ट से 250 करोड़ का स्टीमेटिड कोस्ट तक मतलब आप सोचिए कि कोई मतलब कि कोई किसी तरह का, किस तरह की ये बात 18 करोड़ की स्टीमेटिड कोस्ट 250 करोड़ का हो गया पर किलोमीटर। मतलब सोने की सड़क बनाई है क्या आपने! तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसी ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो सारा ही प्रोजैक्ट अगर आप मुद्रा पोर्ट से लेकर के, आकाश से ले के पाताल से लेकर भारत

माला का जैसा मैंने बताया छत्तीसगढ़ से ले के, मध्यप्रदेश से ले के, केरला से ले के, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो भारत माला का प्रोजैक्ट अडानी का ना हो। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का नैक्सेस है और किस तरह का ये करप्शन हुआ है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा महा घोटाला है जिसकी चर्चा आज ये सदन कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सदन चर्चा करेगा और इसपे जांच होगी और देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से आजाद भारत में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो वो 2014 में बने नरेन्द्र मोदी हुए हैं और जिसका जो है फेस पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, वो सीएजी ने करने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षा: चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इस गंभीर विषय पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि सारे जो है इस देश के सारे चैनल इस विषय पे चुप हैं। अध्यक्ष महोदय ये सीएजी की रिपोर्ट जो है हर साल आती है और हर साल जो है अलग-अलग सरकारों पे सीएजी ऑडिट करती है। इस बार गिरीश चन्द्रा मुर्मु जो है रिटायर्ड आइएएस हैं। वो सीएजी के डायरेक्टर है और उन्होंने हिम्मत करी और धन्यवाद देना चाहूंगा सीएजी को क्योंकि जो भ्रष्टाचार कोई नहीं उजागर कर रहा, वो भ्रष्टाचार जो है सीएजी ने उजागर किये। सात इतने बड़े-बड़े घोटाले जो हैं वो मोदी सरकार के सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट में अपने खुलासे किये जिसमें

सबसे बड़ा खुलासा जो है द्वारका एक्सप्रेस वे का है। द्वारका एक्सप्रेस वे में अभी जैसा ऋतुराज जी ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेस वे में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। जिसमें Cabinet Committee on Economic Affairs जो एक संस्था होती है, जो अप्रूवल देती है, उसने अप्रूवल दिया 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए लेकिन एनएचएआई के बोर्ड ने वो पैसा 7287 करोड़ अप्रूव किया जोकि 251 करोड़ प्रति किलोमीटर का हिसाब है। मतलब जो सड़क जो है 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बननी चाहिए थी वो 251 करोड़ प्रति किलोमीटर में बन रही है। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा घोटाला जो है इस देश में कौन–सा हो सकता है। इतनी खुली लूट जो है मोदी सरकार में इस सीएजी रिपोर्ट ने उजागर करी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। अब इनका जो वचन है वो चेंज हो गए, वो बदल गए। वो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा उससे बढ़कर है, मेरे पास बैठ जाओ मैं अपने हाथ से रोटी तोड़–तोड़ के और निवाले खिलाउंगा। ये स्थिति जो है मोदी सरकार की इस समय हो चुकी है। 'बहुत हो गया भ्रष्टाचार अबकी बार मोदी सरकार'। ऐसे–ऐसे नारों के साथ जो है मोदी सरकार आई थी और अंत में क्या हुआ, मोदी सरकार का सारा खुलासा जो है इस समय सीएजी रिपोर्ट में हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पुराने पापी हैं। देखिए क्योंकि कोई भी सरकार रहती है क्योंकि हाथ में सारी एजेंसी रहती हैं, केन्द्र सरकार के हाथ में सारी एजेंसी

रहती हैं। ईडी, सीबीआई फलाना ढिमका सारे उनके हाथ में। सीऐजी ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से सरकार के खुलासे होते हैं और इस सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार का खुलासा हुआ। इसके अलावा जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां पे भी सीएजी रिपोर्ट जब-जब आई तब-तब इनके बहुत बड़े भ्रष्टाचार जो है, क्योंकि ये पुराने पापी हैं, ये एक्सपीरियन्स होल्डर हैं, तब इसने सारे 10 साल के जो भ्रष्टाचार हैं वो सीएजी रिपोर्ट ने खोल के दे दिये। हरियाणा में जो खट्टर की सरकार है, उसने 1421 व्यक्ति के ट्रीटमेंट जो है एक ही दिन में एक ही अस्पताल में दर्शाये गए और सेम नम्बर पे। जिस तरीके से आयुष्मान भारत का एक बड़ा घोटाला जो है ये सीएजी रिपोर्ट में आया जिसमें साढ़े सात लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर पे किया गया। उसी तरीके का घोटाला जो है खट्टर सरकार में सीएजी रिपोर्ट ने उजागर किया। शिवराज सिंह चौहान का घोटाला जो है बहुत फेमस घोटाला है। पोषण आहार घोटाला जिसमें स्कूटरों के नंबर जो हैं उससे राशन ढोया गया और फाइलों में जो है वो ट्रक के नंबर शो करे गए। पोषण आहार घोटाला जो है 30 हजार करोड़ का घोटाला जो है वो मध्यप्रदेश में हुआ। उसके बाद धामी सरकार में उत्तराखंड में 37 लाख टन के अवैध खनन का घोटाला जिसमें 45 करोड़ राजस्व का चूना जो है वो सरकार को लगा, ये सीएजी ने खुलासा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार का। योगी का उत्तर प्रदेश का घोटाला जो है जिसमें 3640 करोड़ रूपए 5 डिपार्टमेंट में योगी सरकार में

घोटाला हुआ उसका खुलासा जो है वो सीएजी रिपोर्ट में हुआ। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी पे जोकि ये कहते हैं कि क्योंकि अयोध्या भगवान श्रीराम की नगरी है और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सिर्फ वो कहते हैं कि 'मुंह में राम बगल में छुरी', उस तरीके की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी की रहती है। इसने भगवान श्रीराम की अयोध्या नगरी को भी नहीं बख्शा और अयोध्या डेवलपमेंट अथोरिटी में 20 करोड़ का घोटाला जो है वो वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया अध्यक्ष महोदय। सुशील सिंदे, सुशील सिंदे कह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार जो है उसमें 12 हजार करोड़ का irregularity of fund का घोटाला जो है वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया। कर्नाटका में जो इनकी पहले सरकार थी उसमें 4850 करोड़ का अनस्पेंट फंड का घोटाला जो है वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पुराने पापी हैं इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी जब सीएम थे, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 में गुजरात में तब इन्होंने वहां पे भी एक बहुत बड़ा घोटाला किया KG BasinBlock घोटाला जोकि 16706 करोड़ रूपए का था और उस समय वहां के सीएजी 2012 में जो सीएजी रिपोर्ट में आई उसमें इसका घोटाले का जिक्र जो है सीएजी रिपोर्ट में होगा उसका बहुत बड़ा खुलासा उस समय हुआ। तो ये मोदी जी जो हैं वो पुराने पापी हैं, एक्सपीरियन्सड हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सपीरियन्सड हैं।..

माननीया अध्यक्षाः कम्पलीट कीजिए।

श्री प्रवीण कुमारः गुजरात में जो उन्होंने करा वही अब देश में करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। गुजरात मॉडल ये ही था। अध्यक्ष महोदय एक सीएजी रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी 2020 में। 2020 में दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट आई थी और दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट में ये बताया गया क्योंकि सारे प्रदेश में घाटे में सरकार चलती है, लेकिन दिल्ली में जो 2020 की सीएजी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यु प्रोफिट में है, सरप्लस रेवेन्यु है 7499 करोड़ का। ये पूरी दिल्ली विधान सभा के लिए फक्र की बात है। जहां सारी सरकार घाटे में जाती हैं दिल्ली सरकार, अरविन्द केजरीवाल की सरकार 7499 करोड़ के सरप्लस प्रोफिट में चलती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय एक मेरे को ये देख के बहुत हैरत होती है ये वही सीएजी रिपोर्ट है जो जिसने 2जी और 3जी और कॉल ब्लॉक के स्कैम का उजागर किया था। उस समय विनोद राय जी थे जो सीएजी के डायरेक्टर थे। उस समय सारी मीडिया और सारा माहौल जो है वो पूरी तरीके से सीएजी रिपोर्ट ने बना दिया था। सारी मीडिया ने खुल के दिखाया। लेकिन इस समय ये सारी मीडिया इतने दवाब में है, सारी गोदी मीडिया इतने दवाब में है कि सीएजी रिपोर्ट पे एक शब्द मैंने किसी टेलीविजन पे नहीं सुना, ना ही किसी अखबार में देखा। अध्यक्ष महोदय ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर करती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इन भारतीय

जनता पार्टी जो है ऐडी से ले के चोटी तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके बेइमानी की जो है वो पराकाष्ठा हो चुकी है। मेरे पास आज मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी पंक्तियां काका हाथरसी जी की हास्य व्यंग जो है वो मुझे मिली आपके सामने यहां पे पढ़के सुनाता हूँ।

मन मैला तन ऊजरा, भाषण लच्छेदार,
मन मैला तन ऊजरा, भाषण लच्छेदार,
ऊपर अत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार,
झूठे के घर पंडित बांचे कथा सत्य भगवान की,
जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की,
न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस,
जिसकी लाठी बलवती हांक ले गया भैंस,
निर्बल धक्के खाए, तूती बोल रही बलवान की,
जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की।'

एक और है ये आप समझ जाओगे किसके लिए है। नेता जी की कार से कुचल गया मजदूर। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कांड।

'नेता जी की कार से कुचल गया मजदूर,

बीच सड़क पर मर गया हुई गरीबी दूर,

गाड़ी को ले गए भगाकर जय हो कृपा निधान की,

जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की,'..

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवीण कुमारः एक और एक और आखिरी पंक्ति है अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रवीण कुमारः बेकारी और भूखमरी, महंगाई घनघोर, ये कहते हैं,

'बेकारी और भूखमरी, महंगाई घनघोर,

घिसे पीटे शब्द हैं, बंद कीजिए शोर,

ये मोदी जी कह रहे हैं,

घिसे पीटे शब्द हैं, बंद कीजिए शोर,

अभी जरूरत है जनता के त्याग और बलिदान की,

जय बोलो बेईमान, जय बोलो बेईमान की।'

माननीया अध्यक्षः जय भगवान जी। समय सीमा का सब लोग ध्यान रखें भई

श्री जय भगवानः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मुद्दे पर, अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने

का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेरे साथियों ने बताया कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक फिल्म का हिंदी गाना याद आ रहा है पुराना कि–

'जहां डाल–डाल पर,

जहां डाल–डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा,

वो भारत देश है मेरा।'

क्योंकि हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़ियां हुआ करता था। पहले अंग्रेज लूटकर ले गये। अब जो दूसरे अंग्रेज हैं वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। बार–बार जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुछ मित्र भी हैं इसमें और कुछ लोगों को उन्होंने धक्का देकर के यहां से भगाया कि हिंदुस्तान से भाग जाओ, नहीं तो आपको पकड़ा जाएगा। जैसे नीरव मोदी जी, मेहुल चौकसी जी, विजय माल्या जी, इन सबको भगा दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े–बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं, 'न मैं खाऊंगा, न ही खाने दूंगा।' लेकिन उनके इस राज में बहुत बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं। एक 75 हजार किलोमीटर सड़क में साढ़े सात लाख करोड़ का घोटाला, जो अभी कैग की रिपोर्ट में आया है। द्वारका एक्सप्रेसवे में जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो सड़क बननी थी वो करीब–करीब ढ़ाई सौ करोड़ के हिसाब से इन लोगों ने बनाई है। तीसरा अयोध्या

में जमीन का घोटाला। चौथा दिल्ली मुम्बई हाइवे में 154 करोड़ का घोटाला और एचएएल में डिजाइन प्रोडक्शन में, जो डिजाइन की है उन्होंने उसमें 159 करोड़ का घोटाला। सबसे बड़ा अध्यक्ष महोदय जैसे पेंशन, जो पेंशन का जो पैसा है उसमें प्रचार का घोटाला, वो भी 2 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रचार का घोटाला किया है इन लोगों ने। और एबीजी के शिपयार्ड का अभी आपने सुना होगा, 28 बैंकों में 22,282 करोड़ रुपया जो है वो लूट लिया गया। वो भी इन्हीं सभी के मित्र हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जो अभी निकलकर आया, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है अध्यक्ष महोदय जिसमें, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, जो कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि 'आयुष्मान भारत' के अंदर, 'आयुष्मान भारत' में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। करीब-करीब अध्यक्ष महोदय देश के 120 अस्पतालों में 2 सौ करोड़ का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही निंदा का विषय है कि करीब-करीब, इलाज के दौरान 8,760 लोगों की मृत्यु हो गईं अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 2103 लोग जिनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डेड बॉडियों का ट्रीटमेंट, आपने जो कभी नहीं सुना होगा। जैसे हमने फिल्म देखी थी न, एक फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि डेड बॉडी को जब चेक कराने जाते है तो वो डेड बॉडी का ही इलाज कर देते है, वैसा ही इलाज मोदी सरकार में चल रहा है। 2103 डेड बॉडियां, जो लोग मर चुके हैं उनका भी इलाज चल

रहा था। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदय, ऐसे-ऐसे मुद्दे हैं कि एक-एक आदमी को कई-कई बार अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया गया है। और एक ही नंबर पर, 9999999999 पर करीब-करीब साढ़े सात लाख लोगों ने, साढ़े सात लाख लोगों का इलाज किया गया अध्यक्ष महोदय। ये कैसा घोटला चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को जरूरत है इलाज की उनका इलाज हो नहीं पा रहा है। और इस योजना के तहत करीब-करीब 50 लाख लोगों को इसमें कवर करने की बात की गई थी और सभी लोगों से 5 लाख रुपये, कि भई 5 लाख रुपये का आपका इलाज होगा लेकिन उनके साथ में तो एक तरीके से लूट हो रही है। कोई भी आदमी जाता है इलाज कराने उसको पता ही नहीं है, उसका इलाज है 100 रुपये का और कर दिया कम से कम 50 हजार रुपये का। तो अध्यक्ष महोदय, आज जो कैग की रिपोर्ट आई है अब, इसमें मोदी सरकार के जो घोटाले हुए हैं उनकी एक तरीके से पोल खुल गई है। तो एक पंक्ति के साथ मैं कहना चाहता हूं-

‘बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं वो,
बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं वो,
लेकिन उन पर अमल नहीं करते,
बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं वो,
लेकिन उन पर अमल नहीं करते,

पूछते हैं जब उनसे, पूछते हैं जब उनसे,

अमल क्यूं नहीं करते,

वो कहते हैं नीयत नहीं है हमारी,

नीयत है हमारी केवल, नीयत है हमारी केवल लूटने में,
लूटने में, लूटने में।'

माननीया अध्यक्षः चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय भगवानः अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर ये लूटबाजारी हो रही है, इस लूटबाजारी पर रोक लगनी चाहिए और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर के भाषण देते हैं कि 'मैं न ही भ्रष्टाचार करूंगा और न ही भ्रष्टाचार होने दूंगा' लेकिन ये तो उनके सामने हो रहा है, उनकी सरकार में हो रहा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, नमस्कार जी।

माननीया अध्यक्षः हाजी युनूस जी।

श्री हाजी युनूसः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 2014 से इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिसके माननीय मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाये, बड़े-बड़े

सपने, मुंगेरी लाल जैसे सपने इस देश को दिखाकर वो इस देश की गद्दी पर बैठ गयें। 15-15 लाख रुपये देने का वादा, अच्छे दिन आने का वादा, बड़े-बड़े वादे करे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे ये वादे अब जनता की समझ में आने लगे हैं, इसी दौरान पिछले 9 वर्षों के अंदर जो कुछ हुआ ये 8 अगस्त को सीएजी रिपोर्ट में सामने आ गया जिसके अंदर एक 'आयुष्मान भारत' का, जिसका बड़े जोर-जोर से प्रचार चल रहा था और हमारे विपक्ष के साथी जोकि कल मणिपुर के ऊपर जब बात हुई तब भी भाग गये, जब उनको ये मालूम हो गया, जब उन्होंने देखा कि आज की चर्चा में सीएजी विषय है तो इसलिए उनको भागना ही था, इस बहाने से वो आज भी बाहर भाग चुके। और इस आयुष्मान का वो बड़ी जोरों से, बड़े जोर-जोर से कहा करते थे अक्सर विधान सभा में कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में ये आयुष्मान क्यों नहीं लागू करते है, तो मैं सोचता था पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज है जिसके लिए हमारे ये साथी इतना जोर देते है। लेकिन फिर मैंने गौर करा इस रिपोर्ट के आने के बाद कि ये लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल, 2018 से, तो मेरी समझ में आया, थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में दिल्ली की जनता से जो वादे करे थे कि मैं आपको बिजली माफ, बिजली हाफ, पानी माफ, और शिक्षा स्वास्थ्य के जो वादे करे थे जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उन वादों को पूरा करा, उसी दौरान ये योजना इस देश में आईं और इस योजना के

अंदर, अभी जैसे हमारे साथियों ने कहा, एक-एक नंबर पर साढ़े सात-सात लाख रजिस्ट्रेशन करे गये और ये ही नहीं मश्तकों के, 88,760 लोग जो इस इलाज के दौरान इसमें जिनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भुगतान कितने लोगों का करा गया, 2 लाख 14 हजार 923 लोगों का भुगतान होता है। और यहां पर, यहीं बस नहीं हुआ, यहीं बस नहीं चला, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में तो 25 अस्पताल ऐसे हैं कि जिनके अंदर उतने बेड भी नहीं, मशीनरी भी नहीं, उससे ज्यादा लोगों का वहां इलाज हो रहा है। ये एक इतना बड़ा घोटाला है अपने आप में जो देश को शर्मसार कर देने वाला वो घोटाला है कि मुर्दों के ऊपर भी कफन बेच खाया इन लोगों ने, मुर्दों का भी कफ़न बेच खाया। जो लोग मर गये उनके ऊपर भी इन्होंने घोटाला कर लिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री हाजी युनूसः बस कंक्लूड रहा हूं मैम थोड़ा सा। यहां तक कि 7 आधार कार्ड पर 4 हजार 761 रजिस्ट्रेशन हुए, चार आधार कार्ड पर मात्र 7 हजार। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहे थे कि हाजी साहब अगर किसी गरीब का कोई इलाज कराना हो, बड़े से बड़ा इलाज मैं करा दूंगा, मैंने कहा भई कैसे करा दोगे, ये 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे हज यात्रा पर जाने से पहले, मैंने कहा कैसे करा दोगे भाई, बोले बस हो जाएगा 50-60 हजार रुपये का खर्चा है, बड़े से बड़ा इलाज करा दूंगा।

अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तब मेरी समझ में आया कि वो 50-60 हजार रुपये में बड़े से बड़ा इलाज कैसे होता है देश के अंदर। ऐसे ही मेरे एक दोस्त की बहन जिनका नोएडा के एक बड़े मशहूर अस्पताल में इलाज चल रहा था उन्होंने कहा कि मेरी बहन का लगभग 75 हजार रुपये का बिल बना लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये 5 लाख रुपये के बिल पर साइन कर दो और हम आपका पैसा नहीं लेंगे। तब मेरी समझ में आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा देश के अंदर। आयुष्मान भारत के नाम पर किस तरह से मरीजों के नाम पर किस तरह से ये लूट हो रही है।

तो अध्यक्ष जी, मैं, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, एक किस्सा याद आ रहा है। पिछले विधान सभा इलेक्शन में, गुजरात इलेक्शन में माननीय गोपाल राय जी ने मेरी डयूटी लगाई, मैं इनके साथ था पिछले विधान सभा इलेक्शन में। तो मैं एक गांव में डोर टू डोर जा रहा था, वहां गया, बड़ी भीड़ लगी हुई थी, काफी लोग मौजूद थे, मैंने पूछा भई क्या हो गया, बोलेये एक अम्मा है बूढ़ी अम्मा इनका एक बेटा है, वो बेटा जो है हार गया, हम इनसे कह रहे हैं ये मानने को तैयार नहीं है। पहले कुछ लोगों ने आकर कहा, फिर कुछ लोग आये लेकिन वो अम्मा मानने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने भी वहां खड़े होकर उन लोगों से पूछा कि भई आखिर ये क्यों, तो वो अम्मा कहती हैं भैया सुन लो साफ, बात ये है कि एक तो मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, एक तो वो कुछ जानता नहीं और उसके

ऊपर किसी की मानता नहीं, उसे हराने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसे कौन हरा सकता है कि एक तो वो कुछ जानता नहीं, उस पर भी वो किसी की मानता नहीं। अब मैं अपने माननीय सांसद संजय सिंह जी के एक शेर के साथ जो आज के हालात जो देश में चल रहे हैं उसी के ऊपर एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं-

"वतन की हालत जो सुनाने लगेंगे,

अध्यक्षा महोदय,

वतन की हालत जो सुनाने लगेंगे,
तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे,
वतन की हालत जो सुनाने लगेंगे,
तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे,
अगर भीड़ में खो गई इंसानियत,
तो इसे ढूंढ़ने में जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे।'

धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे विपक्ष का आचरण बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या चाहते हैं? अभी सब के सब वॉक आउट करके गये हैं, वहां बैठकर प्रतीक्षा कक्ष से नाम भेज रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की चर्चा पर श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी

जी बोलेंगे और मोहन सिंह बिष्ट जी बोलेंगे। कहां खड़े होकर बोलेंगे, किसके समक्ष बोलेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इनका ये क्या चाहते हैं? ये इनके तरीके हैं। खैर। दुर्गेश पाठक जी।

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया आपने अभी सेंट्रल गवर्मेंट की कारगुजारियों के ऊपर कैग रिपोर्ट पर चर्चा करने का समय दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि बिना किसी पॉलिटिक्ल रेटोरिक के एक-एक लाईन बाई लाइन, एक-एक पेज वाइज पेज इस रिपोर्ट के ऊपर पढ़नी चाहिए और इस रिपोर्ट पर चर्चा भी करना चाहिए। और अगर इस देश के लोगों को लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई खामी है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे पहले कैग क्या है अगर कोई व्यक्ति ना समझे, ना जाने तो बाबा साहेब भीम राव अंबेडर के शब्दों में भारत का नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। यह वो व्यक्ति हैं जो देखता हैं संसद के अंदर मान्य खर्चे की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाये। एक तरीके से ये गवर्मेंट का पूरा का पूरा ऑडिट करता है और ये देखता हैं कि कहीं कोई खर्चा जो गवर्मेंट ने किया है उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं और उस गड़बड़ी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लेकर आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हम घोटाला भी कह सकते हैं, जिनको हम बड़े स्केल का करप्शन भी कह सकते हैं, ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहला प्वाइंट है रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27 अगर कोई साथी पढ़ना चाहे तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट भी अटैच है। रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सोने की सड़क की चर्चा होती है। कैग का रिपोर्ट कहता है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पर 29 किलोमीटर की सड़क बननी थी जिसके अंदर उसकी लागत थी 18 करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर 29 किलोमीटर की ये सड़क बननी थी 18 करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा तय किया गया लेकिन ढाई सौ करोड़ रूपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे खर्चे किए गए। जिस एक किलो मीटर सड़क पर 18 करोड़ रूपये खर्च करने थे उस पे ढाई सौ करोड़ रूपये खर्च किए गए। सबसे शानदार बात ये है कि इसकी पूरी की पूरी जो मोनिटरिंग जो इस पूरे प्रोजक्ट की निगरानी, मोनिटरिंग खर्चा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैबिनेट कमेटी ओन इकोनोमिक अफेयर्स की कमेटी देखती है जिसके प्रेसीडेंट खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की निगरानी में एक सड़क जो कि 29 किलोमीटर बननी थी जिसका रेट 18 करोड़ रूपये पर किलोमीटर था वो 250 करोड़ रूपये के हिसाब से बनी। आप तय कर लें इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है। प्वाइंट नंबर दो जिसको हम भ्रष्टाचार नंबर दो कह सकते हैं, घोटाला नंबर दो कह सकते हैं। रिपोर्ट नंबर 19 पेज 66 जब हम पढ़ते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर दो महत्वपूर्ण चीज हैं जो हमारे साथी ऋतुराज भाई ने भी डिसकस किया। भारत माला प्रोजेक्ट जिसके अंतगर्त भारत के

सभी पार्ट के अंदर एक सड़क निर्माण होनी है और ये लगभग 75 हजार किलोमीटर के आसपास ये सड़क का निर्माण होना है पर किलोमीटर जो खर्चा तय किया गया था वो था 15 करोड़ 37 लाख रूपये, 15 करोड़ 37 लाख रूपये तय किया गया था कि इसका पर किलोमीटर ये खर्चा होगा लेकिन जो खर्चा किया गया वो किया गया 32 करोड़ 17 लाख रूपये पर किलोमीटर, तो लगभग लगभग दो गुना खर्चा किया गया जहां पर 15 करोड़ रूपया खर्चा करना था वहां पे 32 करोड़ रूपये खर्चा गया, 75 हजार किलोमीटर ये सड़क थी तो अगर आप देखा जाए तो लगभग साढे सात लाख करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है, ये पूरा का पूरा साढे सात लाख करोड़ रूपये का घोटाला जो साथी थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें जो 2G spectrum की रिपोर्ट आई थी जिसके उपर पूरी की पूरी केन्द्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई, उसमें कैग की रिपोर्ट के हिसाब से एक लाख 76 हजार करोड़ रूपये का घोटाला था ये लगभग लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रूपये का घोटाला है। रिपोर्ट नंबर 19 है पेज नंबर 66 आप पढेगें तो आपको पता चल जाएगा साथ ही साथ इसमें पेज नंबर 27 में सेम रिपोर्ट में ये कहता है कि जब भी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बनाई जाती है तो एक सेफ्टी कनसल्टैंट का ऐपोइंटमेंट होता है जो एक तरीके से इस पूरे के पूरे रोड़ को देखता है कि ये सेफ है या नही सेफ है एक आडिट के रूप में उसकी भी एक भूमिका होती है मोनिटरिंग की। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सेफ्टी कसंल्टैंट का

कोई ऐपोइंटमेंट ही नहीं हुआ ये पेज नंबर 227 में है। ये भ्रष्टाचार नंबर दो है। भ्रष्टाचार नंबर तीन पे बातचीत करते हैं रिपोर्ट नंबर सात पेज नंबर 4 जो साथी पढ़ना चाहें इसके तहत आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोल होते हैं, टोल एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाते हैं और प्राइवेट कंपनीयां टोल इकटठा करके सरकार को उसका पैसा देती हैं। नेशनल हाइवे एथोरिटी ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि अगर मान लीजिए किसी भी टोल के उपर जो रोड, कनैक्टिंग रोड़ अगर वो रोड़ के उपर काम चल रहा है, रोड़ के उपर किसी तरह का कन्सट्रकशन का काम हो रहा है तो टोल की जो कॉस्ट है वो 75 परसेंट कम होनी चाहिए, सैवन्टी फाइव परसेंट माइनस होनी चाहिए। रिपोर्ट नंबर सात पेज नंबर 4 जब आप पढ़ते हैं तो कैग ने मात्र पांच टोल का आंकलन किया है और उसके हिसाब से कि 75 परसेंट जो कम होना चाहिए था, प्राइवेट कंपनियों को कम लेना चाहिए था, उन्होंने उस 75 परसेंट को कम ना ले के टोटल हंडरेड परसेंट लिया। पांच टोल में लगभग 132 करोड़ रूपये का घोटाला किया गया। अगर आप समझें, अपनी कॉमन सेंस लगाएं कि पूरे देश के अंदर ऐसे कितने टोल होंगे जहां पर इस तरह का कन्सट्रकशन हो रहा होगा जिसके रेट में 75 परसेंट की कमी होनी चाहिए थी लेकिन 75 परसेंट की कमी नहीं की गई सीधा सीधा प्राइवेट कंपनियों को फायदा दिया गया। मात्र 5 टोल में 132 करोड़ से ज्यादा रूपये का फायदा दिलाया गया। इसमें कितना सरकार को मिला हुआ है,

कितने मंत्री जी को मिला होगा, कितने अधिकारियों को मिला होगा उसका कैलकुलेशन आप कर लें। प्वाइंट नंबर फोर रिपोर्ट नंबर 11 पेज नंबर 19 जब आप पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री की 'आयुष्मान भारत' योजना की चर्चा ये रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट कहता है कि लगभग साढे सात लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन मात्र एक नंबर से किया गया और वो नंबर है 9999999999 इसी तरह से एक लाख 1.93 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग दो लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिसमें नंबर ऐड किया गया 8888888888 मतलब कोई नंबर ही नहीं था, फर्जी नंबरों से लगभग नौ लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनका बिल का पैसा निकाल लिया गया। इसी तरह से लगभग 88 हजार उन मरीजों का पैमेंट किया गया जिनकी मौत हो चुकी है, वो मृत्यु हो गई थी पैमेंट लिया और पैमेंट लेने के समय जिंदा हुए फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गईं तो 88 हजार ऐसे लोगों को केन्द्र सरकार ने पैमेंट दे दिया जिनकी मौत हो चुकी थी, फिर उनको जिंदा किया, जिंदा करके उनको पैसा उनके ऐकाउंट में डाला, फिर निकाला और फिर उनको मार दिया। लगभग 88 हजार लोग ऐसे हैं, प्वाइंट नंबर 4 रिपोर्ट नंबर 11 पेज नंबर 19 आप तय करें इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है, आप तय करें। अगला घोटाला नंबर पांच रिपोर्ट नंबर 17 पेज नंबर 52 और ये घोटाला किसी और से नहीं बल्कि खुद भगवान प्रभु राम की जो रामलला की जो एक पूरा का पूरा उनका मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसके उपर ये घोटाला किया गया है। इन्होंने बीस करोड़

रूपये एक ऐसे ठेकेदार को दे दिए जो कि ठेकेदार अयोग्य था उसको आप दे ही नहीं सकते थे जो कि ब्लैक लिस्टिड था, ऐसे ठेकेदार को बीस करोड़ रूपये का पैमेंट दे दिया इन्होंने। ये पांच प्वाइंट इस कैग ने पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट टेबल की गई है ये पांच प्वाइंट मैंने आपके सामने रखा। रोड़ 18 करोड़ में बननी थी ढाई सौ करोड़ में बनाई गई 29 किलोमीटर की ये रोड़ थी द्वारका एक्सप्रेस वे की इसी तरह से भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर जो 15 करोड़ में बननी थी 16 करोड़ में बननी थी उसको 32 करोड़ में बनाया गया मैंने आपको प्रॉपर रिपोर्ट पेज नंबर के हिसाब से दे दिया है। अब इस देश के लोगों को तय करना है किसमें भ्रष्टाचार है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कैग की रिपोर्ट में जब टूजी स्पैक्ट्रम की रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक लाख 76 हजार करोड़ रूपये का घोटाला है पूरा का पूरा देश सन्न था पूरा का पूरा देश पूरा का पूरा मीडिया इसके उपर चर्चा कर रहा था लेकिन आज मीडिया इतना ज्यादा डरा हुआ है। आज सारी संस्थाएं इतनी ज्यादा डरी हुई हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट है जिसमें 75 हजार किलोमीटर सड़क बननी थी 15 करोड़ रूपये लागत थी 32 करोड़ में बनाया गया रिपोर्ट नंबर 19 और लगभग साढे सात लाख करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक, हर सांसद, हर काउंसलर, हर कार्यकर्ता और हरेक सपोरटर से कहूंगा कि आपको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी, फिर आपको तय करना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं या नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

माननीया अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी। (अनुपस्थित) अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमानः धन्यवाद अध्यक्षा महोदया। अध्यक्षा महोदया मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं।..

माननीया अध्यक्षः समय का ध्यान रखें।

श्री अब्दुल रहमानः हां, बस पांच से छह मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात।

माननीया अध्यक्षः पांच ही मिनट हैं आपके पास।

श्री अब्दुल रहमानः ठीक है।

माननीया अध्यक्षः विषय पर रहिए।

श्री अब्दुल रहमानः जी विषय पर ही सुनाना चाहता हूं। एक भारत देश से एक कद किसी विदेश में गया वहां विदेश के कुछ मंत्री गण हमारे कद को लेकर के और अपनी कुछ बनाई हुई सड़कें, कुछ बिल्डिंगस, कुछ फलाई ओवर्स दिखाने के लिए गए और कहा के देखो हमने ये फलाई ओवर बनाया है और इसकी लागत जो है वो 200 करोड़ रूपये आई है उन्होंने कहा भई इतना बड़ा फलाई ओवर और सिर्फ 200 करोड़ में कैसे बना! उन्होंने कहा भई आपके सामने है 98 परसेंट उधर और 2 परसेंट इधर, उन्होंने कहा भई बहुत बढ़िया बना। फिर वो ले गये कोई बहुत बड़ी सड़क दिखाने के लिए हाईवे पर उन्होंने दिखाया कि भई ये

हमने रोड़ बनाया है, तो उन्होंने कहा भई कैसे बना उन्होंने कहा भई हमने जो है ये दस करोड़ रूपया पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया है। उसने कहा भई इतना सस्ता कैसे बना दिया उन्होंने कहा हंडरेड परसेंट उधर ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाईं कुछ दिन बाद वो कद इंडिया आ गया जब वो भारत सरकार के पास आ गया तो भारत सरकार के भी कुछ मंत्री-गण उन्हें घुमाने के लिए ले गए और ले जाने के बाद वो सबसे पहले द्वारका पहुंचे और जब वो द्वारका पहुंचे तो द्वारका में उन्हें एक सड़क दिखाई गई और दिखाने के बाद उनसे कहा गया कि देखो हमने ये 29 किलोमीटर का एक सड़क बनाई है और बहुत शानदार उन्होंने कहा बहुत अच्छी सड़क है। कैसे बनाई ये बताओ? इन्होंने कहा 251 करोड़ रूपया प्रति किलोमीटर। उन्होंने कहा ऐं कैसे बनी, इतना पैसा! उन्होंने कहा 93 परसेंट इधर और 7 परसेंट उधार। उन्होंने कहा फिर बन सकती है, फिर बन सकती है जब 93 परसेंट पाकिट में होगा तो 7 परसेंट तो ठीक है फिर तो बन सकती है। इसी तरह से फिर वो ले गए साहब अपना हाइवे दिखाने के भारत माला एक हमने 75 हजार किलोमीटर की सड़क बनाई है, उन्होंने कहा चलो भईं ले जाने के बाद अब उन्होंने दिखाया कि और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ एक द्वारका एक्सप्रेस वे पर ही 72 हजार उनासी 790 करोड़ रूपये का घोटाला बना है, सिर्फ इस पर ही जो 18 करोड़ रूप्या प्रति किलोमीटर बननी थी और वो 251 करोड़ रूपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनी। इसके बाद वो

भारत माला की दिखाने ले गए और भारत माला जो है जो 15 करोड़ 37 लाख रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बननी थी वो सड़क बनी 32 करोड़ 37 लाख रूपये प्रति किलो मीटर के हिसाब से, अब इसके घोटाले को जोड़ें तो मैं कैलकुलेट कर रहा था लेकिन मेरा कैलकुलेटर ही फैल हो गया उसमें आता ही नहीं। अब मैंने बहुत दिमाग लगाया मैडम, अब इतना पैसा ना कभी सुना ना कभी देखा, तो पता नहीं चला। बहरहाल उस कद को जब बताया तो वो कद बेहोश हो के गिर गया, वो बेहोश हो के गिर गया, के ये है भारत। उसने कहा वाकई में महान है भारत, महान है भारत और मैडम हद तो तब हुई के जब 'आयुष्मान भारत' में अभी मेरे कई सम्मानित साथियों ने बताया लेकिन इसमें कमाल की बात ये थी कि साढ़े सात लाख लोगों का एक ही नंबर पर रजिस्ट्रेशन हुआ 84 या 88 हजार लोगों का इलाज उनका हो गया जो मृत लोग थे, लेकिन ये तो अजूबा ही हो गया भारत के अंदर के ऐसे लोगों का भी हम इलाज करने लगे, तो अमरीका, चाइना ये जितने स्मृद्व देश हैं ये तो सब बेकार अपना नाम लिए हुए हैं। आज इन देशों को हमसे सीखना चाहिए। आज जितने मुल्क हैं आज उनको भारत आना चाहिए जहां वो सीख सकते हैं कि मृत लोगों का भी हम इलाज कर सकते हैं।

जो किसी ने नहीं किया वो हमने करके दिखा दिया और मैडम एक बात सीएजी की रिपोर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय

से एक पेंशन जाती है वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधावा पेंशन और मैडम काफी दिनों से उन ग्रामीणों को पेंशन नहीं मिली, वो बेचारे जगह जगह शिकायत कर रहे थे कि भई पेंशन नहीं आ रही। तो सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि उनको वो पेंशन इसलिये नहीं आ रही थी कि ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के होर्डिंग, पोस्टरों पर वो पेंशन का पैसा भारत के प्रधानमंत्री ने वहां खर्च कर दिया। सिर्फ अपने पोस्टर होर्डिंग लगवाने के लिये उन गरीबों का पैसा वहां लगा दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बुरा नहीं है भारत और प्रधानमंत्री भी बुरे नहीं हैं। सही मायनों में हमें सीखना चाहिये कि हमारे देश के इतने महान प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है जहां मृत लोगों का इलाज होता हो, जहां पेंशन से पोस्टर लगवा लिये जाते हों, जहां कफन खसोट करके पैसा कमाया जाता हो। तो मैडम मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे उसकी और इतनी मगरूरियत और इतना घमंड होना देश के अंदर कोई भी आदमी अमृत पीकर नहीं आया है यहां। इस दुनिया में सदा कोई नहीं रहा, सबको जाना है और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि-

मगरूर दरख्तों को आंधियां उखाड़ देती हैं

मगरूर दरख्तों को आंधियां उखाड़ देती हैं

महफूज़ वो रहता है जो पेड़ लचक जाता है

बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी, समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्षा जी आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। जो लोग कहा करते थे देश में कि 'बहुत हुआ भ्रष्टाचार अबकी बार मोदी सरकार'। अब उन्हीं की सरकार की सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है अध्यक्षा महोदया जिसमें कहा गया कि भगवान राम की कसम खाने वाले लोगों ने भगवान राम के नाम पर चल रहे प्रोजेक्ट में दलाली खाने का काम कर लिया। अध्यक्षा महोदया, ये प्रोजेक्ट अयोध्या डवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इनका गुप्तार घाट है जहां पे 14 स्थानों पे काम होना था। इन 14 स्थानों पे अलग अलग जगहों पे काम होना था, 127 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो 6 राज्यों में होना था इसमें ऐसी ऐसी अनूठी करामात हुई है कि रोज प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, अभी लाल किले पे भी भाषण दे रहे थे कि 'भ्रष्टाचार मुक्त' भारत चाहिये। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात, झूठी बात करने वाले लोग भारत को भ्रष्टाचार युक्त बना रहे हैं इसका खुलासा सीएजी ने कर दिया। जब संसद में रिपोर्ट पेश हुई तो बताया गया कि 19 करोड़ 73 लाख रूपये का अनुचित लाभ डबल इंजन की सरकार में ठेकेदारों को देने का काम किया। यानि कि अब देश को पता चल गया कि अब मोदी जी के राज में एक ऐसा वाशिंग मशीन बन गया है, एक ऐसा डिटरजेंट पाउडर बन गया है जिसका नाम आजकल लोग बड़े चर्चे

में हैं 'मोदी डिटरजेंट पाउडर'। उस पाउडर से धुलाई करने के बाद यानि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, उन पर सारे दाग छूट जाते हैं। अजीत पवार एक महीने पहले भ्रष्टाचार युक्त थे मोदी डिटरजेंट पाउडर लगा, एक महीने बाद भ्रष्टाचार मुक्त हो गये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये। तमाम ऐसे हैं आसाम से लेकर के बंगाल तक, महाराष्ट्र तक शिंदे जी तक। सब लोग एक साल पहले तक भ्रष्टाचार युक्त थे, कमाल का डिटरजेंट पाउडर बनाया है, लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भी हो रहे हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से भगवान राम के नाम पर दलाली खाई गयी। तो भगवान राम से सिया माता ने पूछा कि ये क्या चल रहा है अयोध्या जैसी जगह पर जिसके नाम पर वोट मांगते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं वहां पर घोटाला कर रहे हैं लोग। तो एक बहुत चर्चित लाईन है कि-

"राम चंद्र कह गये सिया से ऐसा मोदी युग आयेगा

राम चंद्र कह गये सिया से ऐसा मोदी युग आयेगा

हंस चुगेगा दाना दुनका अडानी और पीएम के दोस्त मिलकर के मोती खायेगा,

पीएम का दोस्त अडानी देश का मोती खायेगा।"

उसके बाद सिया माता ने कहा कि भगवन ये बताईये कि क्या मोदी राज में धर्म और कर्म नहीं रह जायेगा क्या? तो भगवान राम

ने माता सीता से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि धर्म कर्म तो होगा, हे सिया धर्म कर्म तो होगा लेकिन मोदी राज में शर्म नहीं होगा, केवल शर्म नहीं होगा और दूसरों पर आरोप लगाने का काम होगा। ये ऐसा एक चरित्र लेकर आये हुए हैं, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ अध्यक्षा महोदया मैं दो लाईन में बताकर के बात खत्म करूंगा कि इसमें न केवल कामों में भ्रष्टाचार हुआ बल्कि जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गये थे उनको जीएसटी का कोई भी जो है वापसी नहीं मिलना चाहिये था, उनको भी 19 लाख 57 हजार करोड़ रूपये का जीएसटी का भुगतान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में यहीं नहीं रूकी, भगवान राम के प्रोजेक्ट में उन्होंने जो ठेकेदार जीएसटी कभी भरे नहीं थे, उनको भी जीएसटी एडवांस में दे दिया गया, ये काम किया गया है। और इतना ही नहीं रूके। ये तो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी करके दिखाते हैं। तो ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं। उन्होंने जो काम कभी किसी ठेकेदार ने किया ही नहीं, बिना काम किये ठेकेदारों को पैसा दे दिया गया ये मोदी जी के राज में ही हो सकता है और किसी के राज में नहीं हो सकता, ये कीर्तिमान निश्चित रूप से उन्होंने स्थापित किया और इसी को कहते हैं अध्यक्षा 'जी अंधोर नगरी चौपट राजा'। 'न खायेंगे न खाने देंगे' का नारा देने वाले लोग पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं।..

माननीया अध्यक्षः कंपलीट कीजिये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः देश में एक भी संस्थान न बनाने वाले लोग आज देश का एयरपोर्ट बेच रहे हैं, देश का रेलवे बेच रहे हैं, देश का सी पोर्ट बेच रहे हैं, देश का कोयला बेच रहे हैं और केवल और केवल एक आदमी को पूरे देश का ठेका मिलने का काम हो रहा है ये भी अध्यक्षा महोदया सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट के संदर्भ में खुलासा किया है। जो सड़क द्वारका में 18 करोड़ रूपये पर किलोमीटर में बननी थी उसको ढाई सौ करोड़ रूपया पर किलोमीटर कर दिया गया। ये तो पूरा देश देख रहा है जो कहीं नहीं हुआ..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः वो मोदी राज में मुमकिन है। अब पूरा देश भ्रष्टाचार पर केवल नौटंकी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आज कहने के लिये खड़ी हो गयी है कि अब आप लोग भ्रष्टाचार की बात मत करो, भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे रिकार्ड मोदी जी की सरकार में टूट चुके हैं। आजादी के बाद देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार इस भ्रष्टाचार और इतना आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गयी है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले लोग भारत को भ्रष्टाचार युक्त बना दिये हैं इसका खुलासा सीएजी ने कर दिया है।..

माननीया अध्यक्षः चलिये धन्यवाद।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अब प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिये पूरे देश से और 2024 में विदाई की तैयारी कर लेनी चाहिये, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीएजी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने डिटरजेंट पाउडर को, जो फैल डिटरजेंट पाउडर था, उसको फैल साबित कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री इमरान हुसैन जी।

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री (श्री इमरान हुसैन): माननीय अध्यक्षा महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण..

माननीया अध्यक्षः मंत्री जी, मंत्री जी माफी चाहती हूं। विपक्ष को ये सदन कोई गार्डन, कोई पार्क, कोई कैफे लगता है कि जब किसी भी टॉपिक की शुरूआत होती है, बिना टॉपिक को सुने, बिना चर्चा का विषय जाने शोर मचा के आप चले जायेंगे, फिर आपका मन करेगा आप आ जायेंगे, फिर जिद करेंगे कि मुझे बुलवाओ, मुझे बुलवाओ। जब आप..

...व्यवधान..

माननीया अध्यक्षः नहीं, आप गये नहीं? जब मैंने ये चर्चा का विषय प्रारंभ करा आप सब लोग खूब हंगामा काट कर, खूब शोर करके बार-बार मेरे समझाने के बावजूद आप गये,

...व्यवधान..

माननीया अध्यक्ष: आप गये न। पहले तो आप सब लोग बोल लीजिये।

...व्यवधान..

माननीया अध्यक्ष: नहीं ये कोई तरीका नहीं है मैंने आपसे तब निवेदन किया था, मैंने आपसे तब निवेदन किया था कि आप बैठ जाईये बिधूड़ी साहब आपको मौका मिलेगा लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं माने।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: नहीं अब मैं इस चर्चा पर तो मैं आपको मौका नहीं देने वाली क्यूंकि आप खुद गये थे। निवेदन करने के बावजूद गये थे, मंत्री जी बोलें।

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: माननीय अध्यक्षा महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का मौका दिया..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: विपक्ष को बोलने का मौका लगातार दिया है। मंत्री जी।

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: इसके लिये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी है, हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि 'न खाउंगा न खाने दूंगा' जबकि हकीकत ये है कि द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में मूल लागत से 15 गुना अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। तो इन घोटालों का पैसा कौन खा रहा है? ये बड़े अफसोस और चिंता की बात है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करते हैं और वहीं भारत सरकार की एजेंसियां सरकारी धान का दुरूपयोग करती हैं और खुलेआम इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल में ही भारत सरकार की ऑडिट एजेंसी सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेस वे एनएचएआई द्वारा बहुत ही महंगी दरों पर बन रही सड़क पर ध्यान आकर्षित कराया है।

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: ये बताया गया कि कैबिनेट ने 18 करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेस वे सड़क बनाने का अप्रूवल दिया था और वो ही सड़क..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मंत्री जी आप चालू रखें, कंटिन्यू रखें।

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: वो ही सड़क आज उससे 15 गुना ज्यादा खर्च कर कर बिना कैबिनेट की अप्रूवल लिये 251 करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाई जा रही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मंत्री जी चालू रखें।

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो..

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में कम समय में और अप्रूवल से कम लागत पर जनता के लिये काम कर रही है। कोई भी प्रोजेक्ट कई पुल बनें यहां पर कई, वो लागत से कम में बनें। किसी पुल में 100 करोड़ रूपये बचाये गये, किसी में डेढ सौ करोड़ रूपये बचाये गये और वो पैसा जनकल्याण नीतियों में लगाया गया। और एक तरफ केंद्र की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जिसमें 15 करोड़ रूपये किलोमीटर की लागत का पुल 251 करोड़ में बनाया जा रहा है। अभी हमारे विपक्ष के साथी यहां सब खड़े हैं..

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई अफसरों पर सीएजी ने पैसों के खर्च को लेकर दिल्ली सरकार की बहुत प्रशंसा की है तो वहीं इस फ्लाई ओवर के निर्माण में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। ये भी स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारों के मामलों में पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें देश में आई हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया है।

...व्यवधान...

माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री: इसका अंदाजा सीएजी का 'आयुष्मान भारत' स्कीम में बताई गयी अनियममितताओं से सिद्ध होता है। आयुष्मान भारत में अभी हमारे साथियों ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट है कि 7 लाख लोगों का एक ही अकाउंट नंबर से इलाज करा दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और इसके साथ साथ 83 हजार मृत लोगों का ईलाज करा कर पैसा निकाल लिया जाता है। इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। मेरा आपके माध्यम से अध्यक्षा महोदया मेरा आपके माध्यम से ये अपील है कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में या हाई कोर्ट की अध्यक्षता में सीनियर जजों की निगरानी के अंदर इस घोटाले की जांच कराई जाये और जो भी इसमें दोषी हैं उसको सजा दी जाये और देश की जनता के सामने केंद्र सरकार के घोटालों की सच्चाई सामने आनी चाहिये। जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः सदन की कार्यवाही दोपहर भोजन के बाद ढाई बजे दोबारा शुरू करी जायेगी, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गईं)

सदन अपराहन् 2.35 बजे पुनः समवेत् हुआ।

माननीया अध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं।

माननीया अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्षा जी आपने जिस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है, आज जो भारत के सामने अर्थव्यवस्था की हालत पहुंच गई है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना मुश्किल हो गया है दो टाइम का खाना जुटाना, रोटी जुटाना कि मुझे लगता है कि पहले तो कहते थे कि गरीब लोग परेशान है लेकिन अब तो जो मिडल क्लास है, वही इंडिया के अंदर इतना परेशान है कि पूछो मत। और मिडल क्लास तो छोड़ो अब तो आज रोज अखबारों में पढ़ ही रहे हैं कि जो हाईएस्ट इन्कम ग्रूप के लोग हैं, वो भी इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। सबके अलग-अलग कारण हैं, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है जुलाई के अंदर जो रिटेल इन्फलेशन की। अगर आप देखें तो सारे रिकोर्ड को तोड़ चुकी है। इतना बुरा हाल के एक आम आदमी जिसको ये सब

समझ में भी नहीं आता है कि इन्फलेशन क्या होती है, कैसे इन चीजों को नापा जाता है लेकिन वो इस बात को लेकर जरूर परेशान है कि कल तक जो काम 5 हजार में हो जाता था, अब उसके 6 हजार हो गए और वो बढ़ते ही चले जा रहे है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंफलेशन ने अपने सारे रिकोर्डस को तोड़ा। लेकिन एक जो अच्छी बात है, जिसके लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, वो ये है कि उस सबके बावजूद दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जिसकी वजह से अकेला राज्य जिसकी इंफलेशन दर पूरे भारत में सबसे कम है। इसमें 22 स्टेटस को अगर देखा जाए तो 14 तो ऐसी है जिनकी इंफलेशन रेट 7 परसैंट से भी ज्यादा है और जो बाकी 8 बचे, उसमें भी जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सबसे कम है। राजस्थान में ये ओवरऑल सबसे ज्यादा है जो दिल्ली के साथ लगा हुआ है। अर्बन एरियाज के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंफलेशन रेट उत्तराखंड की है, जो की 10.5 परसैंट है, राजस्थान में 10.4, उड़ीसा में 9.9 और दिल्ली में कितनी है, मात्र 3.7 परसैंट, सबसे कम। बड़ी मजेदार बात है कि मैं पढ़ रहा था कि एक्सपर्टस का इस पर क्या कहना है। टीवी पर भी डिबेटस होती हैं, वैसे तो आपने देखा है कि डिबेटस आज कल जिन मुद्दों पर होती है, उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है लेकिन फिर भी दो–चार चैनलों ने जो दिखाया, जो आज कल यूटूबस चैनल बने हुए हैं, उनके ऊपर मैंने देखा। तो एक्सपर्टस का

कहना था कि ज्यादातर वजह ये है कि सब्जियों के और दालों के रेट बढ़े हैं और उन राज्यों में इंफलेशन रेट ज्यादा है जहां सब्जियॉं पैदा नहीं हो रही। अब बड़े कमाल की बात है। दिल्ली के अंदर खेती–बाड़ी होती है लेकिन बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित। अब टमाटर दिल्ली में कितने होते होंगे। लेकिन दिल्ली में फिर भी सबसे कम है और राजस्थान जैसे बड़े राज्य के अंदर, उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जहां खेती पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, उड़ीसा में, ऐसी जगहों पर इंफलेशन रेट बढ़ रही है। इसके साथ में एक बहुत गौर देने वाली चीज है कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है, वहां की मिनिमम वेजिज बहुत कम है जबकि दिल्ली की मिनिमम वेजिज पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये बैलेंस आप देखिए कि दिल्ली में जो अनस्किल लेबर भी है, वो 16 हजार रुपए कमा रहा है, मिनिमम वेज है उसकी। जो सेमी स्किल्ड है वो 18 हजार कमाता है, साथ में उसको बिजली का फायदा भी मिलता है, जो 200 यूनिट फ्री और 400 हाफ पे है। साथ में उसे पानी का भी फायदा मिलता है 20 हजार लीटर का, साथ में अगर वो महिला है तो बस की यात्रा फ्री है। ये सारे फायदे वो ले रहा है, माता जी, पिता जी को तीर्थ यात्रा को वो फ्री में भेज रहा है। इन्कम बढ़ रही है और खर्चा सबसे कम, क्योंकि इंफलेशन दिल्ली में सबसे कम है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे दिल्ली के नागरिकों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार तीन बार अरविंद केजरीवाल जैसे

पढ़े-लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जिन्होंने चाहे पूरे हिन्दुस्तान के अंदर इंफलेशन बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों को राहत दी, उनकी जेब में कुछ पैसे डाले, वो उस इकोनोमी में उस पैसे से चला रहे हैं, देश को फायदा हो रहा है, दिल्ली को फायदा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पर पूरे देश में, हर राज्य के अंदर लोग ऐसी सरकार को चुनेंगे जो बेवजह के मुद्‌दों की बात ना करके ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना चाहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहेंगे जो उनको कुछ राहत दे, उनकी इकोनोमी में कुछ फायदा दे, देश को आगे बढ़ाए, आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। विनय मिश्रा जी, (अनुपस्थित), अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्षा जी आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तीन बार जीतकर आई और तीनों बार पूरे देश की जितनी भी महंगाई दर थी उससे दिल्ली की महंगाई दर, जब से अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से कम होनी शुरू हो गई है। और आज पूरे देश में महंगाई दर 10 परसैंट से भी ज्यादा है और जहां-जहां बीजेपी के राज्य हैं, वहां आप हरियाणा को देख लीजिए 8.38 परसैंट महंगाई दर, यूपी में 9.6, उत्तराखंड में 10.5, पूरे देश के अंदर जहां-जहां बीजेपी की सरकार है महंगाई

बढ़ती जा रही है और एक तरफ अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, यहां पर महंगाई दर कम होती जा रही है और 3.9 परसैंट जो बहुत ही कम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी, दिल्ली देश की राजधानी है और यहां कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिल्ली उत्पादन नहीं करती, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर महंगाई दर इतनी कम रखी गई है, माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी और उनकी सरकार बधाई के पात्र हैं और ये हुआ कैसे, इसके पीछे वजह क्या हुई? क्योंकि दिल्ली का जितना भी टैक्स का पैसा है मुख्यमंत्री साहब ने उसको दिल्ली की जनता पर लगाया है, दिल्ली के लिए बिजली फ्री की, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा, दिल्ली के लोगों के लिए पानी फ्री किया, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा, दिल्ली के बच्चों के स्कूल अच्छे किए, पहले एडमिशन हुआ करते थे 60 परसेंट, आज 40 परसैंटऔर बढ़ गए हैं। वहां प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजने कम हुए, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। महिलाओं के लिए बस फ्री हुई, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। मोहल्ला क्लीनिक खुले, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा और इसी सब क्रम में दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो भी बचा और दिल्ली की जो महंगाई दर है वो भी बची। इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें जो भी सैंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, आटा हर साल 15 परसैंट की दर से बढ़ रहा है, आलू–प्याज 10 प्रसेंट–15 परसैंट की दर से और टमाटर ने तो रिकोर्ड ही तोड़

दिया। एक समय ऐसा था 20 रुपए किलो टमाटर और अभी थोड़े दिन, तीन-चार दिन पहले तक 300 रुपए किलो टमाटर, 300 रुपए।..

माननीया अध्यक्षः चलिए कंप्लीट कीजिए।

श्री अजय दत्तः कुछ लोग तो टमाटर को सिर्फ देखकर ही उसका स्वाद ले लेते थे। तो ये हुआ, इस वजह से क्योंकि इस देश की सरकारें जो काम कर रही है उससे देश के लोगों को कोई लेना-देना नहीं है, उनकी महंगाई को कम करने से कोई लेना-देना नहीं है। उनका तो एकमात्र एजेंड़ा है कि देश के अंदर किसी भी तरीके से वो जीतकर आ जाएं। लोगों के अंदर किसी भी तरीके से फूट डाल दें, लोगों के अंदर किसी भी तरीके से, इस तरीके की भावनाएं क्रिएट कर दें कि बस उनको वोट मिलें। तो ये वोट की राजनीति है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी काम की राजनीति करते हैं।..

माननीया अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः और ये केंद्र सरकार के लिए किसी ने कहा है:

'आलू खा गए, अदरक खा गए, खा गए वो तो टमाटर,

एक बड़ी सड़क खा गए और तेल पी गए घर जाकर।'..

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः तो ये बीजेपी ने जो कम्बल ओढ़कर तेल पिया है और लोगों का जो पैसा खाया है, ये इसीलिए पूरे देश में महंगाई दर बढ़ी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी की सरकार है..

माननीया अध्यक्षः बहुत वक्ता हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।

माननीया अध्यक्षः देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन से चार लाइनों से ज्यादा ना बोलें आगे भी बहुत सारे विषय हैं, महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्षा जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा हूं कि जब से पैदा हुए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर या पूरे लोगों से आज तक एक ही बात सुनते रहते हैं, यदि कोई राज सबसे बढ़िया हुआ था तो वो राम राज्य हुआ था। आज दिल्ली के अंदर भी मैं वही महसूस कर रहा हूं, उसी राम राज्य की कल्पना कर रहा हूं। क्योंकि रामजी का उद्देश्य एक ही था कि उसके राज्य के अंदर उसके बच्चे शिक्षित हों। उसके राज्य के अंदर हर रहने वाला नागरिक स्वस्थ्य रहना चाहिए। हर नागरिक के लिए पीने का पानी मिलना चाहिए। माताओं को, बहनों को, बेटियो को सम्मान मिलना चाहिए। उसी तर्ज के ऊपर

दिल्ली के अंदर यदि ये काम कर रहे हैं तो वो अरविन्द केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में, दिल्ली के अंदर लगातार तीन बार सरकार बनाकर इस काम को चरितार्थ किया है। उन्होंने वायदा किया था कि मैं दिल्ली के लोगों को पीने के लिए फ्री में पानी दूंगा। अपनी लगातार सफलतापूर्वक परिस्थितियों के अंदर रहते हुए भी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए पीने के लिए पानी हर घर को दिया, ये राम राज्य की कल्पना के अनुसार ही है। राम तो वो नहीं बन सकते लेकिन राम के सेवक हनुमान के दूत के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर यह काम करके दिखाया तो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया और हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी दिया। राम जी की कल्पना थी कि उनके राज्य के अंदर सभी स्वस्थ्य हों उसी के तहत दिल्ली के अंदर अपने सभी हास्पिटलों को चुस्त और दुरुस्त किया और उनके अंदर दवाईयां मुफ्त में देने का काम किया। महंगे से महंगा टैस्ट भी उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्री करवाया। जगह-जगह मोहल्ला क्लीनिक खोले ताकी लोगों को दूर न जाना पड़े, कोई इलाज से वंचित न रहे लेकिन केन्द्र के अंदर बैठी हुई सरकार इतनी निर्दयी है कि उन मोहल्ला क्लीनिकों को भी वो बंद करवाने के लिए लगी हुई है लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मिट्टी के बने हुए हैं कि किसी भी प्रकार से उनको बंद नहीं होने दे रहे।..

माननीया अध्यक्षः कंप्लीट कीजिए।

श्री महेंद्र गोयलः कंप्लीट तो 2024 के अंदर जनता ही कर देगी, जनता जल्दी से कंप्लीट करने वाली है इसमें तो कोई दो राय नहीं है।

माननीया अध्यक्षः किसको?

श्री महेंद्र गोयलः आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यदि कहीं पर नाम लिया जाता है पहले कहते थे शिक्षा के बारे में कहीं पर बात करनी है तो फिनलैंड वालों से करो, इंगलैंड वालों से करो, अमरीका वालों से सीखो, आज अमरीका वाले कहते हैं यदि शिक्षा की नीति के उपर बात करनी है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो ये बात की जाती है शिक्षा के उपर। दिल्ली के मुख्य मंत्री आज हर बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के उपर लगाम लगाई है उन्होंने, उनकी फीस आज तक बढ़ने नहीं दी गई है, ये होता है एक नीति के तहत काम करने का। दिल्ली के लोगों का खर्च आज इसी वजह से कम है कि आज प्राइवेट स्कूल से भी नाम कटवाकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर एडमीशन लेने के लिए आज लाइन लगी रहती है। मैं जिस समय में विधायक बना था बहुत से लोग आते थे उस समय में विधायक जी मेरे बच्चे का एडमीशन करवा दो, मैंने कहा हां भई करवा देंगे कौन से स्कूल में करवाना है, मेरे को यह था कि सरकारी स्कूल के लिए आए होंगे, प्राइवेट स्कूलों का नाम लेते थे और प्राइवेट स्कूल के अंदर हम फोन करते थे तो वहां पर डोनेशन के नाम पर उस समय में पैसा लिया जाता था लेकिन.. हां

बिल्कुल, गुलाब भाई के भी, अमानत भाई के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे भी छोटे–छोटे स्कूलों के अंदर ही पढ़े हैं। हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर में पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के बहुत से ऐसे अमीर घरानों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा लेने के लिए तत्पर हैं और आफिसों के बाहर लाइन लगी रहती है। राम जी का एक ही था कि बुजुर्गो को तीर्थयात्रा करवाई जाए, उसी के तहत दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का कोई भी बुजुर्ग होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि श्रवण कुमार के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल उनके बेटे के रूप के अंदर उनको तीर्थयात्राएं करवाता है, ये होता है एक राम राज्य की कल्पना करना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्य मंत्री साहब का कि वो ऐसी–ऐसी पॉलीसियां लेकर आए जिसके तहत लोगों का खर्च कम हो रहा है। आज सुबह मैं जब आ रहा था तो एक माई मिल गई क्योंकि सुबह–सुबह घर पर बहुत व्यक्ति आ जाते हैं तो कल के अखबार के अनुसार उसके बेटे ने बताया होगा कि दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है, तो वो अम्मा बोली केजरीवाल ने जाके मेरा भी आशीष दियो कि इसी तरह से बना रहे और दिल्ली के लिए नहीं देश के लिए भी काम करे, ऐसा मतलब उन्होंने आशीष दिया है। जिस समय में बिधूड़ी साहब और भाजपा के अन्य नेता बाहर गये थे, हम बाहर ही बैठे थे, हमारे साथी भी वहीं पर बैठे थे उन्होंने भी कहा धन्यवाद प्रस्ताव आएगा लेकिन दिल से कह रहे हैं हम

भी अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली के अंदर महंगाई रेट तो कम है, यही कहा था न, मदनलाल जी, यही कहा था न। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, चाहे बिष्ट साहब हैं या बिधूड़ी साहब हैं कम से कम वो सदन के अंदर नहीं लेकिन सदन के बाहर तो सच बोलने की हिम्मत दिखाईं तो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद उनकी तरफ से भी है।..

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद तो पूरी जनता कर रही है।

माननीया अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये, अल्पकालिक चर्चा नियम-55 के तहत।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये-बैठिये। समय की बहुत कमी है विषय बहुत सारे हैं अल्पकालिक चर्चा नियम-55 के तहत.. श्री संजीव झा जी निर्वाचित दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने में केन्द्र सरकार का अलोकतांत्रिक कदम और संवैधानिक प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरी तरह उल्लंघन के संबंध में चर्चा को प्रारंभ करेंगे।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, कि आज आपने,..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: शुरू कीजिए संजीव झा जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री संजीव झा: आज आपने वो काले कानून जो संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास कराया आज वो कानून कैसे अनडेमोक्रेटिक है, इसकी चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये unconstitutional या undemocratic काम इसलिए करने पर मजबूर हुए क्योंकि 2013 में आंदोलन से आई हुई पार्टी की सरकार बनी और जब 2013 में सरकार बनी तो पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि कोई पार्टी अगर दिल्ली की या देश की जनता से जो वायदा करे वो वायदा पहले दिन से उस पर काम करना शुरु कर दे, नहीं तो होता यही रहा था कि मेनिफेस्टो केवल चुनाव के पहले बनता था बाद में कोई उसको देखता नहीं था। इसकी परंपरा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की कि अगर कहा की हम बिजली आधी करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे तो 48 घंटे के अंदर 104 डिग्री फीवर हुआ था उनको, उस टाइम, 104 डिग्री फीवर होने के बावजूद दिल्ली की जनता को किये गये वायदे को पूरा किया। 49 दिन की सरकार थी उस 49 दिन की सरकार में

पहली बार दिल्ली की जनता को लगा की कोई सरकार आम आदमी या आम आदमी के किसी काम को सरकारी अधिकारी या सरकारी अफसर जाए तो हो पाएगा और 49 दिन के उस टेलर का परिणाम यह हुआ कि 2015 का जब चुनाव हो रहा था तो 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक इतिहास बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 53 परसेंट से ज्यादा मत मिले। मुझे याद है जिस दिन 2015 में रिजल्ट आया था उसी दिन अमित शाह जी के बेटे की शादी थी। 2015 के रिजल्ट के कारण अमित शाह जी के बेटे की शादी में बैंड नहीं बजा था क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनका बैंड बजाया था। बस कहानी यहीं से शुरु हुई कि समुंदर को इतनी सी बात बस खल गई कि मेरे उपर कागज की छोटी सी नाव कैसे चल गईं उसके बाद से साजिश शुरु हुईं इसी सदन में मई 2015 में एक इल्लीगल चिट्ठी आई थी और कहा था कि सर्विसेज अब दिल्ली सरकार का विषय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में 66 एंटरीज हैं इन 66 एंटरीज में 3 एंटरी 1, 2, 18 यानी लैंड, पुलिस, पब्लिक आर्डर ये तीन एंटरी को छोड़कर बाकी जितनी भी एंटरीज हैं ये सारे टरांसफर्ड सब्जेक्ट हैं लेकिन एंटरी-41 जो सर्विसेज की बात थी उन्होंने कहा कि अब एंटरी-41 भी एंटरी 1, 2, 18 के साथ होगा इस बात को लेकर हम लोग कोर्ट गये, कोर्ट में यह मसला चलता रहा लेकिन सर्विसेज के लेने के बावजूद इनको लगा कि सर्विसेज ले लेंगे तो काम कैसे होगा, अधिकारी हमारे पास

रहेगा, हम काम नहीं करने देंगे। काम की गति धीरे जरूर हुई लेकिन काम को रोक नहीं पाए। फिर एक-एक कर जितनी एजेंसीज दिल्ली सरकार के पास थी चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो रहा हो, चाहे सर्विसेज रहा हो, सब ले लिया लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को, उनकी सरकार के जज्बे को कम नहीं कर पाए वो। उसी समय पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ की इसी सदन के 21 विधायकों को आफिस आफ प्रोफिट के कारण का केस लगाकर के सदन से डिसक्वालिफाई कर दिया गया, उसमें मैं भी एक था। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना चुनाव हारे हम एक्स हो गये और बिना चुनाव लड़े जीते, हम फिर विधायक बन गये ये भी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साजिशों का दौर चलता रहा फिर 2018 में एक फैसला आया संवैधानिक पीठ का उस फैसले में क्लीयरली कहा गया कि एलजी जो हैं वो ऐड एंड एडवाइज से बाउंड हैं लेकिन उसके बावजूद फिर 2020 का चुनाव हुआ 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के काम पर पहली बार किसी सरकार ने, किसी सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने काम किया तो काम के नाम पर वोट करना और पहली बार ऐसा हुआ कि जब इतनी साजिश कामयाब नहीं हो पाई तो 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का नहीं था, 2020 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फिर उसी रेडिकल लाइन पर लड़े, उसी पर धर्म पर पता नहीं क्या-क्या नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री दिल्ली के

कौने-कौने में जाकर पर्चे बांट रहे थे। लेकिन जब अरविन्द केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पर वोट करना, फिर इसी दिल्ली की जनता ने 53 परसेंट वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाईं जब तीसरी बार सरकार बनाया फिर एक बिल लेकर 2021 में आ गए कि अब एलजी ही मुखिया होगा। बिना एलजी के सैंक्शन के कोई फाईल नहीं जायेगी और फिर तमाम तरह की नीचता, कह लीजिए, होना शुरू हो गया। सारे विकास के काम रोक दिये गए। दिल्ली के वेलफेयर के काम को रोकने की साजिश की गईं लेकिन उसके बावजूद अरविन्द केजरीवाल जी के जज्बे को कम नहीं कर पाये। 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। दूसरी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने categoricallyकहा कि एलजी केबिनेटके aid and advice से बाउंड हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्विस दिल्ली सरकार का विषय है। मैं अमित शाह जी को संसद में सुन रहा था। अमित शाह जी कह रहे थे कि 239 एए (7)(ए) में केन्द्र को दिल्ली के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि अभी संवैधानिक पीठ ने इसी विषय को ज्यूडिशियल रिव्यू के संविधान पीठ में भेजा है कि (7)(ए) में केन्द्र सरकार के वास्तव में क्या अधिकार है या पार्लियामेंट में कोई काउंटर है कि नहीं है। लेकिन अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो (7)(बी) 239एए (7)(बी) ये कहता है कि आपको पार्लियामेंट 239 AA(7)(बी) stipulate that Parliament law making under article 239(AA) (7)(ए) shall not be deemed to be an amendment of the

constitution कहता है कि कानून बनाने का अधिकार है पर amendment करने का अधिकार आपको नहीं है। ये कह रहे है कि 239एए (3)(बी) कहता है संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। हॉं बना सकता है। पर वो फ्रैश कानून बना सकता है। क्योंकि 239एए (3)(सी) ये कहता है कि आप amend नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप entry 1, 2, 18 के साथ 41 को ला रहे हैं land, public order और पुलिस के साथ अगर आप service को ऐड कर रहे हैं तो आपको constitutional amendment लानापडेगा जिसका प्रोविजन 368 में है। तो अब इसका मतलब ये है कि किसी एक्ट से आप इसको amend नहीं कर सकते। फिर आपको constitutional amendment bill आपको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, ये प्रोविजन कहता है। तो आपने constitutionally fraud किया है पार्लियामेंट में। आपने constitutionally fraud करके दिल्ली की जनता के अधिकार को छीना है आपने। आपने constitutionally fraud करके दिल्ली की जनता को गुलाम बनाया है आपने। एक बात और कह रहे थे अमित शाह। अमित शाह कह रहे थे कि इससे पहले तो कोई विवाद नहीं हुआ और इसी लिए मैं दिल्ली की विधान सभा की प्रोसिडिंग्स को भी लेकर आया हूं। मैं मानता हूं कि 2014 के बाद वो दिल्ली आये हैं। तो 2014 के बाद का इतिहास भी जो प्रक्रिया उनकी जानकारी दिल्ली की होगी और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की टीम भी नहीं है कि वो थोडी रिसर्च भी कर लें। 2002 में चीफ मिनिस्टर जो तत्कालीन थीं वो

रूल 107 में मोशन लेकर आये थे और वो मोशन भी यही था कि उस समय में भी होम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिख करके जीएनसीटीडी को कहा कि ये इसका मतलब एलजी है। उस समय में भी कहा गया कि इन्ट्री 41 केन्द्र का विषय है, स्टेट का विषय नहीं है और उस समय शीला दीक्षित जी ने मोशन मूव किया था कि आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के constitutional right को आप usurp कर रहे हो। ऐसे सात शॉर्टडयूरेशन चर्चा इस सदन में हुआ है कि किस तरह से चुनी हुई सरकार की शक्ति को एलजी supersede कर रहा है। तो ये कोई पहला वाक्या नहीं है। ये पहले भी चर्चा होती रही है। इस सदन में इस बात पर खूब गहन मंथन हुआ है। तो अगर आप इस बात को सदन में कह रहे थे अमित शाह जी तो सदन में आप झूठ बोल रहे थे। वैसे तो आप लोगों का झूठ बोलने का, propaganda फैलाने का आपका अपना एक इतिहास है। आप, जिसका सच से लेना देना नहीं होता है, उसको भी आप साबित कर लेते हो। तो मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदया कि दिल्ली की जनता से बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अमित शाह कह रहे थे कि ये तो सुपारी पार्टी है। वैसे सुपारी किस दुनिया में, सुपारी से बड़ा प्यार है उनको चूंकि सुपारी वालों की एक दुनिया है, जहां सुपारी ली जाती है और दी जाती है। मैं गृह मंत्री के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन जिस जगत में सुपारी की चर्चा होती है,.. हॉ तो उस जगत से मुझे लगता है कि कोई रिश्ता नाता ज्यादा होगा। लेकिन वो

सुपारी अगर गर्दन में अटक जाये तो ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। गर्दन में अटकी पड़ी है आपके वो सुपारी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता के संवैधानिक अधिकारो की हत्या की गई है, इसको कभी देश माफ नहीं करेगा। आप देखिये एक चुनी हुई सरकार की शक्ति की आत्मा तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला –aid and advice ये constitution में चुनी हुई सरकार की मूल आत्मा है कि चाहे गवर्नर हो या प्रेजिडेंट हो केबिनेट की aid and advice पर काम करेंगे। दूसरा collective responsibility of government. जब मैं कहता हूं collective responsibility of government का मतलब क्या है कि सरकार के दो अंग हैं एक Permanent Executive दूसरा Political Executive. Permanent Executive Bureaucracy, Political Executive चुनी हुई सरकार। अगर आप Permanent Executive को अपने पास रख लोगे तो फिर collective responsibility आयेगा कहां से और तीसरी बात जो संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया triple chain of responsibility, ये triple chain of responsibility क्या कहता है? कहता है कि ये जो permanent executive है ये रिस्पोंसिबल होंगे accountable होंगे मिनिस्टर्स के लिए। मिनिस्टर रिस्पोंसिबल होंगे legislature के लिए और ये legislature responsible होगा जनता के लिए। ये पूरा चेन है। इस पूरे चेन में अगर आप Permanent Executive को Political Executive के ऊपर कर दोगे तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा triple chain of responsibility ये triple

chain of responsibility खत्म हो जायेगी। पूरे 102 से लेकर 110 पैरा में अच्छे से समझाया संवैधानिक पीठ के फैसले में कि आखिर किस तरह से चुनी हुई सरकार के लिए ये Permanent Executive जिम्मेदार होंगे। पैरा 106 में कहा 'under the Westminster parliamentary democracy the triple chain of command as follows: Civil Services officers accountable to Minister, Minister accountable to Parliament or Legislature and Parliament/Legislature is accountable to electorate.' आपने सुप्रीम कोर्ट के उस triple chain of responsibility को आपने खत्म कर दिया। आपने एक ऑथोरिटी बना दी और ऑथोरिटी कैसी है कि उसमें तीन लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सैक्रेट्री और होम सैक्रेट्री। अब एक बात बताईये आप वो कहता है कि उसकी कोरम दो लोगों से होगी। तो अगर चेयरमैन नहीं भी है और अगर ये बैठ जायेंगे तो कोरम पूरा हो जायेगा। meeting convene करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेट्री होगें होम सेक्रेट्री तो meeting convene करने की जिम्मेदारी उनकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मिटिंग बुलाकर के फैसला ले ले तो चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। पहला हम कोई ऐसी बॉडी हम देख रहे हैं जिसके चेयरमैन बिना चेयर का है और पहली बार इस constitution का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। कहा कि अगर यहां किसी तरह की आपस में मत एक नहीं होंगे, आपस में एक मत नहीं होंगे तो एलजी फैसला करेगा और एलजी अपने विवेक से फैसला करेगा। अरे ये कैसा, ये राजतंत्र तो नहीं है ना। इस पूरे

constitution में सब लोग चाहे वो प्रेजिडेंट हों, चाहे वो प्राईम मिनिस्टर हों, चाहे मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, हम विधायक हों, संविधान से बंधे हुए हैं। किसी के लिए स्वविवेक का जगह नहीं है कि आप स्वविवेक से फैसला ले लो। किसने अधिकार दिया आपको, किस रूल के तहत लेंगे आप? स्वविवेक से फैसला ले लेंगे आप? तो अगर आप स्वविवेक से फैसला लेंगे तोक्या संविधान से ऊपर हैं आप, parliamentary process से ऊपर हैं आप, जनतांत्रिक मूल्यों से ऊपर हैं आप? इस देश में जब प्रोसेस की बात आई तो parliamentary process को चुना गया और उस parliamentary process में किस तरह से.. पूरी व्यवस्था की गईं तो मुझे लगता है कि समझिये इस देश के संविधान से किस तरह से खेला गया है कि आज एक व्यक्ति को पूरे constitution से ऊपर बैठा दिया गया। कहा उसकी जो मर्जी होगी वो फैसला लेगा वो फैसला binding होगा।..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री संजीव झाः तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदया कि वो इकबाल साहब ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अभी हमारे विपक्ष के साथी नहीं हैं यहां। हो सकता है कि इस सरकार में आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। सरकार किसी की भी होगी लेकिन वो सरकार पैरालाईज सरकार होगी और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब से पार्टी बना तब लेकर उनका ये वादा था कि

हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 1977 से ले करके 1991 में जब ये विधान सभा बना तब भी उन्होंने कहा था कि ये विधान सभा अधूरा विधान सभा है। इस विधान सभा में पूरा स्टेट होना चाहिए। 2003 में उन्होने बिल पास किया था और आज वो पार्टी ये कह रही है कि हम दिल्ली के जो अधिकार है उसको भी छीन लेंगे। तो 2013 में जो इनका अपना स्टैंड था उस स्टैंड से पीछे हट गये कैसे भरोसा करेगा दिल्ली की जनता आप पर। ये कह रहे है 22 से 47 तक हम अमृत काल मनायेंगे। अमृत काल नहीं आपातकाल ले आयेंगे आप। जो आपका स्टैंड शुरू से था उससे तो आप वापिस हो गए, तो क्या अमृत काल लेकर आयेगें आप? मैं देश की जनता को भी आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर अगर ये भरोसा करा तो ये देश को आपातकाल की तरफ ले जायेंगे, निरंकुशता की तरफ ले जायेंगे। इसीलिये 2024 के चुनाव में ऐसी पार्टी को, ऐसे निरंकुश मानसिकता के लोगों को इनको सबक सिखाना चाहिये, बस इतना ही निवेदन और मैं चुने हुये विधायक होने के नाते एक पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि लगातार हमारी जनता ने हमें वोट किया और इसलिये वोट किया है कि हम उनका काम करा पायें। आपने उस जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है दिल्ली की जनता इसको बर्दाशत नहीं करने वाली बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्षा महोदया, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने देने के लिये बहुत–बहुत धन्यवाद आपका। संजीव भाई ने बहुत अच्छी शुरूआत की। आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार इतनी विचलित हो गई है। ये जो सर्विसिज एक्ट बनाया वो ये उदाहरण है कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी, केजरीवाल जी को संभाल नहीं पा रहे, क्या करें। आपने देखा इस देश के अंदर चुनाव का परिणाम कुछ भी हो। पहले ये प्रयास करते हैं कि पैसे के बल पर दूसरी पार्टी के चुने हुये विधायकों को अपने पार्टी में ले आओ और सरकार पे वहां कब्जा जमा लो। इसका इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रयत्न किया लेकिन दिल्ली के विध ायक केजरीवाल के सिपाही, किसी पैसे से खरीदे ना जा सके इसलिये वहां फैल हो गये। इन्होंने फिर प्रयत्न किया फिर दूसरा दांव चला ई.डी. का, सी.बी.आई. का कि किस प्रकार से केजरीवाल जी के विधायकों को, मंत्रियों को ई.डी. का डर दिखाओ, सी.बी.आई. का डर दिखाओ और डर के मारे इनको भाजपा में लाने का प्रयत्न करो। अभी संजीव ने कहा वो अजीत पवार को दिखा 70 हज़ार करोड़ का घोटाला दो दिन पहले ये बात कहा और दो दिन बाद अपने पार्टी में ले लिया, ई.डी का डर दिखाया फिर अपनी पार्टी में ले लिया। अध्यक्षा महोदया, तो ई.डी. और सी.बी.आई. का डर भी नहीं चला। हमारे माननीय मंत्री हैल्थ मिनिस्टर जैन साहब को जेल में बंद कर दिया, हमारे phenomenal historic education minister जिन्होंने एजुकेशन के जरिये पूरे देश का नाम विश्व में प्रचलित

किया, गर्व से ऊँचा किया उनको जेल में बंद कर दिया और जब ये ना पैसे पर खरीदे जा सके अरविंद केजरीवाल के सिपाही ना ई. डी. के डर से इनके पास आये केजरीवाल जी के सिपाही, तो तीसरी चाल चली कि भई इस सरकार की ताकत को ही छीन लो, इसे अपंग बनाओ। उसके लिये इन्होंने पार्लियामेंट जैसे पवित्र मंदिर का मिस्यूज़ किया और इनका जो अंहकार है वो सातवें आसमान पर है। क्या कहा वहां हाउस में, कहा ये अमित शाह जी ने जब पेश.. ये अपना लोकसभा के अंदर बिल पर जो चर्चा हो रही थी तो कहा कि opposition parties belonging to the Indian National Development Inclusive Alliance came together to oppose the bill for the sake of their alliance and not for the democracy and the country for its people for a small party, सुपारी जितनी पार्टी, अहंकार देखिये, सातवें आसमान पर है इनका अंहकार। साथियों ने कहा कि सुपारी का शब्द दो प्रकार से उपयोग में होता है तो सुपारी इनके ज़हन में था चूंकि सुपारी का शब्द बार-बार, बार-बार किसी ना किसी parlance में यूज़ करते होंगे ये तो वो सुपारी शब्द यहां भी यूज़ कर लिया। तो इसीलिये अध्यक्षा महोदय, ये जो अंहकार है और इनको याद होना चाहिये कि भाजपा किसी ज़माने में दो एम.पीज़ की पार्टी हुआ करती थी और दो एम.पी. होने में कई दशक लग गये थे इनको। ये तो केजरीवाल जी की लीडरशिप का कमाल है कि 10 साल में लोकसभा में हमारे एम.पीज.., राज्यसभा में हमारे एम.पीज़, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार,

गोआ के अंदर हमारे एम.एल.ए., गुजरात में हमारे एम.एल.ए. और 10 साल में ये छोटी सी पार्टी जिसको सुपारी जैसी पार्टी कह रहे हैं वो नेशनल पार्टी हो गई, इनको हज़्म नहीं हो रहा। अध्यक्षा महोदया, फिर ये कह रहे हैं मतलब पूरे भाषण सुन लीजिये इनका, एक भी आरग्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे ये जस्टीफाई कर सकें कि क्यों लाये ये सर्विसिज़ बिल, क्या कारण रहा। क्या-क्या बातें करेंगे करप्शन हो गया, शराब घोटाला कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय में मनीष जी के बेल के दौरान जब माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब ने पूछा कि भई ये तो बताओ हुआ क्या, गलती क्या है, money trail कहां है, जिस पैसे के घोटाले की बात करें उसका trail कहां है? तो ई.डी. क्या कह रहा है, कह रहे हैं कुछ मोहलत चाहिये हमें अभी। एक और मौका दीजिये हम आपको बतायेंगें, तो ये सात महीने से जिस व्यक्ति को आपने बंद कर रखा है, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने बंद कर रखा है और सात महीने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि आपको अभी और वक्त चाहिये money trail दिखाने के लिये और इसी की चर्चा कर रहे हैं अमित शाह जी वहां कोर्ट के अंदर, कह रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध इसीलिये कर रही है क्योंकि उनका sole intention है करप्शन को छुपाना। अरे कहां है करप्शन, कहां एक पैसे का money trail दिखा तो दो, दिखा सकते नहीं कोर्ट के अंदर बताया नहीं। अभी हमारे साथियों ने आज बड़ा डिटेल में रखा ढाई सौ करोड़ रुपये

का एक किलोमीटर सड़क बनाने का जो श्रेय इनको जाता है गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकाड्र्स में इनका नाम आयेगा उसके लिये। अध्यक्षा महोदया, उस दिन वो उन्होंने कोट किया कि नेहरू जी कह रहे हैं, अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं कि जी देखो ये कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य ना बनाओ लेकिन जैसा राघव चड्ढा जी ने हमारे सांसद ने उस सदन के अंदर कहा कि ये भूल गये अपने ही नेताओं को, ये भूल गये आडवानी जी को, ये भूल गये मदनलाल खुराना को जिन्होंने.. और साहिब सिंह वर्मा जी को जिन्होंने बार-बार, बार-बार इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी और इस सदन के अंदर भी रखने का प्रयत्न किया कि जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और 2014 के पहले, 2014 में भी इनके मैनीफैस्टो में था ये कि दिल्ली को बनायेंगे full statehood. अध्यक्षा महोदया, बड़ा convenience politics है इनका जब फायदा हो नेहरू जी से नेहरू जी को ले आओ। जब नेहरू जी को गाली देनी हो तो अभी उन्होंने जो नेहरू म्युज़ियम था उसका नाम चेंज करके रख दिया वो तो थोड़ी सी शर्म कहीं किसी ना किसी ने कहा होगा कि भई मोदी म्यूज़ियम ना रख दो इतना ही कसर रह गया था।..

माननीया अध्यक्षः कम्प्लीट कीजिये।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं ये देख रहा था कि ये हार रहे थे। ये जो थे सदन के अंदर हार रहे, राज्यसभा के अंदर साफ-साफ हार रहे थे लेकिन दो पार्टियों ने कि उनका डर दिखा रहा हूं मैं

यहां आपको जो पढ़कर बता रहा हूं कि उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, बड़ा हास्यास्पद है। YSRCP और BJP इन दोनों पार्टियों ने उनका साथ दिया अब क्या कहते हैं YSRCP के एम.पी. वहां मिथुन रेड्डी, कह रहे हैं कि जी I am supporting this bill with the hope that this would not be replicated for other states अब ये साफ-साफ कह रहा है, मतलब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि उस आदमी ने जैसा हमारे साथियों ने पहले भी कहा हुआ है विभिन्न तरीकों से कि कुछ ना कुछ तो डर दिखाया होगा, कुछ तो मज़बूरी रही होगी इस बेकाई की। तो कहा है 'I am supporting this bill assuming expressing the hope that this will not be replicated for other states' और BJD के जो पिनाके मिश्रा जी क्या कह रहे हैं उनका डर देखिये कैसे बाहर आ रहा है 'this law cannot be brought with respect to full states such as Orissa, Rajasthan and West Bengal' मतलब दोनों पार्टियों का डर बकायदा चूंकि ये डर के मारे ही इन्होंने सपोर्ट किया नहीं तो 131 और 102 में जो अगर उनका साथ हमें आ गया होता तो ये राज्यसभा के अंदर ये बिल इनका गिर जाता।..

माननीया अध्यक्ष: कम्प्लीट कीजिये भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: मदन लोकुर साहब हमारे एक जस्टिज़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका एक चार लाइन पढ़कर बताता हूं ये जिनकीauthority है constitution पर, कहते हैं 'given the sweep of the ordinance, it is Quite clear that the intent and the purpose is to

overturn the unanimous judgement of the constitution bench of the Supreme Court' साफ-साफ कह दिया 'the ordinance comes out as a constitutional fraud on the people of Delhi, its elected representatives and the constitution' उन्होंने कोट किया है डॉक्टर अम्बेडकर को जो कि अम्बेडर को कोट किया था उस दिन अमित शाह जी ने, तो अम्बेडकर की वो कोट जो उनको अच्छी नहीं लगेगी वो मैं सदन के सामने रख रहा हूं कि 1948 फोर्थ नवम्बर को जब उन्होंने constituent assembly के अंदर constitutional morality पर बात कही डॉ. अम्बेडकर ने तो क्या कहा 'while everybody recognizes the necessity of the diffusion of the constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things inter connected with it which are not unfortunately generally recognized, one is that the form of the administration has a close connection with the form of the constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the constitution. It is perfectly possible to pervert the constitution without changing its form by merely changing the form of the administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the constitution.' ये हम लोग पढ़ा करते थे colourable exercise जो आपने एक्ट बनाया चूंकि मैं उस वक्त कोर्ट में था जब माननीय चीफ जस्टिज़ ऑफ इण्डिया ने कहा खुले कोर्ट में कि जो आपको जो ordinance में 3(ए) था जिसमें कहा था कि भई सर्विसिज़ पर दिल्ली एसेंबली

कानून नहीं बना सकती तो कहा था भई ये कर क्या रहे हैं आप ये this is amounting to constitutional amendment तो जो उनके वकील थे ये भी बड़ा मुद्दे वाली बात है कि भई हरीश साल्वे साहब जैसा बड़ा वकील एल.जी. साहब कहां से अफ़ोर्ड कर रहे हैं ये भी बड़ा इन्ट्रस्टिंग है कि भई इतना जो जिनकी फीस करोड़ों में जाती है तो एल.जी. साहब कहां से इतना पैसा ला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भई okay my lord possibly we will drop 3(A) openly court में अगर ऐसे कोई घर की पंचायत चल रही हो कि अच्छा जी हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो वही हुआ फाइनल कि बिल में 3(ए) तो नहीं आया लेकिन colourable exercise करी इन्होंने कि पूरे एक्ट का जो इंटेंट है, वो वही है, जो 3–ए में था कि जो अधिकार कंस्टिट्यूशन ने दे रखे थे दिल्ली सरकार को, दिल्ली असेम्बली को कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और लैंड के अलावा बाकी सारी ताकतें दिल्ली सरकार की वही हैं जो एक full fledged सरकार के पास है तो सर्विसेस का ले लेना 3–ए को ड्राप करने के बाद भी ये तो वही काम है जिसकी चिंता माननीय मुख्य न्यायधीश ने की थी।

आप देखें ऑर्डिनेंस बना दिया, मतलब डर देखिये। एक तरह से तो हम सबको देखना चाहिए कि भई केजरीवाल जी से कितना डर है इस व्यक्ति को कि 11 मई को जजमेंट आता है। सात दिन के बाद 19 मई को जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर जाने वाला हैगर्मी के लिए उस दिन ऑर्डिनेंस रात को आ जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के

बंद होने का वेट कर रहे थे कि जी वो बंद हो और तुरंत हम इस आर्डिनेंस को ले आएं। तो एक तरह से आर्डिनेंस का जो आर्टिकल 123 में जो पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसका मिसयूज है क्योंकि there was no reason which could explain that what was the hurry to bring this ordinance अब ये कर क्या रहे हैं। मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर चर्चा होने लगी चारो तरफ कि भई इनकी हरकतों से एक बात तो हर वक्त हर तरफ पहुंच रहा है कि अगर नरेन्द्र मोदी जी को डर लगता है, किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं तो वो एक ही व्यक्ति हैं, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और इस सर्विसेस एक्ट से इन्होंने प्रूव कर दिया कि वो येन-केन-प्रकरेण इस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बड़ा अजूबा रहा कि 3 सदस्यों की इन्होंने अर्थोरिटी बना दी। उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री, ये पहली बार इतिहास में हुआ और सभी सांसदों ने कहा।

माननीया अध्यक्षः जो साथी, जो साथी सदस्य बोल गये रिपिटेशन न करें। कंप्लीट कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः ये जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को सभी सांसदों ने खुले शब्दों में इसकी निन्दा भी की और एक बात और अध्यक्षा महोदया, जो मैं आपके जरिये सदन को और देश को बताना चाहता हूं। एक बड़ा फ्रॉड जो मोदी सरकार करने जा रही है, वो है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी, उसमें सीजीआई होंगे, उसमें प्राइम

मिनिस्टर होंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। इन्होंने उसको ओवर टर्न करके सीजीआई को ड्राप कर दिया और कह रहे हैं सीजीआई की जगह प्राइम मिनिस्टर मनोनित मंत्री होंगे। तो अब वही जो यहां कर रहे हैं फ्रॉड दिल्ली सरकार में वही फ्रॉड वहां भी करने जा रहे हैं देश के साथ कि उस कमिटी में जो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी, उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तीन में से दो इनके प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर मनोनित मंत्री, तो दो इनके और एक विपक्ष का और बाय मेजोरिटी डिसाइड करेंगे तो इस आदमी में इतनी घबराहट है कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ये अपनी बपौती करार देने वाला है।..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारतीः इसलिए मैं आपके जरिये इस बात को सदन में रखना चाहता हूं कि सर्विसेस एक्ट अन-कांस्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है और जहां तक मेरी समझ जाती है संविधान की, माननीय उच्चतम न्यायालय में जरूर ये जो एक्ट बनाया है इन्होंने, इसको set aside कर दिया जाएगा और तब जाकर मोदी सरकार को समझ आएगी कि किस प्रकार से संविधान के साथ जनता के जो वोट की ताकत है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।.

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारतीः आज दिल्ली के.. एक लाईन आखिर में. ... आज दिल्ली की जनता जिन्होंने इतने overwhelming majority दे

करके केजरीवाल सरकार को चुना, आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और आने वाले समय में जो 2024 के अंदर लोक सभा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है कि सातों लोक सभा सीटों के ऊपर इस बार भाजपा की हार सुनिश्चित है और मोदी जी का जाना 24 में सुनिश्चित है, जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी समय का ध्यान रखें। बहुत सारे वक्ता हैं इस विषय पर।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्षा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया और ये विषय जो है ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। ये इस भारत के संविधान का विषय है। ये इस लोकतंत्र का विषय है तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शायरी यहां पढ़ना चाहता हूंः-

तुम रौंद सकते हो, सभी फूलों को,

तुम रौंद सकते हो, सभी फूलों को,

मगर बसंत को आने से नहीं रोक सकते।

आप कितने भी कानून बना लो। आप कितना भी कुछ कर लो, अरविन्द केजरीवाल जी जितने मजबूत थे, उतने मजबूत हैं और आगे भी उतने मजबूत रहेंगे और देश में जितनी लोकप्रियता उनकी

बढ़ रही है, जिससे मोदी सरकार डर के ये कानून लेकर आयी है, ये बिल लेकर आयी है। आप उसको नही रोक सकते क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं।

अध्यक्षा जी, 1977 से लेकर 2015 तक भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे वो मदन लाल खुराना हों, चाहे वो साहब सिंह वर्मा जी हों, हर व्यक्ति भाजपा का हमेशा से दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की बात करता था। उसके अधिकार दिलाने की बात करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वादों से मुकर गयी और दिल्ली की जनता की पीठ में छुरी घोंपने का काम किया और दिल्ली के लोगों से जो वादे किये, उन वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गयी और अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रकरण आपको समझ में आएगा कि आखिर देश की गद्दी पर विराजमान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें दिल्ली के अधिकार छीनने के लिए रात को 11 बजे काला कानून लाना पड़ा, जिसके काले करम होते हैं, वो रात को ऐसे काम करता है। रात को 11 बजे देश के प्रधानमंत्री कानून लेकर आए और वो कानून लेकर आए दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का और जो अधिकार छीने गए वो ऐसे छीने गये क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली से शुरू हुई छोटी सी पार्टी, जिसके नेता माननीय मुख्यमंत्री, अरविन्द केजरीवाल जी हैं, वो लगातार जब दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर

चुनाव हुए तो 2013 के अंदर दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें अरविन्द केजरीवाल जी को दी और 2013 के अंदर जो 49 दिन की सरकार थी, वो 49 दिन के अंदर जो दिल्ली के लोगों नेदेखा, एक ऐसा नायक का रुप अरविन्द केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों ने देखा कि जब कोई थाने में जाता था तो उसका पैन और मोबाईल बाहर जमा करा लिया जाता था। रेड लाईट के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिये थे। आरटीओ दफ्तर में आरसी के, लाइसेंस के पैसे लेने बंद कर दिये थे, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति तो दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और उसके बाद दिल्ली के अंदर फिर दोबारा चुनाव हुए 2015 के अंदर और 2015 के अंदर दिल्ली के लोगो ने उस 28 सीटों के बाद 49 दिन के टेलर देखने के बाद दिल्ली में, देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 70 में से 67 सीटें दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविन्द केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देने का काम किया। उसके बाद 2020 में चुनाव होते हैं, यही पार्टी 70 में से 62 सीटें लेकर आती है, उसके बाद जो मोदी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात, उस गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और गुजरात के लोग वहां पांच सीटें और 15 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं। ऐसा पहली बार होता है।

निगम का चुनाव होता है। 15 साल से भाजपा जड़ जमाये बैठी थी। दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। सारे काम किये

अमित शाह जी ने, सारी चाणक्य नीति लगा ली उन्होंने अपनी, डिलिमिटेशन किया, इधर किया, उधर किया, आरक्षण किया, रिजर्वेशन किया, सबकुछ कर लिया। हिन्दू को मुसलमान में मिला दिया, मुसलमान को हिन्दु में, दलित को ओबीसी से सारे काम किये, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सारा का सारा कारण ये है, सारी का सारी जड़ ये है क्योंकि उनको पता है कि अरविन्द केजरीवाल जी का कद देश की राजनीति के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के लोग आज अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ देख रहे हैं उसकी निगाह से, कि आज अरविन्द केजरीवाल जी हमारे राज्य में आएंगे और वहां के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम होगा। वहां भी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस बन पाएगा, वहां भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब का बच्चा जो पहले आई.आई.टी. तक जाने का स्वप्न देखता था वो आई.आई.टी. के अंदर एडमिशन ले पाएगा, जेईई के अंदर एडमिशन ले जाएगा, ऐसा बदलाव दिल्ली के अंदर हुआ और यही डर है कि रात के 11 बजे चाणक्य अमित शाह जी को यह बिल लेकर आना पड़ा। ये बिल लेकर आना पड़ा और दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का काम हुआ और दिल्ली से उन्होंने अपने जितने वादे दिल्ली के लोगों से किये थे, उन सारे वादों से वो मुकरते चले गये..

माननीया अध्यक्षः कंप्लीट कीजिए।

श्री कुलदीप कुमार: और उन्होंने कहा, बस दो मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर जो जनता की चुनी हुई सरकार को ताकत दी गयी थी, जिसमें वो जनता की सरकार से चुना हुआ मुख्यमंत्री ताकतवर होते थे, अब उसके ऊपर एक अफसरशाही राज करेगी। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर छुरी घोंपनेका काम नहीं है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी जो ये बिल लेकर आई है, ये संविधान के परे नहीं हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सोच कर संविधान बनाया था? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी ने संसद में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने कभी माना नहीं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मान लेते तो आज दिल्ली के अंदर जो गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूरे देश के अंदर गरीब के बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। लोगों को समान स्वास्थ्य मिलना चाहिए लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घमंड में आ गये, इतने घमंड में आ गये, अभी मैंने सुना कि एक आर्थिक सलाहकार समिति हैं मोदी जी की, उसके अध्यक्ष जो है, विवेक ओबराय है। उन्होंने अभी एक लेख लिखा मिड डे अखबार के

अंदर और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। आप सोचिये ये लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश की है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की है, ये उन लाखों, दलितों और ओबीसी की बात है, महिलाओं की बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान, जिनको ये अधिकार देता है, आज संविधान को बदलने की बात हो रही है इस देश के अंदर और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर 2024 के अंदर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का संविधान बदला जाएगा। इसलिए बदला जाएगा क्योंकि ये संविधान सबको बराबरी की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली के लोग मोदी जी से क्या कह रहे हैं, आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं मोदी जी से:

न पूछ मेरे सब्र की इंतहां कहां तक है,
न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है,
तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है,
और का की उम्मीद जिन्हें होगी, उन्हें होगी,
हमें तो देखना है तू बेका कहां तक है।

दिल्ली वालों से हमेशा बेकाई करने का काम भाजपा के लोगों ने किया है और दिल्ली वाले इसका जवाब आने वाल 2024 में दे

देंगे। मैं दावे से कह रहा हूं सदन के अंदर सात की सात लोक सभा सीटों पर भाजपा जीरो होने जा रही है और दिल्ली के लोग अरविन्द केजरीवाल जी को जितायेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।

माननीया अध्यक्षः सुश्री आतिशी जी माननीय मंत्री।

माननीय मंत्री (सुश्री आतिशी): धन्यवाद अध्यक्षा जी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर बोलने का मौका दिया। मुझे दुख है इस बात कि हमारे भाजपा के साथी अभी इस सदन में नहीं हैं, क्योंकि दो ही हमारे भाजपा के साथी और इनसे पहले इस सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने इस सदन की पावर बढ़ाने की बात करी और सालों तक करी। भारतीय जनता पार्टी साल दर साल संघर्ष करती रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हर साल जब भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे मैं उनके इतने मैनिफैस्टो लेके आई हूँ। 1989, 1991, 1996, 1998, 2004 हर बार वो एक वादा जरूर करते थे। वो ये वादा करते थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज नेता अडवानी जी, वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, मदनलाल खुराना जी सबने बार-बार हर फोरम पर यही बात की के हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। 2013 में जब दिल्ली में विधान सभा चुनाव था मैं कुछ उस समय के इनके ट्विट्स इक्कट्ठे करके लाई हूँ भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता

पार्टी का ही ट्विटर का हैंडल है जो बार–बार यही कहता रहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली वालों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। 2013 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफैस्टो सबसे पहले ये कहता है, जहां पर वो कहता है 'our commitments, full statehood for Delhi' ये उनका पहला वादा था। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने इस मैनिफैस्टो को पूरे इण्टरनेट से, सोशल मीडिया से गायब कर दिया है क्योंकि उसमें उन्होंने खुद वादा किया हुआ है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में भी अगर आप इसमें देखिए जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केन्द्र का चुनाव जीतकर आई तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि सबसे पहला जो हम वादा पूरा करेंगे जो मोदी जी वादा पूरा करेंगे वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए करेंगे। तो इतनी लम्बी लड़ाई जो वो लड़ते आये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे तो 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो अपना वादा भूल गए। अकच्युएली अध्यक्षा जी 2015 में दिल्ली में कुछ अद्भुत हो गया जिससे ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी परेशान हो गए। 2015 से पहले दिल्ली के लोग भी बाकि देश के लोगों की तरह परेशान रहते थे, हताश रहते थे, निराश रहते थे। बहुत cynicism से वो राजनीति को, पॉलिटीशियन्स को देखते थे, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव में किसी को भी वोट दे दो क्या फर्क पड़ता है। सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। लेकिन एक आम

आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आना। एक आम आदमी को महीने की पहली तारीख पे ये सोचना पड़ता है कि इस महीने मेरा घर कैसे चलेगा। एक आम आदमी को ये सोचना पड़ता है कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया तो परिवार के सारे जेवर, परिवार की सारी जमीन को गिरवी रखना पड़ेगा। एक आदमी ये सोचता है के अगर हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अपने पेट काटकर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन-सी सरकार आती है, कौन-सी सरकार जाती है। लेकिन 2015 में दिल्ली के लोगों ने देखा कि दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा आदमी आया जो नेता नहीं था। जो उनका बेटा था, उनका छोटा भाई था, जिसने उनको वादा किया कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनायेगा। 2015 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविन्द केजरीवाल जी को अपना प्यार दिया, अपना आशिर्वाद दिया, अपनी वोट दी और इस सदन में 70 में से 67 सीट जीता के भेजा आम आदमी पार्टी को अरविन्द केजरीवाल जी को। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की कहानी पलट गईं उन्हें समझ में आ गया कि अगर अरविन्द केजरीवाल जी की राजनीति सक्सेसफुल हो गयी, वो राजनीति जो भ्रष्टाचार खत्म करती है, वो राजनीति जो फ्री बिजली देती है, वो राजनीति जो घर-घर पानी पहुंचाती है। वो राजनीति जो सबको अच्छा इलाज देती है, बच्चों को अच्छा भविष्य देती है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक दुकान बंद हो जायेगी और यही डर था जिसकी वजह से

मई 2015 में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन एमएचए द्वारा इशु किया जाता है और कहा जाता है कि संविधान कुछ भी कहे, संविधान तो ये कहता है कि लैंड लॉ एण्ड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकि सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास हैलेकिन एमएचए एक नोटिफिकेशन इशु करता है, कहता है कि सर्विसिस यानि अफसरों की ट्रांस्फर पोस्टिंग, अफसरों को आदेश देने की ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी। अध्यक्षा जी 8 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने संघर्ष किया। इस नोटिफिकेशन के बावजूद, इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने दिल्ली वालों के काम रूकने नहीं दिये। कभी सड़क पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, एलजी ऑफिस में जाके लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी लेकिन दिल्ली में उन्होंने वो करके दिखाया जो देश के 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ। आज दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बजली मिलती है। हजारों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पे पहली बार पानी की लाईन पड़ी है, सीवर की लाईन पड़ी है। देश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल के हजारों बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं वो हर साल जेईई, नीट का एग्जाम क्लीयर करके देश के बड़े–बड़े इंजीनियर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आठ साल तक अपनी ताकत कम होने के बावजूद भी अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। पहले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच,

कॉन्सटीटयूसन बेंच दो-दो बार बैठी लेकिन दिल्ली के हक की लड़ाई अरविन्द केजरीवाल जी लड़ते रहे और आखिर में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसकी कान्सटीटयूसन बेंच ने 11 मई को एक फैसला दिया, एक तरुा फैसला unanimous 5:0 का फैसला और उन्होंने कहा कि लैंड लॉ एण्ड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है। ना तो वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना तो वो संविधान का सम्मान करते हैं और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 8 साल के कोर्ट में संघर्ष के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट दिया, क्यूं? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अरविन्द केजरीवाल की सरकार को ताकत मिल जायेगी तो देश देखेगा कि किस स्पीड से काम होते हैं। पब्लिक के काम किस तरह से होते हैं। पहले वो ऑर्डिनेंस लेके आये, फिर वो बिल लेके आये। अध्यक्षा जी, इस बिल में दिल्ली के लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के ऊपर एक एलजी को थोपा गया है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर वॉयसराय का महल है जो अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पे थोपे गए थे कि भारत के लोग चाहें या ना चाहें लेकिन वॉयसराय उन पर शासन करता था। आज केन्द्र सरकार ने भी वो ही किया है कि

दिल्ली के लोग चाहें या ना चाहें एलजी साहब उनके ऊपर शासन करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अरविन्द केजरीवाल जी की ताकत कम नहीं की है। उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को वोट का अधिकार लाखों लोगों के संघर्ष के बाद मिला था। अभी 15 अगस्त बीती है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम तिरंगा फहराते हैं। ये तिरंगा फहराने का अधिकार, वोट करने का अधिकार सैकड़ों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है और अगर आज जनता की ताकत को छीनोगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपने दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार किया है। जो आपने दिल्ली के लोगों की ताकत छीनी है ये ही दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को मुहतोड़ जवाब देंगे। ना सिर्फ लोकसभा में सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन ये जो 8 सीटें भी इन्हें दिल्ली की विधान सभा में मिली हुई हैं 2025 के चुनाव में ये भी चली जायेंगी और 70 में से 70 सीटें दिल्ली के लोग अरविन्द केजरीवाल जी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी बस एक आखिरी चीज याद रखे। आप लोगों पर अत्याचार कर सकते हो, आप उनकी ताकत छीन सकते हो, आप उनकी

वोट की शक्ति पे वार कर सकते हो, लेकिन आप इस सबसे दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत सकते, दिल्ली की जनता का प्यार नहीं जीत सकते। दिल्ली की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी।

माननीय जलमंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आज इस चर्चा में शामिल होने का आपने मुझे मौका दिया। संजीव भाई ने बहुत अच्छी शुरूआत की और constitutional provisions बताये कि क्यों केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया ये Amendment Act गैर-संवैधानिक है, गैर-लोकतांत्रिक है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी ये मामला आयेगा, ये नहीं टिकेगा। दो-तीन दिन पहले मैं पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहा था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा सर आप बार-बार कह रहे हैं कि ये unconstitutional है और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। मगर पार्लियामेंट के पास तो पावर है एक्ट बनाने की। कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है तो पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे हटा देगा, तो मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भक्त हैं उनको क्या पाठ सीखाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बाबासाहब का संविधान आज जिंदा है। किसी भी देश की संसद को या केन्द्र सरकार को ये अधिकार तो है कि आप कानून बना सकते हैं

मगर वो कानून आपके basic principles of constitution के अंदर ही बना सकते हैं आप उसके बाहर नहीं बना सकते।

ये कोई नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। मसलन ये है कि आपको कोयले की खदान बांटनी है, कानून आप बना सकते हैं मगर आप ये कानून नहीं बना सकते कि भई जिसने लाल कमीज पहनी है उसको कोयले की खदान दे देंगे, ऐसा कानून नहीं बन सकता। ये कानून नहीं बन सकता कि जी साउथ इंडिया के लोगों को देंगे, नॉर्थ इंडिया को नहीं देंगे। ये कानून नहीं बन सकता कि महिलाओं को नहीं देंगे, पुरूषों को सिर्फ खदान देंगे। ऐसे कानून नहीं बन सकते। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, हमारे कांस्टीट्यूशन के उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तो ये कानून तो बेसिक प्रिंसिपल से बाहर है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। तो कांस्टीट्यूशन के विषय में कई साथियों ने बताया, मैं उस विषय में दुबारा नहीं घुसूंगा। मैं एक बड़ी साधारण सी बात करना चाहता हूं जो एक साधारण आदमी को समझ में आये कि क्या कारण है केंद्र सरकार इस तरीके से अमादा है, सारी लोक–लज्जा, नैतिकता, शर्म, लिहाज, सब छोड़ दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई उसी दिन रातों–रात ऑर्डिनेंस ले आये, ऐसा क्या हो गया? कारण ये है अध्यक्षा महोदया भारतीय जनता पार्टी ये बात मान चुकी है कि वो दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकती, ये बात वो मान चुकी है। उनकी सरकार यहां नहीं बन सकती, उनको मालूम है। इसलिए अब

वो सारे काम किये जायेंगे कि यहां पर बिना सरकार चलाये ही किसी तरीके से दिल्लीवालों को परेशान किया जाए। दिल्लीवालों के काम रोके जाए।

कल पेटिशंस कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा हो रही थी और रिपोर्ट्स में लिखा है अध्यक्षा महोदया, आप सोचिए आप राजनीति में क्यूं आते हैं? आप राजनीति में इसलिए आते हैं आप गरीबों की मदद कर सकें, बेसहारा लोगों की आप पेंशन लगवा सकें, कोई बीमार हो तो आप अस्पताल में उसका इलाज करवा सकें, कोई गरीब हो उसके पास पैसे न हो तो मुफ्त में उसका टेस्ट करवा सकें, इसीलिए तो आप राजनीति में आते हैं। ये ही काम हैं आपका राजनीति में आकर, वर्ना और क्या कर सकते हैं? और ये जो नए-नए कानून लाये गये हैं, जो 2015 में लाये गये, 2020 में लाया गया, फिर 2023 के अंदर लाया गया ऑर्डिनेंस, फिर 2023 में दुबारा कानून लाया गया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अध्यक्षा महोदया सिर्फ ये है कि दिल्ली के गरीब, आम लोगों को परेशान करना, उनकी जिदंगी को हराम करना।

आप सोचिए अध्यक्षा महोदया मैं जब विधायक था, अपनी विधान सभा के कार्यालय में बैठता था तो एक औरत मेरे पास हर हफ्ते आती थी और वो कहती थी, वो डीडीए फ्लैट्स कालकाजी से आती थी, शायद 13 नंबर ब्लॉक या 11 नंबर ब्लॉक से और वो आकर ये ही कहती थी कि बेटा मेरी और मेरे पति की पेंशन 3 महीने से रूकी हुई है, 3 महीने से उसके और उसकी पति

की पेंशन मिला लो तो 5 हजार रुपये महीने का उसका रूका हुआ है। मैंने कहा जी पति क्यों नहीं आते आपके, आप क्यों आती हो, कह रहे बेटा उनको कैंसर है, वो बीमार है, चल भी नहीं सकते। अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है मगर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है, ऑटो में आने जाने में 2 सौ रुपये लगते हैं, 2 सौ रुपये नहीं है मेरे पास। दवाई लेने का टाइम हो गया है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया, मेरे पास 2 सौ रुपये नहीं है, मैं कैसे ऑटो लेकर जाऊं और रोती थी आकर। और इस तरीके का एक नहीं था कोई, इस तरीके के लाखों लोग दिल्ली में थे जिनकी पेंशन पिछले साल 3 महीने के लिए रोकी गई थी। जून में मुझे लगता है कि पेंशन दी गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ये पेंशन रोकी गईं अक्टूबर के अंदर ये मामला हमारे पास आया, क्यूं पेंशन नहीं दी जा रही, फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगा दिये, क्यों ऑब्जेक्शन लगा दिये, अध्यक्षा महोदया, हम सुनकर हैरान हो गये कि क्या बात है, कहते हैं कि जी जो शुरू में पेंशन की जो स्कीम बनी थी उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसिस जो थे उनको पेंशन डिसबर्स्ड करनी थी और इस बार जब फाइनेंस के अंदर फाइल गई तो फाइनेंस ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो तुम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे, सेंट्रल ऑफिस पेंशन कैसे देगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेंशन देंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसिस को कहा गया कि तुम पेंशन दो। उन्होंने वापिस चिट्ठी लिखी कि जी हमारे पास न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न हमारे पास ऑपरेटर

है, हमारे पास न क्लेरिकल स्टाफ है, हम कैसे दें? और ये फाइल आगे पीछे, आगे पीछे होते–होते 3 महीने गुजर गये अध्यक्षा महोदया और गरीब लोगों को पेंशन दी नहीं गईं

फिर आई बात, एक और पेटिशन लगा था अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर्स हैं, ओपीडी काउंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर सबसे पहले कोई गरीब बीमार आदमी वहां जाता है अपना एक ओपीडी का पर्चा बनवाता है और फिर वो अस्पताल के अंदर डॉक्टर के पास जाता है। हमें पता चला कि अस्पतालों के अंदर जितने भी ओपीडी काउंटर हैं उनके अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी अचानक नौकरी खत्म कर दी गई, घर जाओ। पता किया भई ऐसा क्या हो गया। पता चला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि भई आप इतने सालों से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लगा रहे हों इसकी आपने एक एआर स्टडी तो कराई ही नहीं है और क्योंकि आपने एआर स्टडी नहीं कराई है इसलिए सबको निकाल दिया गया ताकि जब तक एआर स्टडी नहीं होगी तब तक अस्पतालों के अंदर ओपीडी काउंटर के ऊपर बैठने वाला कोई नहीं होगा। स्वीपर बैठा हुआ है ओपीडी काउंटर पर, उसको क्या पता ophthalmologist के पास भेजना है या डेंटिस्ट के पास भेजना है, उसको क्या पता, गायनेकॉलोजिस्ट के पास भेजना है या बच्चों के डॉक्टर के पास भेजना है, उसको कुछ नहीं पता। आपने अफरा तफरी मचा दी। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, आपने सिर्फ फाइनेंस की ऑब्जेक्शन के सहारे आपने कई महीनों तक अस्पतालों

के अंदर और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद कर दिये। ये क्यूं किया जा रहा है? दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, आप इस बात को समझिये।

जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, लोग पानी की समस्या से परेशान है। किसी के यहां सीवर ओवरफ्लो हो रहा है वो परेशान है मगर जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, क्यूं रोका गया? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि दिल्ली की जनता को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, करते रहो उनको परेशान, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो जाए, सिर्फ एक मकसद है।

जो अफसर अच्छा काम का है, ऐसा नहीं है अफसर अच्छे नहीं हैं, अफसर हैं अच्छे, जो अफसर अच्छा काम करते हैं उनको ऐसी जगह लगा दिया जाता है जहां पर वो काम ही न कर सकें या उनको ट्रांस्फर कर दिया जाता है। जो अफसर सबसे ज्यादा बदमाश हैं, जो हर काम को रोकेगा उस असफर को ऐसी जगह लगाया जाता है ताकि दिल्ली सरकार का हर काम रोका जाए। हर चीज के ऊपर, फाइल के ऊपर कोई ऐसी बात लिख दी जाए कि वो कई महीनों तक फाइल घुमती रहे, घुमती रहे, उसका नंबर ही न आये काम होने का।

मैं अध्यक्षा महोदय एक बात बताना चाहता हूं, एक घर के अंदर मां होती है और बेटा गरीब होता है मगर मां बेटे से प्यार करती है इसीलिए मां उसके साथ रहती है, इसलिए नहीं रहती कि

मां को वो सहूलियत दे रहा है। ये दिल्ली की जनता अरविदं केजरीवाल जी की मां है और ये मां जान रही है, ये मां जान रही है कि बेटा तो कमाता है, बेटा तो चाहता है कि मां को सब सहूलियत मिले मगर बीच में कुछ लोग हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं जो वो सहूलियतें दिल्लीवालों को पहुंचने नहीं दे रहे, ये बात जनता भी जानती है। और ये ही कारण है अध्यक्षा महोदया भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना ये है 93 में पहली सरकार बनी थी, 25 साल हो गये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं आ पाईं ये इसी जगह बैठेंगे अगली बार भी आप देख लीजियेगा। ये ही जगह होगी और ये हमेशा सामने बैठेंगे। ये कभी इस तरफ नहीं आ पायेंगे क्योंकि ये दिल्ली को, क्योंकि ये दिल्ली की जनता को सताते हैं। इन्होंने 2013 में ये करने की कोशिश की, इन्होंने 2015 में ये कोशिश की, इन्होंने 2020 में ये कोशिश की और दिल्ली की जनता जानती है कि इनकी नीयत खराब है। ये लोग दिल्ली की जनता को परेशान करने वाले लोग हैं इसलिए अध्यक्षा महोदया मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये लाख कोशिशें कर लें अगली बार भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री बनायेगी।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): अध्यक्षा महोदया, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित उस ऑर्डिनेंस और उसके बाद एक बिल जो उन्होंने अभी संसद में

पारित किया, जिससे उन्होंने दिल्ली के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस ऑर्डिनेंस और इस बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस क्यूं आया, ये बिल क्यूं आया। थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, 8-9 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2013 का साल था, अगले साल 2014 में अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। पूरे देश के अंदर 2013 में कांग्रेस को लेकर बड़ी नेगेटिविटी थी। चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। चारों तरफ देश के अंदर मोदी के बारे में और मोदी जी के बारे में चर्चा थी, अचानक 4 दिसंबर, 2013 को दिल्ली विधान सभा के चुनाव हुए, 8 दिसंबर को नतीजे आये और 8 दिसंबर को कुछ अद्‌भुत हो गया कि एक नई पार्टी जिसके पास न आदमी, 4 आदमी नहीं थे, 4 रुपये नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, सारे मीडिया ने, मेरे को याद है चुनाव के 48 घंटे पहले भी इन मीडिया वालों ने हमारा एक sting जारी किया था। और एक नई पार्टी की 28 सीट आ गई और उनकी सरकार बन गई है और 28 दिसंबर को उस सरकार ने शपथ ली और सरकार ने काम करना चालू कर दिया। तो जो पूरे देश में मोदी लहर, मोदी लहर चल रही थी अब चर्चा चारों तरफ हो गई पूरे देश में आम आदमी पार्टी की, ये आम आदमी पार्टी कहां से आ गईं सारे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा, मेरे को याद है जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया के ंंट पेज

के ऊपर हेडलाइन थी कि उन्होंने सर्वे कराया और आम आदमी पार्टी की डेढ़ सौ सीट आने वाली हैं, मतलब माहौल ये था चारों तरु, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या करिश्मा होने वाला है। आप सोच सकते हो मोदी जी के दिल पर उस टाइम क्या गुजर रही होगी, आदमी बेचारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और एक अचानक पता नहीं एक छोटे से राज्य, आधे राज्य के अंदर एक नई पार्टी आई और उसने हंगामा शुरू कर दिया। हमारी सरकार 49 दिन ही चली लेकिन उस 49 दिन को लोग आज भी याद करते हैं। उस 49 दिन में जो अभी कुलदीप कह रहा था, पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। लोग बताते हैं ये पंजाब जो हम जीते, पंजाब के ट्रक ड्राइवर जो दिल्ली आते हैं वो बताते हैं जी चौराहों के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिये, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने पैसे लेने., हमने जारी किया था न वो कि भई अब कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना उसकी सेटिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना और मैं उस असफर को जेल भेज दूंगा।

बत्तीस अफसरों को जेल भेजा हमने 49 दिन में। दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लोगों ने कभी ऐसी सरकार देखी नहीं थी और उसकी चर्चा पूरे देश में। उसके बाद कोई महिला सुरक्षा को लेके दो तीन केस आये जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सड़क के उपर जाके दो या तीन दिन के लिये रात भर मैं वहां सोया

था। पूरे देश का सारा मीडिया हमारी ही चर्चा कर रहा था। मोदी जी तो, उनको लगा कि यार ये क्या हो गया, अभी तक तो चर्चा उन्हीं की चल रही थी। दिल्ली के अंदर बिजली के रेट एकदम से आधे हो गये। दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त हो गया और उस वक्त जो इस देश का सबसे अमीर आदमी था उसके खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज कराने. जिस आदमी का नाम लेने से ये सारी पार्टियां कांपती हैं नाम लेने से, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने नोटिंग करी थी 49 दिन की सरकार थी। हमने इस्तीफा दिया जो भी कारण रहे। हमने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी। अप्रैल का महीना आया ये चुनाव लड़े और उसके बाद इनको पूरी ये लोग जीत गये भारी बहुमत से मोदी जी की जीत हुई और सारी तरफ हुआ मोदी इरा, मोदी एज, मोदी युग आ गया। इनको पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गयी है। मेरे को याद है एक अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफी चलता है उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद 16 मई को नतीजे आये थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में तो मैं जरूर उनके साथ डिबेट करूंगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी खत्म और केजरीवाल भी खत्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसके बाद लोक सभा के

बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गये, हरियाणा में चुनाव हुए मोदी जी हरियाणा जीत गये, झारखंड में चुनाव हुए मोदी जी झारखंड जीत गये। फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। तीन सीट पे सिमट गयी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी तीन सीट के उपर सिमट गयी। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया, वो लव और कुश ने दिल्ली वालों ने, उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है। भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिये, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिये, पूरा तंत्र लग गया और उपर वाले का करिश्मा देखो उपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया उपर वाले ने करिश्मा कर दिया। मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया, उन्होंने पूरी कोशिश की खत्म करो इनकी

पार्टी उसके उपर भी मैं आउंगा अभी एक एक करके। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को, 23 मई, तीन महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया एमएचए ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसिज़ के उपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार। संविधान में लिखा है ये हमारा है। कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के उपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के उपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के उपर कोई अधिकार नहीं रहे, वो तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकंस्टिटयूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसिज़, क्यूं करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें। और सर्विसिज़ क्यूं उन्होंने किया, सर्विसिज़ इसलिये किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में bureaucracy of Delhi has been weaponized उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे और वो किया भी। सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिये। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी, बताओ मोहल्ला क्लिनिक

के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों, अफसरों को बुलाते हैं उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं, अफसर बुरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने, सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको, जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बिठा रखा है इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिये इन लोगों ने। लैबोरेटरी के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट रोक दिये इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जायें। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं टीचर्स को फारेन ट्रेनिंग पर भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की डेढ़ साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गयी हैं पिछले डेढ साल से। ओल्ड एज़ पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूं न बीजेपी ने ये सब किया है कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो पार्टी चुनाव जीतने के लिये दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है वो दवाईयां रोकना तो उनके लिये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उपर वाले के यहां देर है अंधोर नहीं है। आठ साल के जद्दोजहद के बाद अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का

आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के तीन हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की और तीन हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद चार महीने तक उन्होंने सोचा, समझा आपस में और चार महीने के बाद ऑर्डर दिया उन्होंने सुनवाई के और उस ऑर्डर में एकतरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है और सरकार चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिये, अफसरशाही के उपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी ये कोर्ट के आदेश में लिखा है। कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर नहीं होगी। साफ साफ आदेश, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो गया। लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता, 11 मई को ऑर्डर आया 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी 20 मई से छुट्टियां होने वाली थी, 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने एक आर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उलटा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा

मैं उसको पलट दूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर तो इस देश की जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलायेगा? सारा देश स्तब्ध। मैं जहां भी जाउं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पलट देते हैं। सारा देश स्तब्ध था। उसके बाद अब ये बिल लेके आये आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिये बिल ले के आये। मैं सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। दो घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस दो घंटे में एक लाईन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा। दिल्ली की जनता का क्या फायदा, बार बार बस एक ही लाईन बोल रहे थे हमारे पास पावर है संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की। हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर, अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है तो डुबोओगे क्या इस देश को, लेके डूबोगे क्या इस देश को, मारोगे क्या लोगों को, तानाशाही करोगे क्या इस देश के उपर, कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर ये जो पावर, पावर, पावर का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है। बस एक ही लाईन बोलते हैं पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किसलिये दी है तुमको? पावर इसलिये दी है कि जनता का भला करो। पावर इसलिये दी है कि जनता के लिये काम

करो, पावर इसलिये दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिये दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिये काम करो। पावर इसलिये नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिये नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है इन लोगों को आर्डिनेंस क्यूं लाना पड़ा? इन लोगों को आर्डिनेंस इसलिये लाना पड़ा क्यूंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको दो तरीके इन्होंने अपनाये हैं, दो हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं। या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किये। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं, पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में तीन घोड़े हैं एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। मोदी जी ये तीन रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं इस रथ से इन्होंने अरूणाचल प्रदेश जीत लिया, अरूणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी,

कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुदुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उतराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की

सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इन्होंने आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गये थे बोले 25-25 करोड़ रूपये ले लो, हैं न? दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी नहीं बिका, 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके। कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी, सीबीआई भेजी सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं जो जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है।आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जायें, कल बेल हो जायेगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी, सीबीआई जो मर्जी कर लो पूरी जिन्दगी जेल में रख लो लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आयेंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रूक गया, न तो इनका कैश चला, न ही ईडी, सीबीआई चली। तो तब इनको ये आर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, पहले हमें असेम्बली के 3 चुनाव जिताये फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया। पिछले साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में जो अभी मैं बता रहा था। पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ थोडे ह़ी है, इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला

क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधावा पेंशन रोक दी, फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा न आ जाये कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं कहीं पूरा देश इनको न प्यार करने लग जाये। दिल्ली हो गयी, दिल्ली के बाद अब पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती। तो उनको यही डर लगता है। आठ साल में, आठ साल हो गये हमारी सरकार को अब आठ साल में दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है। पहले दिल्ली को लेके पूरे देश में क्या चर्चा होती थी कॉमन वेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला, पूरे देश में जब भी कोई दिल्ली वाला जाता था अच्छा तु दिल्ली से आया है वही सीएनजी घोटाला, कामन वेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाले से जाने जाते थे। अब दिल्ली वाला पूरे देश में कहीं भी जाता है लोग पूछते हैं अच्छा तुम्हारे बिजली के बिल जीरो आते हैं, अच्छा तुम्हारे स्कूल इतने अच्छे हो गये, अच्छा तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक कैसे हैं, अच्छा तुम्हारे यहां ईलाज, लोग दिल्ली के लोगों की पूरे देश में इज्जत बढ़ गयी, लोगों के बाहर से रिश्तेदार आते हैं, मेरे को बताते हैं लोग बाहर से रिश्तेदार आते हैं

कितने लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं आज मैं बाहर से आया, मैं टैक्सी में बैठा, मैंने टैक्सी ड्राईवर से पूछा, टैक्सी ड्राईवर खूब तारीफ कर रहा था स्कूलों की, आज मैं बाहर से आया, मैं ऑटो में बैठा, मैंने ऑटो ड्राईवर से पूछा वो खूब तारीफ कर रहा था दिल्ली के अस्पतालों की। इतनी इज्जत, दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है पिछले आठ साल के अंदर। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली पिछले आठ साल से प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिये, उसके बावजूद भी हमने स्कूल ठीक कर दिये, मोहल्ला क्लिनिक बना दिये, अस्पताल अच्छे कर दिये, अस्पतालों के अंदर ईलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं बुजुर्गों को, कच्ची कालोनियों के अंदर इतना बड़ा सड़क बना रहे हैं, पानी की पाईप लाईन लगा रहे हैं, सीवर का नेटवर्क लगा रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन आज सबसे ज्यादा पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है, सबसे कम महंगाई है ये मैं नहीं कह रहा केंद्र सरकार का आंकड़ा कह रहा है, सबसे कम महंगाई आज दिल्ली के अंदर है और जगह जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। इतने काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर सबसे ज्यादा काम करने का कोई नोबल प्राईज होता तो वो दिल्ली की जनता को 2 करोड़ लोगों को मिलता। मुझे कई बार लगता है कि भगवान की कृपा है दिल्ली

वालों के उपर कि इतनी सारी, इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही हैं लेकिन भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की कहीं से खोलता है हर जगह कभी न कभी कोई खिड़की खुल जाती है और दिल्ली वालों के काम हो जाते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। ये पिछले दो साल से सारी सीबीआई, ईडी लगी हुई है कह रहे हैं सौ करोड़ रूपये खा गये ये लोग सारे, अरे कहीं कोई एक पैसा तो मिले। सौ करोड़ हैं कहां? सौ करोड़ खा गये। हमारे पास अगर है तो हमारे पास आशीर्वाद है। आज दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य बना दिया, उनके मां बाप आसीस देते हैं हमको। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर करोड़ों लोग अपना फ्री में ईलाज कराते हैं जिसका भी फ्री में ईलाज होता है, ऑपरेशन होता है, बीमारी ठीक हो जाती है वो हमें आशीर्वाद दे के जाता है। आज दिल्ली के घर घर के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, जितने गरीब हैं वो तो हमें आशीर्वाद देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने अभी तीर्थयात्रा पे मैं एक ट्रेन को सी ऑफ करके गया था इतना आशीर्वाद दे रहे थे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा के लिये जा रहे थे। और जितने काम इन्होंने किये है वो सारे पाप किये हैं और उपर वाला देख रहा है। इन्होंने लोगों के अस्पताल रोके, इन्होंने लोगों की दवाइयां रोकी, इन्होंने लोगों का पानी रोका। तो पाप अगर करोगे तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा और इसी जन्म में

भुगतना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है ये जिंदगी भर यहीं बैठेंगे और अभी तो आठ हैं देखना अगली बार दो भी नहीं बचेंगे यहां पर। मोदी जी दिल्ली वालों को हराना चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं न दिल्ली वाले हारेंगे और न दिल्ली वालों का बेटा हारेगा। डट के मुकाबला करेंगे और मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं आपका एक भी काम मैं रूकने नहीं दूंगा। स्पीड थोड़ी कम हो जायेगी मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आयेगा, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आयेंगे, दिल्ली के लोगों के हक मैं वापस दिलाउंगा और उसके बाद सौ की बजाए दो सौ की, तीन सौ की स्पीड से काम होगा लेकिन तब तक काम रूकेंगे नहीं आपके। विदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। जनतंत्र की बात करेंगे, largest democracy की बात करेंगे, और यहां आके डेमोक्रेसी को कुचलने की और क्रश करने का। मैं ये सोच रहा था डेमोक्रेसी के कई सिस्टम होते हैं, कोई कहता है वेस्ट मिंस्टर मॉडल, कोई कहता है Presidential form of Democracy कोई कहता है Parliamentry form of Democracy अलग अलग मॉडल हैं। ये जो बिल लाये हैं इसमें तीन मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री होगा और दो अफसर उसके सर पे बैठे होंगे। ये कौन सा मॉडल है? भगवान ही जानता है ये कहां से लाये हैं आरएसएस वालों का सबसे खुराफाती दिमाग होता है।.. ये संघी मॉडल है। भगवान ही जातना है ये ऐसा मॉडल वेस्ट मिंस्टर मॉडल है कि लंदन का ये

संघी मॉडल है जो ये डेमोक्रेसी का एक अलग ही मॉडल ये निकाल के ले के आये हैं। चौथी पास मॉडल है ये। दिल्ली के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपने मुझे कुर्सी दी है मैं आपकी कभी भी पगड़ी उछलने नहीं दूंगा। आपका कभी भी सर नहीं झुकने दूंगा, दिल्ली के कभी कोई काम मैं रूकने नहीं दूंगा। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो और नहीं तो या तो तुम को झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। अभी लाल किले से भाषण दिया प्रधान मंत्री जी ने, वो कह रहे थे कि अब हम हजार साल आगे का एक वो नींव रख रहे हैं हजार साल, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने हजार साल की नींव रख रहे हैं तो हजार साल का अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे, और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के जरिये पूरा देश चलायेगा तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एक हजार साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल 140 करोड़ लोग मिल के इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। हमने आजादी केवल अंग्रेजों को भगाने के लिये नहीं पाई थी, इस देश के लोग सरकार चुनेंगे, आप उस अधिकार को छीन नहीं सकते,

आप जनतंत्र को कुचल नहीं सकते। केंद्र में भी सरकार लोग बनायेंगे, राज्य में भी सरकार लोग बनायेंगे, पंचायत में भी सरकार लोग बनायेंगे और म्यूनिसिपैलिटी में भी सरकार लोग बनायेंगे। आप अगर सोचो कि आप प्रधानमंत्री बनके और गर्वनरों के जरिये और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिये पूरा देश चलाओगे तो 140 करोड़ लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, हजार साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल नहीं चलने वाला। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सातों सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के मुद्दे के उपर ये वाला चुनाव होने वाला है।

अध्यक्ष महोदया: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सदन को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने से पहले मैं सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिये विधान सभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों, सुरक्षा एजेंसी तथा मीडिया का भी मैं धन्यवाद करती हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे राष्ट्रगान के लिये खड़े हो जाएं।

राष्ट्रगान

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की गई)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।